चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 13 जून- 19 जून 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

जजों की नियुक्ति के लिए बनी सूची में न्यायाधीशों के बेटों और रिश्तेदारों की भरमार

पैरवी में है दम जज बनेंगे हम

प्रभात रंजन दीन

जजों की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी गई है, वह धांधलियों का पुलिंदा है. जज अपने बेटों और नाते रिश्तेदारों को जज बना रहे हैं और सरकार को उपकृत करने के लिए सत्ता के चहेते सरकारी वकीलों को भी जज बनाने की संस्तुति कर रहे हैं. न्यायाधीश का पद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के प्रभावशाली जजों का खानदानी आसन बनता जा रहा है. जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अद्यतन सूची में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेटे से लेकर कई प्रमुख न्यायाधीशों के बेटे और रिश्तेदार शामिल हैं. नेताओं को भी खूब उपकृत किया जा रहा है. वरिष्ठ कानूनविद्, उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे वीएन खरे के बेटे सोमेश खरे, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सगीर अहमद के बेटे मोहम्मद अल्ताफ मंसूर समेत ऐसे दर्जनों नाम हैं, जिन्हें जज बनाने के लिए सिफारिश की गई है. जजों की नियुक्ति के लिए की गई संस्तुति की जो सूची सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें 73 नाम जजों के रिश्तेदारों के हैं और 24 नाम नेताओं के रिश्तेदारों के हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के पूर्व जो तकरीबन 50 नाम जजों की नियुक्ति के लिए भेजे उनमें भी अधिकांश लोग जजों के बेटे और रिश्तेदार हैं या सरकार के पैरवी-पुत्र सरकारी वकील हैं. अब जज बनने के लिए योग्यता ही हो गई है कि अभ्यर्थी जज या नेता का रिश्तेदार हो या सत्ता की नाक में घुसा हुआ सरकारी वकील. अन्य योग्य वकीलों ने तो जज बनने का सपना देखना भी बंद कर दिया है.

जब न्यायाधीश ही अपने नाते-रिश्तेदारों और सरकार के प्रतिनिधि-पुत्रों को जज नियुक्त करे तो संविधान का संरक्षण कैसे हो? यह कठोर तथ्य है जो सवाल बन कर संविधान पर चिपका हुआ है. यह पूरे देश में हो रहा है. जजों की नियुक्ति के लिए विभिन्न हाईकोर्टों से जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी जा रही हैं, उनमें अधिकांश लोग प्रभावशाली जजों के रिश्तेदार या सरकार के चहेते सरकारी अधिवक्ता हैं. वरिष्ठ वकीलों को जज बनाने के नाम पर न्यायपीठों में यह गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी कृत्य निर्बाध गति से चल रहा है, इसके खिलाफ सार्वजनिक मंच पर बोलने वाला कोई नहीं. सार्वजनिक मंच पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर जजों की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रो सकते हैं, लेकिन जजों की नियुक्तियों में जो धांधली मचा कर रखी गई है, उसके खिलाफ कोई नागरिक सार्वजनिक मंच पर रो भी नहीं सकता. इस रुदन और उस रुदन के मर्म अलग-अलग हैं. रिश्तेदारों और सरकारी वकीलों को जज बना कर आम आदमी के संवैधानिक अधिकार को कैसे संरक्षित-सुरक्षित रखा जा सकता है और ऐसे जज किसी आम आदमी को कैसा न्याय देते होंगे, लोग इसे समझ भी रहे हैं और भोग भी रहे हैं. देश की न्यायिक व्यवस्था की यही सड़ी हुई असलियत है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों की नियुक्ति के लिए जिन नामों की सिफारिश कर फाइनल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट भेजी, उनमें से अधिकांश नाम मौजूदा जजों या प्रभावशाली रिटायर्ड जजों के बेटे, भांजे, साले, भतीजे या नाते रिश्तेदारों के हैं. बाकी लोग सत्ता सामर्थ्यवान सरकारी वकील हैं. चंद्रचूड़ यह लिस्ट भेज कर खुद भी सुप्रीम कोर्ट के जज होकर चले गए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के समक्ष यह सवाल छोड़ गए कि क्या जजों की कुर्सियां न्यायाधीशों के नाते-रिश्तेदारों और सत्ता-संरक्षित सरकारी वकीलों के लिए आरक्षित हैं? क्या उन अधिवक्ताओं को जज बनने का पारंपरिक अधिकार नहीं रहा जो कर्मठता से वकालत करते हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इलाहाबाद और लखनऊ पीठ के जिन वकीलों के नाम जज की नियुक्ति के लिए भेजे गए हैं उनमें मोहम्मद अल्ताफ मंसूर, संगीता चंद्रा, रजनीश कुमार, अब्दुल मोईन, उपेंद्र मिश्र, शिशिर जैन, मनीष मेहरोत्रा, आरएन तिलहरी, सीडी सिंह, सोमेश खरे, राजीव मिश्र, अजय भनोट, अशोक गुप्ता, राजीव गुप्ता, बीके सिंह जैसे लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं. ये कुछ नाम उदाहरण के तौर पर हैं. फेहरिस्त लंबी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से तकरीबन 50 वकीलों के नाम सुप्रीम कोर्ट भेजे गए हैं, जिन्हें जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है. इसमें 35 नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के और करीब 15 नाम हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के हैं. जो नाम भेजे गए हैं उनमें से अधिकांश लोग विभिन्न जजों के रिश्तेदार और सरकारी पदों पर विराजमान वकील हैं. इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक भी वकील शामिल नहीं है. ऐसे में,खबर के साथ-साथ यह भी जानते चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्माण से अब तक के 65 साल में एक भी अनुसूचित जाति का वकील जज नहीं बना. इसी तरह वैश्य, यादव या मौर्य जाति का भी कोई वकील कम से कम लखनऊ पीठ में आज तक जज नियुक्त नहीं हुआ. बहरहाल, ताजा लिस्ट के मुताबिक जो लोग जज बनने जा रहे हैं, उनके विभिन्न जजों से रिश्ते और सरकारी पदों के सत्ता-छत्र का तफसील भी देखते चलिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे सगीर अहमद के बेटे मोहम्मद अल्ताफ मंसूर को जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है. अल्ताफ मंसूर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता (चीफ स्टैंडिंग काउंसिल) भी हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे अब्दुल मतीन के सगे भाई अब्दुल मोईन को भी जज बनने योग्य पाया गया है. अब्दुल मोईन उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे ओपी श्रीवास्तव के बेटे रजनीश कुमार का नाम भी जज बनने वालों की सूची में शामिल है. रजनीश कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहे टीएस मिश्रा और केएन मिश्रा के भतीजे उपेंद्र मिश्रा को भी जज बनाने की सिफारिश की गई है. उपेंद्र मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सरकारी वकील हैं. पहले भी वे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रह चुके हैं. उपेंद्र मिश्र की एक योग्यता यह भी है कि वे बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा के भाई हैं. इसी तरह हाईकोर्ट के जज रहे एचएन तिलहरी के बेटे आरएन तिलहरी और जस्टिस एसपी मेहरोत्रा के बेटे मनीष मेहरोत्रा को भी जज बनने लायक पाया गया है. इनके भी नाम लिस्ट में शामिल हैं. लखनऊ बेंच से जिन लोगों के नाम जज के लिए चुने गए, उनमें चीफ स्टैंडिंग काउंसिल (2) श्रीमती संगीता चंद्रा और राजकीय निर्माण निगम व सेतु निगम के सरकारी वकील शिशिर जैन के नाम भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे वीएन खरे के बेटे सोमेश खरे का नाम भी जज के लिए भेजा गया है. इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्वनामधन्य जज रहे जगदीश भल्ला के भांजे अजय भनोट और न्यायाधीश रामप्रकाश मिश्र के बेटे राजीव मिश्र का नाम भी जजों के लिए अग्रसारित सूची में शामिल है. अंधेरगर्दी की स्थिति यह है कि हाईकोर्ट के जज रहे पीएस गुप्ता के बेटे अशोक गुप्ता और भांजे राजीव गुप्ता दोनों में ही जज बनने लायक योग्यता देखी गई और दोनों के नाम सुप्रीम कोर्ट भेज दिए गए. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सिटिंग जज एपी शाही के साले बीके सिंह का नाम भी अनुशंसित सूची में शामिल है. सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सीडी सिंह का नाम भी जजों के लिए चयनित सूची में शामिल है.

यह मामला अत्यंत गंभीर इसलिए भी है कि जजों की नियुक्ति की यह लिस्ट खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तैयार की और अपनी संस्तुति के साथ सुप्रीम कोर्ट भेजी. चंद्रचूड़ अब खुद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं. उन्हें न्याय के साथ न्याय करने के लिए ही तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया होगा. जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई संस्तुति ने उनकी न्यायिकता और उन्हें तरक्की देने के मापदंड की न्यायिकता दोनों को संदेह में डाला है. डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं. वकीलों का यह सवाल वाजिब है कि क्या जजों की नियुक्ति के लिए किसी ताकतवर जज का रिश्तेदार होना या एडिशनल एडवोकेट जनरल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल या गवर्नमेंट एडवोकेट होना अनिवार्य योग्यता है? क्या सरकारी वकीलों (स्टेट लॉ अफसर) को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत वकील माना जा सकता है? संविधान के ये दोनों अनुच्छेद कहते हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए किसी वकील का हाईकोर्ट या कम से कम दो अदालतों में सक्रिय प्रैक्टिस का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है. क्या इसकी प्रासंगिकता रह गई है? भेजी गई लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कभी भी किसी आम नागरिक का मुकदमा नहीं लड़ा. काला कोट पहना और पहुंच के बूते सरकारी वकील हो गए, सरकार की नुमाइंदगी करते रहे और जज के लिए अपना नाम रिकमेंड करा लिया.

वर्ष 2000 में भी 13 जजों की नियुक्ति में धांधली का मामला उठा था, जिसमें आठ नाम विभिन्न जजों के रिश्तेदारों के थे. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में कानून मंत्री रहे राम जेठमलानी ने जजों की नियुक्ति के लिए देशभर के हाईकोर्ट से भेजी गई लिस्ट की जांच का आदेश दिया. जांच में पाया गया कि 159 सिफारिशों में से करीब 90 सिफारिशें विभिन्न जजों के बेटों या रिश्तेदारों के लिए की गई थीं. जांच के बाद अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कानून मंत्रालय ने वह सूची खारिज कर दी थी. जजों की नियुक्ति में जजों द्वारा ही धांधली किए जाने का मामला बाद में जनेश्वर मिश्र ने राज्यसभा में भी उठाया. इसके जवाब में तब कानून मंत्री का पद संभाल चुके अरुण जेटली ने सदन को आधिकारिक तौर पर बताया था कि औपचारिक जांच पड़ताल के बाद लिस्ट खारिज कर दी गई. उस खारिज लिस्ट में शुमार कई लोग बाद में जज बन गए और अब वे अपने रिश्तेदारों को जज बनाने में लगे हैं. इनमें जस्टिस अब्दुल मतीन और जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा जैसे नाम उल्लेखनीय हैं. इम्तियाज मुर्तजा के पिता मुर्तजा हुसैन भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे. अब्दुल मतीन के सगे भाई अब्दुल मोईन को जज बनाने के लिए संस्तुति सूची में शामिल कर लिया गया है.

इस प्रकरण की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जजों की नियुक्ति में धांधली और भाई-भतीजावाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक पांडेय द्वारा दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी गई थी और अशोक पांडेय पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था. जबकि अशोक पांडेय द्वारा अदालत को दी गई लिस्ट के आधार पर ही केंद्रीय कानून मंत्रालय ने देशभर से आई ऐसी सिफारिशों की जांच कराई थी और जांच में धांधली की आधिकारिक पुष्टि होने पर जजों की नियुक्तियां खारिज कर दी थीं. अशोक पांडेय ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए भेजी गई मौजूदा लिस्ट में बरती गई अनियमितताओं के खिलाफ उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की और फिर हाईकोर्ट ने उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई. अदालत ने एडवांस कॉस्ट के नाम पर 25 हजार रुपए जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके (शेष पृष्ठ 2 पर)

सुप्रीम कोर्ट भेजी गई लिस्ट में सरकारी वकीलों और नेता पुत्रों के भी नाम

जजों के चयन में योग्यता और वकालत के अनुभव का मापदंड पूरी तरह दरकिनार

बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे का नाम भी जजों की लिस्ट में

पैरवी में है दम

जज बनेंगे हम

पृष्ठ 1 का शेष

बाद ही मामले पर सुनवाई की जाएगी. पांडेय चिंता जताते हैं कि संविधान और कानून से जुड़े इतने संवेदनशील मामले को 25 हजार रुपए के लिए अदालत ने लंबित रख दिया है. धांधली की यह सूची प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को भेजने के बारे में अशोक पांडेय विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा भेजी गई सूची पर ही तत्कालीन कानून मंत्रालय ने वर्ष 2000 में कार्रवाई की थी. ■

जजों की नियुक्ति में हो रहे भाई-भतीजावाद और धांधलियों के खिलाफ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के समक्ष पूरा तथ्य पेश करूंगा ताकि जांच हो सके और समुचित कार्रवाई हो. यह संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है. वर्ष 2000 में भी मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कानून मंत्री राम जेठमलानी को पूरी सूची सौंपी थी, जिस पर जांच हुई और लिस्ट रद्द कर दी गई थी. मुझे उम्मीद है कि वर्तमान प्रधानमंत्री और कानून मंत्री भी इस मामले में समुचित कार्रवाई करेंगे और जजों की नियुक्ति को संविधान-सम्मत और पारदर्शी बनाएंगे.

- अशोक पांडेय

वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट

न्याय व्यवस्था को सत्ता-प्रभाव में लाने का चल रहा षडयंत्र

सरकारी वकीलों को जज बना कर पूरी न्यायिक व्यवस्था को शासनोन्मुखी करने का षडयंत्र चल रहा है. सीधे तौर पर नागरिकों से जुड़े वकीलों को जज बनाने की परंपरा बड़े ही शातिराना तरीके से नष्ट की जा रही है. कुछ ही अर्सा पहले अधिवक्ता कोटे से जो 10 वकील जज बनाए गए थे, उनमें से भी सात लोग राजीव शर्मा, एसएस चौहान, एसएन शुक्ला, शबीहुल हसनैन, अश्वनी कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार अरोड़ा और देवेंद्र कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार के वकील (स्टेट लॉ अफसर) थे. इनके अलावा रितुराज अवस्थी और अनिल कुमार केंद्र सरकार के लॉ अफसर थे.

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता देने में भी भीषण अनियमितता हो रही है. नागरिकों के मुकदमे लड़ने वाले वकीलों को लंबा अनुभव हो जाने के बावजूद उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता नहीं दी जाती, जबकि सरकारी वकीलों को बड़ी आसानी से वरिष्ठ वकील की मान्यता मिल जाती है. कुछ ही अर्सा पहले लखनऊ बेंच के चार वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में मान्यता दी गई, जिनमें चीफ स्टैंडिंग काउंसिल आईपी सिंह, एडिशनल एडवोकेट जनरल बुलबुल घोल्डियाल, केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल असित कुमार चतुर्वेदी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के वकील शशि प्रताप सिंह शामिल हैं. लखनऊ में अनुभवी और विद्वान वकीलों की अच्छी खासी तादाद के बावजूद हाईकोर्ट को उनमें कोई वरिष्ठ अधिवक्ता बनने लायक नहीं दिखता. ऐसे रवैये के कारण वकीलों में आम लोगों के मुकदमे छोड़ कर सरकारी वकील बनने की होड़ लगी हुई है. सब इसके जुगाड़ में लगे हैं और इससे न्याय की मूलभूत अवधारणा बुरी तरह खंडित हो रही है. ■

जजी भी अपनी, धंधा भी अपना...

जजों के रिश्तेदार जज बन रहे हैं और जजों के रिश्तेदार उन्हीं के बूते अपनी वकालत का धंधा भी चमका रहे हैं. न्याय परिसर में दोनों तरफ से जजों के रिश्तेदारों का ही आधिपत्य कायम होता जा रहा है. जजों के बेटे और रिश्तेदारों की आलीशान वकालत का धंधा जजों की नियुक्ति वाली लिस्ट की तरह कोई चोरी-छिपी बात नहीं रही. यह बिल्कुल सार्वजनिक मामला है. आम लोग भी जजों के रिश्तेदार वकीलों के पास ही जाते हैं, जिन्हें फीस देने से न्याय मिलने की गारंटी हो जाती है. जजों के रिश्तेदारों की उन्हीं के कोर्ट में वकालत करने की खबरें कई बार सुर्खियां बन चुकी हैं. हाईकोर्ट की दोनों पीठों के दर्जनों नामी-गिरामी जजों के बेटे और रिश्तेदार वहीं पर अपनी वकालत का धंधा चमकाते रहे हैं. इनमें जस्टिस अब्दुल मतीन के भाई अब्दुल मोईन, जस्टिस अभिनव उपाध्याय के बेटे रीतेश उपाध्याय, जस्टिस अनिल कुमार के पिता आरपी श्रीवास्तव, भाई अखिल श्रीवास्तव और बेटे अंकित श्रीवास्तव, जस्टिस बालकृष्ण नारायण के पिता ध्रुव नारायण और बेटा ए. नारायण, जस्टिस देवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विशेष सिंह, जस्टिस देवी प्रसाद सिंह के बेटे रवि सिंह, जस्टिस दिलीप गुप्ता की साली सुनीता अग्रवाल, जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा के भाई रिशाद मुर्तजा और नदीम, जस्टिस कृष्ण मुरारी के साले उदय करण सक्सेना और चाचा जीएन वर्मा, जस्टिस प्रकाश कृष्ण के बेटे आशीष अग्रवाल, जस्टिस प्रकाशचंद्र वर्मा के बेटे ज्योतिर्जय वर्मा, जस्टिस राजमणि चौहान के बेटे सौरभ चौहान, जस्टिस राकेश शर्मा के बेटे शिवम शर्मा, जस्टिस रवींद्र सिंह के भाई अखिलेश सिंह, जस्टिस संजय मिश्र के भाई अखिलेश मिश्र, जस्टिस सत्यपूत मेहरोत्रा के बेटे निषांत मेहरोत्रा और भाई अनिल मेहरोत्रा, जस्टिस शशिकांत गुप्ता के बेटे रोहन गुप्ता, जस्टिस शिवकुमार सिंह के बेटे महेश नारायण और भाई बीके सिंह, जस्टिस श्रीकांत त्रिपाठी के बेटे प्रवीण त्रिपाठी, जस्टिस सत्येंद्र सिंह चौहान के बेटे राजीव चौहान, जस्टिस सुनील अम्बवानी की बिटिया मनीषा, जस्टिस सुरेंद्र सिंह के बेटे उमंग सिंह, जस्टिस वेद पाल के बेटे विवेक और अजय, जस्टिस विमलेश कुमार शुक्ला के भाई कमलेश शुक्ला, जस्टिस विनीत शरण के पिता एवी शरण और बेटे कार्तिक शरण, जस्टिस राकेश तिवारी के साले विनीत मिश्रा, जस्टिस वीरेंद्र कुमार दीक्षित के बेटे मनु दीक्षित, जस्टिस यतींद्र सिंह के पिता विकास चौधरी, भतीजा कुणाल और बहू मंजरी सिंह, जस्टिस सभाजीत यादव के बेटे पीपी यादव, जस्टिस अशोक कुमार रूपनवाल की बिटिया तनु, जस्टिस अमर शरण के भतीजे सिकंदर कोचर, जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही के ससुर आरएन सिंह और साले गोविंद शरण, जस्टिस अशोक भूषण के भाई अनिल और बेटे आदर्श व जस्टिस राजेश कुमार अग्रवाल के भाई भरत अग्रवाल अपनी वकालत का धंधा अपने रिश्तेदार जजों के बूते ही चमकाते रहे हैं. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 15
13 जून- 19 जून 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एच-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

प्रशंसा पड़ी भारी

मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अजय सिंह गंगवार राज्य सरकार के गुस्से के तब शिकार हो गए जब उन्होंने हाल में अपने एक फेसबुक पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा की. हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा दिया गया था. लेकिन नुकसान तो हो ही गया. शिकायत मिलने पर राज्य के मुख्य सचिव एंथनी जेसी डी सा ने बड़वानी जिले के कलेक्टर गंगवार को वहां से हटा कर उप सचिव के रूप में भोपाल स्थित राज्य सचिवालय स्थानांतरित कर दिया. गंगवार पर सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. व्यक्तिगत राय की अभिव्यक्ति, जिसका दावा गंगवार कर रहे हैं, को लेकर जो प्रतिक्रिया आई है वह उसी तरह की है, जब मध्य प्रदेश के एक बाबू की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वे एक सरकारी अस्पताल में एक बेड पर अपना पैर टिकाए हुए थे. उन्हें इसके लिए निलंबित कर दिया गया था. वर्तमान मामले में, गंगवार की समस्या यह है कि नेहरू वास्तव में भाजपा सरकार के, केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर, पसंदीदा नहीं हैं. प्रयास यह हो रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में नेहरूवादी विरासत को समाप्त किया जाए. जाहिर है, उस राज्य में नेहरू की प्रशंसा करना तो ठीक नहीं ही है, जहां सरकार चलाने वाले के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री एक अभिशाप हैं. ■

जूनियर बाबू, सीनियर पोस्ट

पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने संकेत दिया था कि राज्य के नए मुख्य सचिव सीनियर अधिकारियों के बजाए एक जूनियर अधिकारी हो सकता है. अधिकतर बाबुओं ने मान लिया था कि मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिया, उसके मुताबिक उनकी पसंद वीसी फारका, सीनियर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वीरभद्र सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं. अब यह संकेत सच हो गया है. फारका अब पी मित्रा की जगह राज्य के नए मुख्य सचिव हैं. इस प्रक्रिया में 1983 बैच के आईएएस अधिकारी फारका ने 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों दीपक सनन, अजय मित्तल, विनीत चौधरी (सभी 1982 बैच के), उपमा चौधरी, भारती एस सिहाग और आशाराम सिहाग को पीछे छोड़ दिया. वीरभद्र सिंह ने सार्वजनिक रूप से अपने पसंद के संकेत नहीं दिए थे, तब बाबूशाही पर नजर रखने वालों की उम्मीद थी कि अजय मित्तल, मित्रा की जगह आएंगे. लेकिन, फारका डार्क हॉर्स बन कर उभरे. ■

बस्सी को मिली नई नौकरी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) है, जो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है, के सदस्य के रूप में दिल्ली के पूर्व पुलिस प्रमुख बीएस बस्सी की नियुक्ति ने बस्सी की सेवानिवृत्ति के बाद की योजनाओं के बारे में उड़ने वाली अफवाहों पर विराम लगा दिया है. फरवरी में उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, चर्चा थी कि वे मुख्य सूचना आयुक्त बनने की दौड़ में हैं. लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में राजद्रोह मामले को ठीक से न निपटाने के बाद कांग्रेस ने मजबूती से उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया और केंद्र ने उनका नाम हटा दिया. बाद में, बस्सी का नाम उत्तराखंड के राज्यपाल के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में सामने आया. लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ. बस्सी का ये कार्यकाल पांच साल के लिए है. वे 65 साल तक या 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे, जो भी पहले पूरा हो जाए. आमतौर पर यूपीएससी के सदस्यों को छह साल के लिए नियुक्त किया जाता है. दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में, आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा उनकी तनातनी रही. केजरीवाल ने उन पर केंद्र सरकार की कठपुतली होने का आरोप लगाया. अब यूपीएससी में बस्सी का कार्यकाल अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण होना चाहिए. ■

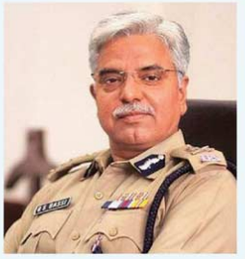

किसानों की आंख में आंसू ला रहा प्याज

विदर्भ बनने की राह पर नासिक

सर्वविदित तथ्य है कि प्याज एक मौसमी फसल है, जिसका इस्तेमाल साल भर होता है और बिना इसे स्टोर किए यह संभव ही नहीं है. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार कभी भी किसी उत्पादक को किसी भी मूल्य पर आपूर्ति के लिए कह सकती है. ऐसे में, पहले से ही घाटा उठा रहे किसानों को क्या फायदा होगा?

शशि शेखर

नासिक के लासलगांव स्थित देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में आजकल प्याज और किसान अपनी किस्मत पर रोते दिख रहे हैं. दूसरों को रुलाने वाला प्याज इसलिए रो रहा है कि उसे खरीदार नहीं मिल रहे, तो वहीं किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं. किसानों की भी अजीब विडंबना है. कभी उत्पादन न होने से मारे जाते हैं तो कभी उत्पादन ज्यादा होने से. लेकिन सवाल यह है कि ऐसा किसानों के साथ ही क्यों होता है? क्या आपने कभी सुना है कि दूध का उत्पादन बढ़ जाने से उसकी कीमत घट जाती हो, या शराब का उत्पादन बढ़ जाने से उसे कंपनियां मुफ्त में बांटने लग जाएं या सड़क पर फेंकने लगें. ऐसा सोच पाना भी मुश्किल है. लेकिन, गेहूं का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो मूल्य घट जाता है, सरकारी गोदामों में पड़े-पड़े गेहूं सड़ने लगता है. प्याज का उत्पादन बढ़ जाए तो किसानों को अपना उत्पाद फेंकने पर मजबूर होना पड़ता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि एक तरफ तो उत्पादन बढ़ा है, दूसरी तरफ निर्यात पर सीमित अंकुश होने और विदेशों से मांग में कमी होने की वजह से महाराष्ट्र के किसानों को प्याज पर अपनी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है. खबरों के मुताबिक, नासिक में किसान प्याज से भरा ट्रक मंडियों में छोड़ रहे हैं, क्योंकि व्यापारी उनके प्याज की कीमत दो-तीन रुपये प्रति किलो दे रहे हैं. ज्यादा से ज्यादा दस रुपये किलो, जबकि किसानों की लागत ही प्रति किलो 15 रुपये से अधिक है. गौरतलब है कि पिछले साल यही प्याज 63 रुपये प्रति किलो बिका था और इस बार अधिकतम दस रुपये.

नासिक जिला अकेले पूरे देश का करीब दस फीसदी प्याज उगाता है. यहीं का लासलगांव देश का सबसे बड़ा प्याज का मंडी है. इस इलाके के आसपास के क्षेत्र में पिछले 15 महीनों के दौरान करीब 26 किसान आत्महत्या कर चुके हैं. एक समय इस मंडी से देश-विदेश जाने के लिए तैयार ट्रक प्याज से भरे होते थे, आज हालत यह है कि रोजाना यहां अधिकतम 15 हजार क्विंटल प्याज ही बिकने के लिए आ रहा है, जबकि पहले यह मात्रा 30 हजार क्विंटल से भी अधिक होती थी. कभी इस मंडी में 60 रुपये किलो बिकने वाला प्याज आज सौ से सात सौ रुपए क्विंटल भी बमुश्किल बिक पा रहा है. औसतन, एक किसान को आज अपने उत्पादन लागत का दस से पांच गुना कम पैसा मिल रहा है. जाहिर है, इस हालात ने नासिक क्षेत्र के किसानों के हौसले को तोड़ कर रख दिया है. एक तो प्याज बिक नहीं रहा, दूसरी तरफ मानसून सिर पर दस्तक दे रहा है. बारिश में अगर प्याज सड़ता है, तो यह किसानों के लिए एक सदमा होगा. ऐसी स्थिति में बैंक और साहूकारों के कर्ज में फंसे प्याज उत्पादक किसान आत्महत्या भी कर सकते हैं.

गौरतलब है कि पिछले एक साल के दौरान नासिक जिले में ही 35 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं. लेकिन, इनके बारे में खबर लिखने या दिखाने की फुर्सत राष्ट्रीय मीडिया को नहीं है. न ही यह खबरें महाराष्ट्र से बाहर आ रही हैं. सवाल है कि तीन साल से सूखे के बाद जब किसानों ने गन्ना की जगह प्याज की खेती शुरू की तो रिकॉर्डतोड़ उत्पादन ने अब फिर से उनकी कमर तोड़ दी है. जाहिर है, अगले साल किसान प्याज की खेती करने से पहले सौ बार सोचेंगे. नतीजतन, अगले साल प्याज का उत्पादन कम हो सकता है, जिससे एक बार फिर प्याज किसानों की बजाय उपभोक्ताओं की आंखों में आंसू लाएगा. किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह हाल ही में नासिक और लासलगांव क्षेत्र का दौरा कर लौटे हैं. उन्होंने चौथी दुनिया को बताया कि पूरे इलाके के प्याज उत्पादक किसानों की हालत दयनीय है. वह बताते हैं कि 2014 तक 18 हजार टन प्याज का निर्यात हुआ जिससे किसानों को राहत मिली थी, लेकिन पिछले दो साल से प्याज के निर्यात पर आंशिक अंकुश होने से किसानों की हालत खराब हो रही है. वह कहते हैं कि मौजूदा सरकार द्वारा तत्काल कोई निर्णय नहीं लिए जाने से किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है. किसानों को अपना प्याज सौ रुपये क्विंटल तक बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है. हमें याद रखना चाहिए कि 50 फीसदी से अधिक प्याज इसी इलाके से आता है और अगर यहां के किसानों ने प्याज बोना छोड़ दिया तो क्या होगा? विनोद सिंह इस मामले में बिचौलियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हैं. किसान मंच के स्थानीय नेता धनंजय धोर्डे बताते हैं कि किसानों ने ब्याज पर कर्ज लेकर और गहने गिरवी रखकर प्याज की खेती की थी. अब एक्सपोर्ट बंद है, दाम मिल नहीं रहा, किसान भला करे तो क्या? प्रति हेक्टेयर 25 से 30 हजार का नुकसान हो रहा है. राज्य और केंद्र सरकार हमारी कोई बात सुन नहीं रही है. हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और भला क्या चारा बचा है?

प्याज की खेती का सच और भ्रम को लेकर एपीएमसी लासलगांव एपीएमसी के चेयरमैन नाना साहेब पाटील ने एक रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट कई ऐसे तथ्यों का खुलासा करती है जो बताती है कि प्याज उत्पादक किसानों की हालत क्या है और सरकार के लिए क्यों जरूरी है कि इस दिशा में एक ठोस नीति और योजना बनाए ताकि हर साल प्याज को लेकर होने वाले बवाल पर लगाम लग सके. यह रिपोर्ट बताती है कि जब 2014 में खुद सरकार ने यह घोषणा की कि ओलावृष्टि की वजह से 30 फीसदी प्याज बर्बाद हुआ, तब क्यों नहीं इसके मूल्य इस बार तय किए गए. इसके अलावा, प्याज को सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी में तो शामिल कर लिया, लेकिन इसका एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय नहीं किया. फिर, जो प्याज स्टोर किए जाते हैं, वह भी आद्रता और बारिश की वजह से बर्बाद होते हैं. यह बर्बादी हर साल करीब 30 से 35 फीसदी होती है. मार्केट प्राइस तय करते वक्त इन कारकों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है. दूसरी बात यह कि बिना एमएएसपी घोषित किए प्याज को एसेंशियल कमोडिटी में शामिल किए जाने से भी प्याज उत्पादक किसानों पर नकारात्मक प्रभाव हुआ. एसेंशियल कमोडिटी के तहत किसी उत्पाद को स्टोर नहीं किया जा सकता है. जबकि, सर्वविदित तथ्य है कि प्याज एक मौसमी फसल है, जिसका इस्तेमाल साल भर होता है और बिना इसे स्टोर किए यह संभव ही नहीं है. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत सरकार कभी भी किसी उत्पादक को किसी भी मूल्य पर आपूर्ति के लिए कह सकती है. ऐसे में, पहले से ही घाटा उठा रहे किसानों को क्या फायदा होगा? ■

प्रधानमंत्री चुनाव से पहले किसानों को लागत मूल्य पर 50 फीसदी अतिरिक्त लाभ देने की बात कर रहे थे, आज कहां गया वो 50 फीसदी अतिरिक्त लाभ. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों का क्या हुआ? आज, अगर इन प्याज किसानों की मदद नहीं की गई तो महाराष्ट्र में एक और नया विदर्भ बनेगा. जाहिर है, इस सरकार में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है.

-विनोद सिंह, *राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मंच.*

हमारे किसानों की लागत ज्यादा हो गई है. खाद के दाम 300 प्रतिशत बढ़ गए हैं. इसके बाद भी, खरीफ और रबी, दोनों फसलों के दौरान प्याज की लागत मूल्य तक नहीं मिल सका है. किसान लगातार लागत मूल्य से नीचे प्याज बेचने को मजबूर हैं. एक्सपोर्ट कम हो गया है. प्याज का कोई एमएसपी नहीं है. अनुदान की राशि मिलनी चाहिए, जो अभी तक मिली नहीं है.

-नाना साहेब पाटील, *चेयरमैन, एपीएमसी, लासलगांव.*

फिर भी कहते हैं, उत्पादन बढ़ाओ

2015-16 में प्याज का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करीब 17 टन हुआ. एक और हिसाब देखिए. चीन हमारे मुकाबले प्रति एकड़ 22 टन और तुर्की 30 टन उपजा रहा है. यानी, हम अब भी चीन और तुर्की के मुकाबले बहुत कम प्याज का उत्पादन कर रहे हैं. यहां प्रति एकड़ 17 टन उत्पादन करने के बाद भी किसानों के हाथ खाली हैं. सरकार इतने उत्पादन को भी संभालने में असफल रही. किसानों की हालत क्या हो गई, हम सब देख रहे हैं. एक तरफ सरकार कहती है, ज्यादा उत्पादन करो, जब किसान ज्यादा उत्पादन करता है तो वह अपनी लागत तक वसूली नहीं कर पाता. अगर उत्पादन कम हो तो उपभोक्ता महंगे उत्पाद से परेशान. उत्पादन अधिक हो तो बेचारा किसान परेशान. इस मर्ज का इलाज क्या है? 2013 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 44 हजार करोड़ रुपये के फल और सब्जियां उचित भंडारण के अभाव में सड़ गईं. यह जानकारी लोकसभा में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने दी थी. 2015 तक यह नुकसान 52 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 2012 में एक रिपोर्ट आई थी. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 290 लाख टन कृषि उत्पादों के भंडारण की सुविधा है, जबकि उत्पादन 610 लाख टन है. सवाल है कि जब हम अपने अन्न के भंडारण में भी अक्षम हैं तो फिर किस मुंह से हर बार कम उपज के लिए सूखा या अतिवृष्टि को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं. आज, जब प्याज हमारे पास अधिक है तो क्यों नहीं उसे सहेजने के लिए हमारे पास नीति, नीयत और सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इस देश का किसान शायद धरती का सबसे निरीह प्राणी है, जिसके सिर अपनी हर गलती का ठीकरा फोड़ सरकारें पाक-साफ बनी रहती हैं. ■

देश में प्याज का कुल उत्पादन

2015-16	-	203.15 लाख एमटी
2014-15	-	189.27 लाख एमटी
2013-14	-	194.02 लाख एमटी

(नोट: पूरे देश में जरूरत है करीब 144 लाख एमटी)

प्याज की क़ीमत (27 मई तक)

- मुंबई - 15 से 30 रुपये प्रति किलो
- पुणे- 20 से 30 रुपये प्रति किलो
- नागपुर - 15 से 25 रुपये प्रति किलो
- गोवा- 16 से 20 रुपये प्रति किलो

लासलगांव मंडी में प्याज का भाव

- औसतन थोक मूल्य 750 रुपये प्रति क्विंटल
- उच्चतम थोक मूल्य 980 रुपये प्रति क्विंटल
- न्यूनतम थोक मूल्य 100 रुपये प्रति क्विंटल

feedback@chauthiduniya.com

सिंहस्थ के बाद

मध्यप्रदेश भाजपा में अब आएगा तूफान

सोरिन शर्मा

सिंहस्थ को लेकर एक कहावत चर्चित है, इसके आयोजन के दौरान जो भी सत्ता में रहता है, सिंहस्थ के बाद उसकी कुर्सी चली जाती है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं तो ऐसी कई मान्यताओं को झुठला चुके हैं, लेकिन प्रदेश में बन रहे राजनीतिक हालात कुछ और संकेत कर रहे हैं. संघ के तेवर को देखकर दावा किया जा रहा है कि सिंहस्थ के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आएगा. प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में पार्टी के शक्तिशाली पदाधिकारी अरविंद मेनन की छुट्टी से संकेत मिले हैं कि संघ और भाजपा हाईकमान कुछ और कठोर निर्णय ले सकता है.

फिलहाल प्रदेश में तूफान से आने के पहले की शांति है, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी. उज्जैन सिंहस्थ में सब ठीक नहीं चल रहा था, केवल सब कुछ ठीक होने का भ्रम रचा जा रहा था. अचानक एक दिन आए आंधी-तूफान ने सात लोगों की बलि ले ली. मेले में भारी उथल-पुथल मचा दी. प्रकृति का प्रकोप ऐसा ही होता है, क्योंकि हम भी तो लगातार प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहते हैं.

सिंहस्थ में जो कुछ हुआ, माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश की राजनीति में भी बहुत जल्द ऐसा ही होने वाला है. परदे के पीछे कथानक लिखे जा चुके हैं. मध्यप्रदेश को लेकर भाजपा हाईकमान अभी तक कमजोर दिख रहा था. राजनीतिक परिस्थितियों से समझौता करते हुए हाईकमान ने शांति का चोला ओढ़ रखा था. तभी तो व्यापमं जैसे घोटाले को दबाने के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया. सीबीआई को अभी तक मध्यप्रदेश में एक भी जांच के मामले में सफलता नहीं मिली है. शेहला मसूद हत्याकांड में तो सीबीआई हत्या का क्राइम सीन तक क्रिएट नहीं कर सकी है. इसमें शामिल राजनीतिक आरोपियों को इसका पूरा लाभ दिया गया और वे आरोपों के कटघरे से मीलों दूर चले गए. व्यापमं घोटाला में भी जांच सीबीआई को तो सौंप दिया गया, लेकिन एक-एक कर सभी आरोपी जेल से जमानत पर छूटते चले गए.

जबकि माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपने विरोधी खेमे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सबसे पहले गाज गिराने की तैयारी करेंगे, क्योंकि वे एक समय उनके सबसे बड़े विकल्प के रूप में उभर चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इस बार सीबीआई मप्र में कुछ करेगी. परंतु उसने इस मामले में भी हथियार डाल दिए. संघ भी इस घोटाले के आरोपों की जद में आने से नाराज था, परंतु कुछ कारणों से संघ शिवराज को माफ करता आ रहा है. परंतु अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, उनमें दावा किया जा रहा है कि संघ ने मध्यप्रदेश भाजपा में आमूल-चूल परिवर्तन का कथानक लिख दिया है. इसी सिलसिले में सबसे पहला विकेट संगठन महामंत्री अरविंद मेनन का गिरा. असल में मेनन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाम कसेंगे, परंतु मेनन उनके प्रमुख सिपहसालार बन गए . यही नहीं, हर मामले में दोनों मिलकर निर्णय करने लगे. भाजपा में कुछ कांग्रेसी नेताओं के प्रवेश की भूमिका भी मेनन द्वारा बनाई गई. यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन संघ के पास जो सूचनाएं छनकर

संघ प्रदेश भाजपा में तुरंत नेतृत्व परिवर्तन करने का पक्षधर है. इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात सामने आ रही है, वहीं मुख्यमंत्री के विकल्प की खोज भी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष केलिए दो नाम फिलहाल सामने आए हैं, उनमें साध्वी उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री की कमान देने पर विचार हो रहा है तो प्रभात झा को वापस संगठन में भेजने की बात कही गई है.

पहुंचीं, उससे संघ की भंवें तन गईं. मेनन पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी जांच मेनन के गृह नगर वाराणसी में भी कराई गई. आरोप सच पाए गए. यही नहीं, मेनन से एक महिला के कथित संबंधों का मामला भी संघ के पास पहुंचा था, परंतु उक्त महिला का आज तक कहीं पता नहीं चला. संघ के मुखबिरों ने भी मेनन को लेकर बहुत गंभीर रिपोर्ट सौंपी थी. इसके अनुसार मेनन प्रदेश भाजपा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा सांसद ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सामने यहां तक कह दिया था कि मध्यप्रदेश में या तो मेनन रहेंगे या फिर भाजपा. इसके बाद मेनन की अचानक विदाई कर दी गई.

इसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों की दृष्टि सिंहस्थ पर गई. सिंहस्थ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था. सवा लाख करोड़ का सरकार के सिर पर कर्ज होने के बाद भी सिंहस्थ में जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहाया गया, उतनी व्यवस्था वहां चुस्त-दुरुस्त नहीं दिखी. एक बड़ा हिस्सा तो मुख्यमंत्री के प्रचार में ही खर्च कर दिया गया. इसे लेकर संघ खेमे में खुसर-पुसर तेज हो गई. मेनन के स्थान पर आए संगठन महामंत्री सुहास भगत देखने में तो जितने सहज-सरल लगते हैं, उतने ही वर्तमान भाजपा नेतृत्व को लेकर उनके इरादे खतरनाक हैं. उनके नाम की घोषणा होते ही जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक दिल्ली पहुंचे तो भगत ने उनसे केवल औपचारिक मुलाकात ही की. राजनीतिक मामलों पर कोई चर्चा नहीं की. इतना ही नहीं, जब प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने उन्हें भी खास तवज्जो नहीं दिया. उनका तेवर देख विश्लेषकों का चौंकना स्वाभाविक था. माना जाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद अच्छे-अच्छे विरोधियों के तेवर भी ठंडे पड़ जाते हैं, परंतु सुहास भगत पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है. वैसे प्रदेश के प्रभारी बनाकर भेजे गए विनय सहस्त्रबुद्धे को लेकर भी पार्टी नेतृत्व आशावान थी, पर वह कोई कमाल नहीं दिखा सके. सत्ता व संगठन पर नियंत्रण करना तो दूर, वे खुद उनके नियंत्रण में दिखने लगे. हां, सिंहस्थ में जरूर एक-दो बार उनके तेवर देखने को मिले.

फिलहाल शिवराज खेमे में सन्नाटे का माहौल है, हालांकि इस खेमे के लोग मानकर चल रहे हैं कि मध्यप्रदेश में कोई विकल्प नहीं होने के कारण अगला विधानसभा चुनाव भी भाजपा शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही लड़ेगी. शिवराज ने मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के सभी दूसरी कतार के नेताओं को इतना बौना कर दिया है कि वे अपने जिले या संसदीय क्षेत्र के बाहर निकलने की बात भी नहीं सोच पा रहे हैं. पहली कतार के नेताओं को तो मार्गदर्शक बनाकर घर में बैठा दिया गया है. वहीं प्रदेश स्तर पर जिन नेताओं का प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है, उसके पर कतर दिए जाते हैं. किसी को घोटाले के आरोप में उलझा दिया जाता है तो किसी को आपराधिक मामलों में. भले ही वे बाद में बेदाग निकल आएं, लेकिन तब तक उनका राजनीतिक कद बौना हो जाता है. इसके बाद वहां उनके समानांतर नेता पैदा कर दिए जाते हैं.

यही प्रक्रिया संघ के पास पहुंची रिपोर्ट में बताई गई है. संघ व्यापमं में नाम आने से पैसे ही नाराज था, अब भाजपा की प्रदेश में लगातार गिरती छवि और इसके एक तरह से कांग्रेसीकरण होने से चिंतित है. कहा जा रहा है कि भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेता अपने व्यावसायिक हितों के कारण यहां आए हैं. अपना हित पूरा होने के बाद वे कभी भी वापस जा सकते हैं. एक तो भाजपा में अंदरूनी तौर पर उनका विरोध है और दूसरे उनकी विचारधारा भाजपा से कतई मेल नहीं खाती. ऐसे में आगामी चुनाव के ऐन पहले यदि माहौल थोड़ा भी भाजपा के विरोध में जाता दिखा, तो ये नेता फिर घरवापसी कर सकते हैं. इसकी आशंका स्वयं भाजपा और संघ को है. ऐसी स्थिति में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है. लगातार सत्ता में रहने के कारण एंटी इनकंबेंसी फैक्टर भी बढ़ रहा है. पिछली बार कांग्रेस उसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थी, इस बार कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तो भाजपा के विरोध में जाती दिख रही है. शहरी क्षेत्रों में भी आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है.

सूत्रों का कहना है कि संघ भाजपा में तुरंत नेतृत्व परिवर्तन करने का पक्षधर है. इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात सामने आ रही है. वहीं मुख्यमंत्री के विकल्प की खोज भी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए दो नाम फिलहाल सामने आए हैं, उनमें साध्वी उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री की कमान देने पर विचार हो रहा है तो प्रभात झा को वापस संगठन में भेजने की बात कही गई है. हालांकि सूची में आधा दर्जन नाम हैं, जिनके बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है. संघ बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना चाहता है, ताकि भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी बड़ा राजनीतिक नुकसान नहीं हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक किन्नर की अनूठी पहल...

मासूम की ज़िन्दगी में भरे ख़ुशियों के रंग

जगदीश शुक्ला

मुरैना जिले में जौरा तहसील की इस्लामपुरा निवासी किन्नर मंजू उर्फ पायल पढ़ी-लिखी तो नहीं, लेकिन इलाज से महरूम एक मासूम बच्ची को गोद लेकर उसने एक मिसाल कायम किया है. सीमित आमदनी के बावजूद उसने एक असहाय मां-बाप की मदद की और बच्ची का इलाज करा उसे जीवनदान दिया. इतना ही नहीं, बच्ची के मां-बाप की सहमति से गोद लेकर मासूम का भविष्य संवारने का जिम्मा भी अपने ऊपर लिया. दूसरों की खुशियों में नाच-गाकर गुजारा करने वाली मंजू ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरणा लेकर समाज के लिए सराहनीय कार्य किया है.

मंजू को एक साल पहले जानकारी मिली कि ग्वालियर क्षेत्र का एक ग्रामीण परिवार आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी बेटी का इलाज कराने में असमर्थ है. तभी मंजू ने उस बच्ची तनिष्का का इलाज कराने और गोद लेने का फैसला कर लिया. वह तनिष्का के परिजनों से मिलने गई. मासूम बच्ची के मां-बाप अपनी बेटी मंजू को गोद देने के लिए तैयार हो गए. मंजू ने कटे होठ वाली बच्ची का मुरैना, आगरा व ग्वालियर में इलाज कराया. बच्ची के पूर्णतया स्वस्थ होने के बाद मंजू अब उसके लालन-पालन में पूरी तरह से जुट गई है. वह अपनी बेटी के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना भी नहीं भूलती. मंजू अब अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर एक बड़ा पुलिस अधिकारी बनाना चाहती है. वह अपने इस नेक कार्य का कहीं जिक्र नहीं करती. लोगों को इसकी जानकारी तब मिली जब मंजू ने अपनी बेटी की द्वितीय वर्षगांठ पर जौरा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान नाच-गाने के जश्न के साथ मंजू के आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजती रहीं. इस जश्न में शरीक होने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, मुरैना एवं अन्य दूर-दराज से मेहमान आए.

बेटी को हर खुशी देने की हसरत

प्रकृति ने भले ही किन्नरों के मां बनने की हसरत छीन ली हो, लेकिन आज मंजू अपनी पूरी ममता असहाय बच्ची पर उड़ेल देना चाहती है. वह अपनी गोद ली हुई बेटी की हर इच्छा पूरी करने के लिए मां की तरह मचल उठती है. वह दुनिया की हर खुशी मासूम बच्ची की झोली में डाल देना चाहती है. मंजू की तमन्ना है कि उसकी बेटी एक ईमानदार पुलिस अफसर बन

चंबल में बेटियों को दोयम दर्जे का समझ आज भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से महरूम रखा जाता है. चंबल का इतिहास बच्चियों के जन्म लेते ही मार देने का गवाह रहा है, ऐसे माहौल में एक किन्नर ने उम्मीदों की एक नई दुनिया कायम की है.

समाज में गरीबों पर हो रहे अत्याचार को रोके.

चंबल का कलंक धोने की कोशिश

चंबल में बेटियों को दोयम दर्जे का समझ आज भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से महरूम रखा जाता है. चंबल का इतिहास बच्चियों के जन्म लेते ही मार देने का गवाह रहा है, ऐसे माहौल में एक किन्नर ने उम्मीदों की एक दुनिया कायम की है. मंजू का यह कदम सिर्फ अपने लिए जीने वाले समाज के लिए एक सबक ही नहीं, अपितु सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ अभियान का भी एक सार्थक उदाहरण है.

बसाए गरीब परिवार की बेटियों के घर

किन्नर मंजू भले ही आर्थिक रूप से इतनी संपन्न नहीं है, लेकिन वह हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए तैयार रहती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों की खुशियों में शरीक होकर नाचने-गाने पर उसे जो नेग मिलता है, उसका एक बड़ा भाग वह सामाजिक व धार्मिक कार्यों में खर्च करती है. मंजू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से प्रेरित होकर अभी तक आधा दर्जन से अधिक गरीब परिवार की लड़कियों की शादी भी करा चुकी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सारी कुंडियां खड़का कर चौधरी पहुंचे मुलायम के दरवाज़े

सपा की गोद में रालोद!

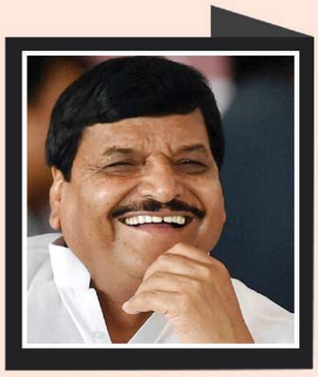

प्रभात रंजन दीन

विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट मोलभाव और शर्तों पर बिकने वाला माल हो गई है. पार्टियां योग्यता पर नहीं, उससे होने वाले राजनीतिक फायदे का गुणाभाग कर सीट दे रही हैं तो उम्मीदवार भी कितना तोल कर उस पार्टी को फायदा देगा, इसकी बोली लगा रहा है. इसमें समाजवादी पार्टी कुछ अधिक ही बेचैनी में दिख रही है. सपा की बेचैनी यह दिखा रही है कि राज्यसभा की सीट देकर वह विधानसभा की सारी सीटें अपने कब्जे में करने का जैसे स्वप्न देख रही हो. सपा की इन कोशिशों में उसका वैचारिक विरोधाभास जनता के समक्ष बुरी तरह उजागर हो रहा है.

एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सहयोग कर उसके प्रत्याशी कपिल सिब्बल को राज्यसभा तक पहुंचाने की जोड़तोड़ में लगी है तो दूसरी तरफ वह कांग्रेस के बेनी वर्मा को तोड़ कर अपनी पार्टी में शरीक करा लेती है और उन्हें भी राज्यसभा का रास्ता दिखा देती है. इससे पहले सपा ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को भी राज्यसभा भेजने में मदद की थी. लेकिन तब भी सपा को इसका कोई फायदा नहीं मिला था.अमर सिंह का भी उदाहरण सामने है, जिन्हें राज्यसभा पहुंचाने के लिए मुलायम ने रामगोपाल और आजम जैसे नेताओं की नापसंदगी का कोई ध्यान नहीं रखा. अब ताजा मामला राष्ट्रीय लोक दल के नेता चौधरी अजित सिंह के साथ हुए मोलभाव का सामने आया. राजनीतिक अवसरवादिता के शिखर-पुरुष चौधरी अजित सिंह ने इसके पहले जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जदयू ने स्पष्ट कर दिया कि रालोद का पहले जदयू में विलय हो तो फिर आगे की बात हो. रालोद के जदयू में विलय की बातें काफी परवान चढ़ीं, लेकिन इसी क्रम में चौधरी की नई-नई शर्तें भी परवान चढ़ती रहीं, और आखिरकार धराशायी हो गईं. इसके बाद चौधरी ने बसपा नेता मायावती के आगे मत्था टेका, लेकिन क्रय-विक्रय में चौधरी का मायावती के सामने क्या चलता, वहां भी वे खेत रहे. चौधरी को कांग्रेस और भाजपा की तरफ से भी ना मिल चुकी थी. तभी उन्हें सपा की विधानसभाई बेचैनी का तापमान मिला और वे मुलायम की दहलीज पर आ धंसे. इसमें पर्दे के पीछे अमर सिंह की भी भूमिका रही होगी, लेकिन वे कहीं भी सामने नहीं आए, क्योंकि उन्हें पहले अपनी राज्यसभा की सीट तो हासिल करनी थी. मुलायम ने अपने राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की नाराजगी को दरकिनार कर चौधरी अजित सिंह से मुलाकात की और विस्तार से बातचीत की. शिवपाल यादव भी इस पहल में मुलायम का साथ दे रहे थे. हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पहल से असहमत हैं. अखिलेश सोचते हैं कि वे अपने बूते ही फिर से विधानसभा का चुनाव जितवा ले जाएंगे. बहरहाल, जदयू वाले फार्मूले की तरह मुलायम भी चाहते थे कि रालोद का सपा में विलय हो जाए, लेकिन विलय में चौधरी की शर्तें भारी थीं. लिहाजा, खबर लिखे जाने तक सपा नेतृत्व की तरफ से कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया था.

रालोद और चौधरी अजित सिंह के भविष्य को लेकर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी कोई फैसला भले ही नहीं लिया, लेकिन इस प्रकरण ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के मतभेद को सामने जरूर ला दिया. इस मतभेद को बढ़ाते हुए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव यह कहते रहे कि रालोद के साथ सपा का गठबंधन साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ाई में फायदेमंद साबित होगा. शिवपाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि साम्प्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए सभी लोहियावादी, चौधरी चरण सिंह के सिद्धान्तों पर चलने वाले और गांधीवादी विचारधारा के लोग एक मंच पर हो जाएं. शिवपाल ने कहा कि रालोद के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत अभी शुरू हुई है, अच्छी बात हुई है, चौधरी अजित सिंह से उनके पहले से ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं. बातचीत आगे बढ़ी तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे.

शिवपाल के ऐसे बयान के समानान्तर रामगोपाल ने कहा कि रालोद के मुखिया अजित सिंह अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं. उनसे किसी भी तरह का समझौता करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए समझदारी नहीं होगी. रामगोपाल बोले कि कभी अजित सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अपरिहार्य हुआ करते थे. उनसे गठबंधन करने के लिए बसपा को छोड़कर सभी दल तैयार रहते थे. यह अजित सिंह पर निर्भर करता था कि वह अपने राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर किसके साथ गठबंधन करें. वह कांग्रेस, भाजपा और सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुके हैं. लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब स्थितियां बदल चुकी हैं. यही वजह है कि अजित को राज्यसभा में पहुंचने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों के दरवाजे खटखटाने पड़े और हर जगह से उन्हें अपनी पार्टी को विलय कर देने की शर्त सुननी पड़ी.

साफ है कि चौधरी अजित सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी में कितने गहरे विरोधाभास हैं. रामगोपाल ने सही ही कहा कि चौधरी सब तरफ आजमा कर सपा के दरवाजे पहुंचे. राजनीतिक गतिविधियों के जानकार बताते हैं कि इसके पहले चौधरी अजित सिंह ने बहुजन समाज पार्टी से भी हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. मायावती इसके लिए कतई तैयार नहीं हुईं. जाटव वोट बैंक को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का मुख्य आधार माना जाता है. जाटवों और जाटों के बीच शाश्वत झगड़ा रहता है. रालोद से तालमेल पर जाटव वोट बैंक नाराज हो सकता था, क्योंकि जाट और जाटव कभी साथ में नहीं आ सकते. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट के खिलाफ गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा भी बसपा को मिलता है. लिहाजा, ऐसा गठजोड़ बसपा के लिए प्रतिगामी हो सकता है.

इस प्रकरण में चौधरी अजित सिंह की तो फजीहत हो गई. यहां तक कि उनकी मदद के लिए कांग्रेस भी तैयार नहीं हुई जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत खुद ही खस्ता है, फिर भी कांग्रेस ने चौधरी में कोई रुचि नहीं दिखाई. अजित सिंह राज्यसभा जाने के इरादे से सोनिया गांधी से मिले भी थे और राज्यसभा भेजने के बदले 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करने की बात भी कही थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया.

यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चौधरी की शर्तों के बरक्स विलय कर लेने की सलाह रखी थी. भाजपा के साथ मिल कर वे पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं और इसका उन्हें फायदा भी मिला है. 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के तालमेल से रालोद के पांच सांसद जीते थे. 2002 के विधानसभा चुनाव में भी रालोद के 14 विधायक जीते थे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों के साथ भाजपा का सामंजस्य हो जाता था, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट वोटर पूर्ण रूप से भाजपा के साथ हो गए. 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की शानदार कामयाबी के पीछे जाट-शक्ति ही है. यही वजह है कि चौधरी अजित सिंह की प्रासंगिकता उतनी नहीं रही, हालांकि भाजपा ने उनके समक्ष विलय की शर्त रखी थी, लेकिन चौधरी को यह मंजूर नहीं हुआ. 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अजित सिंह से तालमेल किए बगैर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से काफी सीटें जीती थीं. सपा को मुसलमान और गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा मिला था. लेकिन मुजफ्फरनगर कांड ने इस ध्रुवीकरण को बुरी तरह झकझोर दिया. यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से पश्चिम पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें चौधरी अजित सिंह को अपने साथ मिलाने से परहेज नहीं. ■

शिवपाल के ऐसे बयान के समानान्तर रामगोपाल ने कहा कि रालोद के मुखिया अजित सिंह अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं. उनसे किसी भी तरह का समझौता करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए समझदारी नहीं होगी. रामगोपाल बोले कि कभी अजित सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अपरिहार्य हुआ करते थे. उनसे गठबंधन करने के लिए बसपा को छोड़कर सभी दल तैयार रहते थे. यह अजित सिंह पर निर्भर करता था कि वह अपने राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर किसके साथ गठबंधन करें.

feedback@chauthiduniya.com

मुलायम चाहते हैं पश्चिम में जाट और मुसलमान फिर एक हों

राष्ट्रीय लोक दल का समाजवादी पार्टी में विलय के बहाने मुलायम की मंशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाटों और मुसलमानों के बीच एकता और व्यापक समीकरण स्थापित करने की है. मुजफ्फरनगर कांड के बाद पश्चिम के दो बड़े वोट बैंक अलग-अलग हो गए, जिसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ रहा है, वही नतीजा 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी नहीं भुगतना चाहती. लिहाजा, विलय या तालमेल की इन कोशिशों के गहरे निहितार्थ हैं. राजनीतिक समीक्षकों का भी मानना है कि अगर सपा के मुस्लिम और रालोद के जाट वोटरों का गठजोड़ फिर से बन जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 145 विधानसभा सीटों पर भाजपा और बसपा के लिए तगड़ी चुनौती दे सकता है. पिछले दिनों सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और रालोद नेता चौधरी अजित सिंह की दिल्ली में जो मुलाकात हुई उसमें इन मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके बाद ही चौधरी सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलने दिल्ली में महारानीबाग स्थित उनके आवास पर गए. इससे पहले भी शिवपाल अजित सिंह से मिल चुके थे. सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि रालोद सहित कई दूसरी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में सरकार विरोधी माहौल से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है.सपा नेतृत्व यह भी देख रहा है कि पिछले दो चुनावों में सपा और बसपा के बीच करीब चार फीसदी वोट के अंतर पर हार-जीत हुई है, जबकि रालोद करीब तीन फीसदी वोट हासिल करने में कामयाब रहा है.पिछले दो विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी तीस प्रतिशत वोट हासिल करने में कामयाब रही, वह बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेती है. वर्ष 2007 में बसपा को 30.43 प्रतिशत वोट के साथ 206 सीटें मिली थीं. जबकि 2012 में सपा को 29.3 प्रतिशत वोट के साथ 224 सीटें मिलीं. इस चुनाव में रालोद ने 46 सीट पर चुनाव लड़ा और उसे 2.5 फीसदी मतों के साथ नौ सीटें मिली थीं. ■

कांग्रेस से ख़ुद दफा हो जाएंगे ख़फा प्रशांत!

कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए बड़ी उम्मीदों से लाए गए प्रशांत किशोर के कांग्रेस छोड़ कर जाने की चर्चाएं यूपी कांग्रेस से लेकर दूसरी पार्टियों में भी सरगर्म हैं. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को प्रशांत किशोर के सुझाव रास नहीं आ रहे हैं. ऐसे में संभव है कि कांग्रेस उनसे और वे कांग्रेस से जल्दी ही मुक्ति पा लें. इस तरह कांग्रेस मंझधार में ही छूट जाएगी. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि वैसे ही कांग्रेस को यूपी में क्या मिलना है.

प्रशांत किशोर के सुझावों और शिकायतों को सुधारात्मक तौर पर लेने के बजाय कांग्रेस के नेता उसे निजी तौर पर ले रहे हैं. वे प्रशांत किशोर के खिलाफ बगावती माहौल तैयार कर रहे हैं. उनकी सभाओं में सार्वजनिक विरोध और यहां तक कि मारपीट की घटनाएं भी होने लगी हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ही प्रशांत किशोर की सेवाएं ली थीं. प्रशांत किशोर को बिहार चुनाव में नीतीश का साथ देने और उनकी सफलता में भूमिका अदा करने का पुरस्कार मिला था. लेकिन प्रशांत को बिहार से कहीं अधिक मुश्किलों का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ रहा है. उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को प्रशांत की दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही है. पार्टी नेताओं की शिकायत पर आलाकमान ने यह कह कर प्रशांत को फटकार भी लगाई है कि उन्हें पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने का जिम्मा दिया गया है न कि संगठन का पदाधिकारी बनाने और टिकट बांटने को लेकर फैसला करने का. इस फटकार और फजीहत के बाद प्रशांत का जाना करीब-करीब तय हो गया है. प्रशांत ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो योजना तैयार की थी, उसे भी कांग्रेस नेताओं की आपत्तियों के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने खारिज कर दिया है.

प्रशांत किशोर ने पार्टी को सुझाव दिया था कि यूपी में पार्टी का चेहरा किसी ब्राह्मण का हो. प्रशांत ने राजपूत और मुस्लिम वोट को भी लक्ष्य करने की योजना कांग्रेस के समक्ष रखी थी. प्रशांत का मत था कि कांग्रेस दलित वोटों के लिए अन्य समीकरण खराब न करे, क्योंकि दलितों का एक खास तबका मायावती के साथ ही रहेगा. प्रशांत ने यह भी सुझाव दिया था कि राहुल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में प्रियंका की भी खास भूमिका होनी चाहिए. प्रशांत ने उम्मीदवारों के लिए 250 कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाने की शर्त के साथ ही टिकट देने का फॉर्मूला भी रखा था, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे पचा नहीं पाए. इन बदली हुई स्थितियों में प्रशांत को यह लगने लगा है कि उन्हें अगर बिहार चुनाव की तरह बहुत हद तक आजादी से काम नहीं करने दिया गया तो अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं होंगे, ऐसे में उनका निकल लेना ही बेहतर है. प्रियंका का नाम लेने पर कांग्रेस की इलाहाबाद इकाई के दो नेताओं हसीब और शिरीष को महासचिव पद से हटा दिए जाने का तमाशा प्रशांत देख चुके हैं, लिहाजा ऐसे तमाशे को वो अपने लिए पूर्व संकेत भी मान कर चल रहे हैं. इलाहाबाद कांग्रेस के ये दोनों नेता प्रियंका गांधी को राजनीति में सक्रिय करने और कांग्रेस पार्टी में अहम ज़िम्मेदारी दिए जाने की मांग कर रहे थे. ■

अरुणाचल प्रदेश, तवांग

शांति दूतों पर पुलिसिया हमला

नवीन चौहान

तिब्बती बुद्धिज्म का केंद्र होने के कारण कभी सुर्खियों में रहने वाला अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र अब जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के विरोध के कारण चर्चा में है. हाल में तवांग के स्थानीय लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जो अपने नेता लामा लोसांग ग्यातसो को पुलिस हिरासत से छोड़े जाने की मांग कर रहे थे. 2 मई को करीब दो हजार लोग तवांग के जिला मुख्यालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बिना चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी. इस घटना में तवांग मोनेस्ट्री के 21 वर्षीय बौद्ध भिक्षु नियमा वांगड़ी और जांगोड़ा गांव के तेसरिंग टेंपा (31 वर्ष) की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई. जबकि अन्य 19 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत अब भी नाजुक बनी है. ग्यातसो को पुलिस ने आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था. उन्हें ज़मानत भी नहीं मिल पा रही थी. ऐसे में लोगों को यह आशंका थी कि कहीं उनके साथ कुछ गलत न हो जाए. वहीं, पुलिस ने आरोप लगाया कि विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस थाने पर हमला करने की कोशिश की, पुलिस को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा है.

पुलिस अधिकारियों की यह तहरीर लोगों के गले नहीं उतर रही है. स्थानीय लोगों का मानना है कि जलपरियोजनाओं के विरोध के कारण प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं. इस क्षेत्र में तकरीबन 125 छोटी-बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है. जिनमें 13 बड़ी परियोजनाएं हैं. पर्यावरणीय और धार्मिक दृष्टिकोण के कारण साल 2011 से ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं. स्थानीय लोग लंबे समय से 780 मेगावाट की, 6400 करोड़ रुपए लागत वाली न्यामंग चू पॉवर परियोजना के विरोध में थे. इस परियोजना के लिए 2012 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी. लेकिन हाल में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस पर रोक लगा दी थी. इस परियोजना के निर्माण स्थल पर ठंड के दिनों में काले गले वाले क्रेन (सारस) का प्राकृतिक आवास है. स्थानीय बौद्ध मोनपा समुदाय के लोग इस पक्षी को 6वें दलाई लामा का अवतार मानते हैं जो तवांग घाटी के रहने वाले थे. काले गले वाले क्रेन(सारस) तिब्बत के पठार में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में तवांग आ जाते हैं. ये पक्षी मुख्य रूप से चीन में पाए जाते हैं. आईयूसीएन (इंटरनेशनव यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर) ने इस पक्षी को विलुप्त होने की सूची में रखा है जबकि भारत में वन्यजीव कानून में इसे पहली अनुसूची में रखा गया है. इसके अलावा इस क्षेत्र में अन्य जीव जैसे लाल पांडा, स्नो-लियोपर्ड पाए जाते हैं. इस संबंध में तवांग घाटी में रहने वाले लोगों ने कई बार स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की एजेंसीज को पत्र लिखे. थक-हारकर उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण (एनजीटी) का रुख किया. एनजीटी ने प्रोजेक्ट के लिए दी पर्यावरणीय मंजूरी को 7 अप्रैल 2016 को निरस्त कर दिया.

एनएपीएम के उमेश बाबू बताते हैं कि 26 अप्रैल 2016 को स्थानीय नेता ग्यात्सो को एनजीटी के निर्णय के फलस्वरूप बदला लेने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया. इसके बाद 28 अप्रैल को जिला पंचायत अध्यक्ष ने तवांग घाटी क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर परिचर्चा के लिए एक जनसभा आयोजित की, वहां लोगों ने एक काग़ज पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए दस्तखत किए. बाद में उस

अटेंडेंस शीट को साजिशन एक अन्य काग़ज के साथ अटैच कर दिया गया और ग्यात्सो को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद चार दिन तक उन्हें अदालत से ज़मानत नहीं मिली. 2 मई 2016 को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित होकर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेता को रिहा करने की मांग कर रहे थे.

इस घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग स्थानीय लोगों ने की. जब सरकार और प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो 60 बौद्ध भिक्षुओं का एक दल विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा और सरकार के सामने अपनी मांग रखी. तवांग से दिल्ली आए लोसांग चौदुप ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मसले पर ध्यान दे. अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर रही है. साउथ एशियन नेटवर्क फॉर रिवर्स, डैम एंड पीपुल

के हिमांशु ठाकुर ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि इस परियोजना से पैदा हुई बिजली तवांग के लोगों तक पहुंचेगी या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन उनका विनाश होना तय है. ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के जंपा टेसरिंग ने कहा कि तवांग के लोगों को माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट की आवश्यकता है न कि बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की.

पुलिस फायरिंग को बर्बरतापूर्ण करार देते हुए नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट के विमल भाई ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे शांत प्रदेशों में से एक है. यहां बौद्ध भिक्षु बहुतायत में रहते हैं. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने का कोई कारण नज़र नहीं आता, वह भी बिना किसी चेतावनी के. यह घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह पूर्वनियोजित थी? लोगों की मांग है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार पुलिस ने किसके आदेश पर यह कदम उठाया.

यहां काम कर रहे एसएमआरएफ, एनएपीएम, डीएसजी जैसे समूह प्रशासन के इस मनमाने रवैये की आलोचना कर रहे हैं. उनका कहना है कि निजी कंपनियों और सरकारी महकमे का गठजोड़ लोकहित के खिलाफ काम कर रहा है. क्या सरकार लोगों को डरा धमकाकर निजी कंपनियों को पर्यावरणीय मंजूरी दिलाना चाहती है. क्या वह लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी न किसी तरह दोबारा पर्यावरणीय मंजूरी कंपनी को दिला देगी. भले ही उसे लोगों की लाश पर से ही क्यों न गुजरना पड़े. एसएमआरएफ के सदस्य लोसांग चोदप ने आरोप लगाया कि बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं न केवल तवांग के पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर रही हैं बल्कि बौद्ध समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों को भी खत्म कर रहे हैं. चीन के साथ सीमा लगे होने की वजह से तवांग क्षेत्र में कई जगहों पर सेना का कब्जा है. इसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट इस क्षेत्र को लील रहे हैं, ऐसे में स्थानीय लोग और उनकी संस्कृति खतरे में है.

इस क्षेत्र में काम कर रहे पर्यावरणीय सिविल सोसयटी एसएमआरएफ के प्रतिनिधियों ने नेशनल एलांयस फॉर पीपुल्स मूवमेंट और दिल्ली सॉलीडैरिटी ग्रुप के प्रतिनिधियों के एक समूह ने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव से दिल्ली में क्रमशः 24 और 25 मई को मुलाक़ात की. अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि राज्य के अधिकारियों पर अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के तहत मामला दर्ज किया जाए और मामले की जांच सीबीआई या न्यायिक आयोग का गठन कर की जाए. साथ ही जांच में स्थानीय पुलिस को शामिल नहीं किया जाए. इसके अलावा पुलिस फायरिंग में मारे गए और घायल लोगों को मुआवजा देने के लिए कहेंगे.पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि वे एनजीटी के 7 अप्रैल के आदेश को चुनौती नहीं देंगे. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय वन्यजीव संस्थान से विलुप्तप्राय पक्षी के संबंध में अध्ययन कराने का आश्वासन भी दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

असम में पुलिस उत्पीड़न का सिलसिला जारी, आयोग गंभीर

असम में पुलिस तंत्र की अराजकता और लोगों के उत्पीड़न के मामले लगातार दर्ज होते आए हैं. हाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने असम में हुई मुठभेड़ के चार मामलों को फर्जी ठहराते हुए असम सरकार और रक्षा मंत्रालय को सख्त निर्देश दिया कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए छह युवकों के परिवारों को राहत के तौर पर कुल 30 लाख रुपए अदा किए जाएं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सेना और अर्धसैनिक बलों की इकाइयों के साथ असम पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ के चार मामलों को फर्जी पाया. इनमें से तीन मामलों में आयोग ने असम सरकार से मृतकों के निकट परिजनों को राहत के तौर पर कुल 25 लाख रुपए अदा करने को कहा. वहीं आयोग ने मुठभेड़ के चौथे मामले में रक्षा मंत्रालय को राहत के तौर पर पांच लाख रुपए अदा करने को कहा है. सभी मामलों में आयोग की नोटिस के जवाब में न तो असम सरकार और न ही रक्षा मंत्रालय आयोग को तसल्ली करा सका कि मुठभेड़ असली थी. पुलिस और सेना ने पहले कहा था कि सशस्त्र बलों को उस वक्त आत्मरक्षा में गोलीबारी करनी पड़ी जब उन पर बदमाशों और उग्रवादियों ने हमला किया था.

गौरतलब है कि पीकू अली 23 जुलाई 2008 को नगांव जिले में पुलिस गोलीबारी में मारा गया था. मृगांक हजारिका और हिमांशु गोगोई नाम के दो युवक 23 फरवरी 2011 की रात दिसपुर में पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे. आयोग ने दोनों मृतकों के निकट परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए राहत के तौर पर देने का निर्देश दिया है. जॉनम वासुमतारी और ओखोफट वासुमतारी सोनितपुर जिले में जून 2009 में ही पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे. आयोग ने प्रत्येक परिवार को पांच-पांच लाख रुपए देने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोनितपुर जिले में नौ जुलाई को हुई मुठभेड़ में रोजित नाराज़ारे उर्फ अबराम के मारे जाने के मामले में रक्षा मंत्रालय को मृतक के निकट परिजन को छह हफ्ते के अंदर पांच लाख रुपए अदा करने को कहा है.

इसके पहले भी फर्जी मुठभेड़ के छह मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर असम सरकार ने मृतकों के परिजनों को 40 लाख रुपए का मुआवजा दिया था. आयोग के मुताबिक राज्य में 2010 और 2011 के दौरान हुई मुठभेड़ों में से छह घटनाएं फर्जी पाई गई थीं. जांच पड़ताल के दौरान राज्य सरकार इन घटनाओं की सत्यता साबित नहीं कर पाई थी. ■

पश्चिम बंगाल में बांग्ला-हिंदी के रोचक प्रसंग

दारुण हिंदी का 'मोजा' लीजिए

विनय बिहारी सिंह

चुनावी चर्चाएं बहुत हो गईं. अब तो चुनाव परिणाम भी आ गए और ममता बनर्जी फिर से सत्ता पर काबिज हो गईं. लिहाजा, थोड़ा विषयांतर भी जरूरी है. राजनीतिक खबरों और विश्लेषणों से अलग बंगाल के सामान्य लोगों में हिंदी कैसे बोली जाती है, इसका भी थोड़ा आनंद लेते चलें. कहने की जरूरत नहीं कि सारी भाषाएं मूल रूप से संस्कृत से निकली हैं. बांग्ला एक अत्यंत समृद्ध भाषा है. क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द बहुतायत में मिल जाएंगे. हिंदी तो अत्यंत शुद्ध और समृद्ध है ही. लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों भाषाओं का रोचक घालमेल देखने को मिलता है. एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का आना पश्चिम बंगाल में सामान्य सी बात है. सब वैसे ही जैसे कि भाषा की सारी नदियां हिंदी की गंगा में मिल जाती हैं. हिंदी में स्वच्छ की जगह बांग्ला का प्रचलित शब्द परिष्कार भी चलता है और नया की जगह नूतन भी चलता है. हां, बांग्ला उच्चारण (प्रोनंसिएशन) के हिसाब से नतून नहीं चलता.

शुरुआत एक रोचक घटना से करते हैं. एक परिवार ने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया था. समय काटने के लिए उनके बच्चे की हिंदी की कॉपी देख रहा था. बच्चों को ऐसे व्यक्ति पर लेख लिखना था जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हो. जिस परिवार में मैं आमंत्रित था, उनकी बच्ची ने अपनी दीदी को प्रेरणा का स्रोत बताया था और उनके बारे में लिखा था. कॉपी जांचने वाली अध्यापिका बांग्ला भाषा के परिवेश से थीं. उस बच्ची के लेख में उन्होंने एक पंक्ति जोड़ दी थी. पंक्ति इस प्रकार थी- मेरी दीदी मेरी सारी चाहिताएं पूरी कर देती हैं. (चाहिता बांग्ला शब्द है, जिसका अर्थ है इच्छा). अध्यापिका लिखना चाहती थीं-मेरी दीदी मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देती हैं. लेकिन वह बांग्ला मिश्रित हिंदी हो गई. मुझे यह पढ़ कर झटका भी लगा और अच्छा भी लगा, क्योंकि भाषाएं इसी तरह गलबहियां डाल कर आगे बढ़ती जाती हैं. वह अबोध बच्ची बांग्ला मिश्रित हिंदी सीख रही थी, इस ओर अभिभावकों का ध्यान दिलाने पर उन्होंने कहा कि वे स्कूल की प्रधानाध्यापिका से मिलेंगे और इस समस्या पर बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि कम वेतन देकर कुछ प्राइवेट स्कूल हिंदी की कम जानकारी वाली किसी महिला को भी हिंदी टीचर नियुक्त कर देते हैं.

दूसरी घटना भी कम रोचक नहीं है. एक कार्यालय में उत्तर प्रदेश से कुछ सामान भेजा गया. अंदर जो कागज मिला, उस पर लिखा था- भेजे गए सामान की सूची. इस सूची में लिखा गया- नए रजिस्टरों की संख्या-९. अब हिंदी के अंकों को समझने वाला वहां कोई नहीं था. एक बांग्ला जानने वाले कर्मचारी ने हिंदी समझने का दावा किया और उसने बांग्ला में हिंदी के नौ को सात लिख दिया. अब दोनों कार्यालयों में पत्राचार शुरू हुआ. कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं. अंत में जब सामान भेजने वाले कार्यालय की जांच टीम कोलकाता आई और हिंदी व बांग्ला अनुवाद आमने-सामने रखा गया तो गलती पकड़ में आई. हिंदी जानने का दावा करने वाले कर्मचारी ने कहा कि हिंदी का ९ बांग्ला के सात से मिलता-जुलता है, इसलिए मैंने सात लिख दिया.

कई मामलों में कुछ शब्द हिंदी में भी बांग्ला उच्चारण जैसे ही लिख दिए जाते हैं. जैसे- पानी ठंकी को टेंकी, बस को बास, गाय को गोरू, नमकीन को नुनता और स्वादिष्ट को दारुण. हिंदी में दारुण अत्यंत कष्टकारी अर्थ में लिया जाता है. लेकिन बांग्ला में अत्यंत स्वादिष्ट सामग्री की प्रशंसा दारुण टेस्ट कहकर की जाती है.

अब बंगाल के साइन-बोर्ड भी देखें. कोलकाता के पास एक अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है- दक्षिणेश्वर. यह वही विशिष्ट स्थान है जहां विख्यात संत रामकृष्ण परमहंस ने आध्यात्मिक साधनाएं की थीं और मां काली का साक्षात दर्शन किया था. जहां उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनसे दीक्षा ली थी. यहां हिंदी भाषी प्रदेश के अनेक लोग रोज आते हैं और मां काली का दर्शन करते हैं. शनिवार और मंगलवार को तो यहां भारी भीड़ होती है. कोलकाता आने वाला हर आस्तिक व्यक्ति यहां आना चाहता है. यहां बस स्टैंड पर कुछ सरकारी बोर्ड लगे हैं. इसमें एक पर लिखा है- बेलघरिया एक्सप्रेस हाई ओय. बेलघरिया एक्सप्रेस हाई-वे की जगह यह अशुद्ध हिंदी आपको खूब गुदगुदाती है. हिंदी के ऐसे प्रयोग देख कर मन दुखी भी होता है, लेकिन हिंदी सब जगह प्रविष्ट है, यह देख कर संतोष भी होता है.

कोलकाता में बांग्ला-हिंदी का यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है. मेट्रो रेल के डिब्बे में एक स्टिकर चिपकाया गया था. अब उसे हटा लिया गया है- दरवाजे पास-पास में खुलेंगे, दरवाजों पर टेक न लगाएं. कहने की कोशिश है कि मेट्रो रेल के दरवाजे सरक (स्लाइड) कर खुलते हैं. लेकिन जो दरवाजे एक दूसरे के विपरीत (अपोज़िट) सरक कर खुलते हैं, उन्हें पास-पास लिखा जाना बांग्ला प्रभाव को दर्शाता है. कोलकाता में आपको सुरक्षित स्थान के बदले सुरक्षित स्थान लिखा हुआ कई जगह दिख जाएगा. दक्षिण कोलकाता के बाजारों में सोने-चांदी के गहनों की अनेक दुकानें हैं. हैं तो उत्तर कोलकाता में भी, लेकिन दक्षिण कोलकाता में अपेक्षाकृत ज्यादा हैं. किसी जमाने में यहां एक प्रसिद्ध ज्वेलर हुआ करते थे- लक्ष्मी बाबू (बांग्ला में इसे लक्खी बाबू कहते हैं). उनका नाम प्रतिष्ठा और शुद्धता का पर्याय बन गया है. आप किसी न किसी दुकान पर यह लिखा जरूर देख सकते हैं- यहि लखि बाबु की असली दोकान हाय. (यह लक्खी बाबू की असली दुकान है). इसी तरह अनेक जगहों पर चित्तु बाबू को चित्तु बाबु लिखना आम चलन है. यदि आपको अशुद्ध हिंदी खटकती है तो इसका मतलब है कि आप भाषा के फैलाव और विस्तार का आनंद नहीं ले रहे. भाषा को लेकर एक ही ढक्कन में बंद होना तकलीफ देता है. अब देखिए, हिंदी में कई बार जहां बड़ी ई वाली मात्रा का प्रयोग होता है, वहां बांग्ला में छोटी ई चलता है. जैसे- बीड़ी को ही लें. इसे बांग्ला में बिड़ि लिखा जाता है. कुछ बांग्ला लिखने वाले हिंदी में बीड़ी को बिड़ि ही लिखते हैं. उन्हें यही लिखने की आदत है. यहां छपने वाले हिंदी के पैंफलेटों में कई बार इसी तरह की अशुद्धियां दिख जाती हैं और कई बार क्लिष्टता भी दिखती है जैसे- स्वच्छता बनाए रखें को परिष्कारिता बनाए रखें, चेतना रैली को सचैतन्य रैली लिखा जाता है और आम सभा का अनुवाद साधारण सभा कर दिया जाता है. एक दिलचस्प घटना का जिक्र करना यहां जरूरी है. एक राजनीतिक दल की रैली में बांग्ला में पर्चा छपवाया गया. उस पर रैली की तिथि, समय और उसमें आने का आह्वान किया गया था. अंत में लिखा गया था- दले-दले आसून (दल बना कर आइए. यानी समूह बना कर आइए. निहितार्थ- रैली को सफल बनाइए). किसी को हिंदी अनुवाद करने को कहा गया ताकि पर्चा हिंदी में भी छप सके. अनुवादक ने अंतिम पंक्ति का अनुवाद किया- दलदल में आइए. अब कौन दलदल में फंसने के लिए आए? पढ़ने वाले को सदमा लगे तो उसका दुर्भाग्य और मजा आए तो उसके हवादार दिमाग को साधुवाद.

एक और दिलचस्प वाकया का जिक्र न करने से यह रिपोर्ताज अधूरी रह जाएगी. पश्चिम बंगाल में मूढ़ी (पफ्ड राइस) खाने का चलन है. आमतौर पर लोग शाम को मूढ़ी का नाश्ता ही करते हैं. यह सुपाच्य और बिना घी-तेल वाला नाश्ता है. हालांकि मूढ़ी में नमक, नमकीन और सरसों का तेल डलवा कर, बेगुन भाजा (बांग्ला में बैगन के पकौड़े को बेगुन भाजा कहते हैं) के साथ खाने वालों की भी कमी नहीं है. लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सतर्क लोग सादा मूढ़ी ही खाते हैं. नाश्ते के रूप में अनेक लोग मूढ़ी को सर्वोपरि रखते हैं. तो एक जगह लिखा था- स्वादिष्ट और ताजा मुड़ी खाइए. अब भोजपुरी बोलने वालों के लिए मुड़ी का अर्थ है सिर. मूढ़ी की जगह मुड़ी देख कर भोजपुरी वाला यह समझने की गलती न करें, स्वादिष्ट और ताजा सिर खाइए. आमतौर पर लोग लिखने का निहितार्थ समझते हैं, अशुद्धियों पर ध्यान जरूर देते हैं, पर उसका मोजा (मजा) लेते हैं.

ऐसे ही कुछ और मोजा-दार उदाहरण बंगाल में मिलेंगे. कई मामलों में कुछ शब्द हिंदी में भी बांग्ला उच्चारण जैसे ही लिख दिए जाते हैं. जैसे- पानी टंकी को टेंकी, बस को बास, गाय को गोरू, नमकीन को नुनता और स्वादिष्ट को दारुण. हिंदी में दारुण अत्यंत कष्टकारी अर्थ में लिया जाता है. लेकिन बांग्ला में अत्यंत स्वादिष्ट सामग्री की प्रशंसा दारुण टेस्ट कहकर की जाती है. सत्तू को छातू लिख देना भी इसी कड़ी का हिस्सा है. छाता को छाती लिखना-कहना बांग्ला हिंदी का आम हिस्सा है. उनके लिए बड़ा छाता, छाता और छोटा छाता, छाती. जबकि हिंदी में छाता और छाती का कहीं कोई रिश्ता नहीं है. बंगाली हिंदी में अनेक शब्द को अनेकों लिख कर अशुद्ध कर दिया जाता है, लेकिन यह गलती तो हिंदी के जानकार भी करते हैं. बंगाल के गुहा साहब को पुकारते हुए हिंदी जगत के लोग गुहा की क्या दुर्गत करते हैं, इसका दर्द बंगाली महसूस करते हैं, फिर भी मोजा लेते हैं... ■

feedback@chauthiduniya.com

मधेसी आंदोलन पार्ट-टू

सधे क़दम से सरकार बेदम

विनोद/गोविंद

भारत का सहयोगी मित्र राष्ट्र नेपाल इन दिनों भारी राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है.पिछले साल अगस्त में नेपाल सरकार द्वारा लाए गए संविधान के मसौदे को मधेसियों ने एक सिरे से खारिज कर सरकार से संविधान में संशोधन की मांग की थी. इसके बाद से ही हालात बिगड़ते चले गए. संपूर्ण नेपाल आंदोलन की जद में आ गया और धरना, प्रदर्शन से लेकर आर्थिक नाकेबंदी महीनों तक जारी रही. इस दौरान नेपाल में पुलिस व सेना और आंदोलनकारियों के बीच हुई सीधी टक्कर में सैकड़ों लोगों की जानें गईं. आंदोलनकारियों ने सरकार की हठधर्मिता भांपकर आंदोलन की दिशा बदलने की ठानी. उन्होंने कुछ समय तक विराम के बाद नेपाल सरकार से अपनी मांगों को लेकर फिर सीधी भिड़ंत शुरू कर दी. इस बार आंदोलन का केंद्र गांव की बजाय देश की राजधानी काठमांडू को बनाया गया और देखते-देखते सड़कों पर आंदोलनकारी उतर आए. अब देखना है कि 29 मधेसी समर्थक दलों की एकता क्या गुल खिलाती है.

लंबे अर्से तक माओवादी हिंसा को झेलने के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम तो हुई, लेकिन नेपाली शासकों की अदूरदर्शिता के कारण महज चंद साल बाद ही राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो गई. पिछले साल नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा लाए गए नए संविधान मसौदे ने ऐसा बवाल खड़ा किया कि देश में हर तरफ आंदोलन की लपटें उठने लगीं. देश में अराजकता व अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई. संविधान में उचित अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर नेपाल के तराई में रहने वाले मधेसियों ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया. इसकी आंच भारत-नेपाल सीमा पर रह रहे दोनों देश के नागरिकों को भी झुलसाने लगी. तब पुराने संबंधों पर खतरा महसूस करते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर भारत ने मधेसी आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया. तब मधेस आंदोलन का नेतृत्व महज आधा दर्जन राजनीतिक संगठन कर रहे थे. आंदोलन के दूसरे चरण में जब इसकी आंच काठमांडू तक पहुंची तब ढाई दर्जन राजनीतिक दलों ने आंदोलनकारियों का साथ देना शुरू कर दिया. हालात ये हैं कि आंदोलनकारी नेपाल के प्रधानमंत्री के कार्यालय व आवास का घेराव करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं. नेपाल सरकार की तमाम कोशिशें नकारा साबित हो रही हैं. आंदोलनकारियों ने रणनीतिक बदलाव करते हुए आम जनता को परेशान नहीं कर नेपाल सरकार को सबक सिखाने की ठानी है.

अब नेपाल में शुरू द्वितीय चरण के मधेस आंदोलन पर एक नजर डालते हैं. 15 मई 2016 को मधेसी नेताओं ने काठमांडू में सिंह दरबार की घेराबंदी कर प्रदर्शन किया. काठमांडू के माईतीघर

मंडला से आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठानी शुरू की. आंदोलन में मधेसमोरचा के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम व थारू सहित कई अन्य वर्गों के लोग शामिल हुए. नेपाल सरकार के मुख्य प्रशासनिक भवन सिंह दरबार को घेरने की योजना में मधेसी नेताओं को सफलता मिल गई. आंदोलन के क्रम में हनुमान स्थान पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई. माइती मंडला के नजदीक आंदोलनकारियों ने पुलिस घेराबंदी को तोड़ते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. आंदोलनकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आंदोलन केवल सरकार को परेशान करने के लिए किया जाएगा. नेपाल के संविधान में अपने अधिकारों समेत 27 सूत्री मांगों के समर्थन में महज 7 दलों के साथ शुरू हुए आंदोलन में अब समर्थक दलों की संख्या बढ़कर 29 तक पहुंच गई. आंदोलनकारी पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं हैं. 17 मई को मधेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास व कार्यालय घेर लिया, पुलिस लाठीचार्ज में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, लेकिन किसी ने भी कदम पीछे नहीं हटाया. लाठी चार्ज में सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण व तराई मधेस समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा तिवारी समेत कई आंदोलनकारी जख्मी हुए. प्रदर्शन में सद्भावना पार्टी के नेता राजेंद्र महतो, संघीय समाजवादी फोरम के नेता उपेंद्र यादव व तमलोपा के महंत ठाकुर समेत कुल 29 दलों के अध्यक्ष, नेता व कार्यकर्ताओं ने अहम भागीदारी दी. 21 मई 2016 को काठमांडू में वैध नेतृत्व वाले माओवादियों द्वारा विरोध जताने के बाद नेपाल की राजनीति में भूचाल आ गया है. बताया जाता है कि माओवादियों ने विक्रमचंद विप्लवा, हेमंत प्रकाश बली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. इन लोगों ने-जनयुद्ध जारी है, सशस्त्र क्रांति जिंदाबाद, नया संविधान खारिज करो व संसदीय व्यवस्था वापस लो-के नारे लगाए. माओवादियों के इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. मधेसी, माओवादी व नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा वर्तमान सरकार के विरोध में उतरने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है. वीरगंज, पोखरा, जनकपुर, रौतहट के अलावा काठमांडू के कई इलाकों में आंदोलन चरम पर है. धरना, प्रदर्शन व विरोध सभाएं लगातार जारी हैं. इस विरोध-प्रदर्शन के बीच नेपाल सरकार ने बजट पास किया. इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकने को तैयार नहीं है. वहीं आंदोलनकारी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं. साफ है कि अगर नेपाल सरकार मधेसी आंदोलन पर जल्द विचार नहीं करती तो नेपाल का भविष्य क्या होगा, कहना मुश्किल है.

बताते चलें कि पिछले आंदोलन में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह मीडिया फॉर बॉर्डर हारमोनी के संरक्षक डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने नेपाल के मधेस आंदोलन के समर्थन में भारत-नेपाल के सीमावर्ती जिले में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाया था. तब उन्होंने कहा था कि अगर नेपाल सरकार मधेसियों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो नेपाल के अंदर घुसकर आंदोलन से भी परहेज नहीं किया जाएगा. नेपाल के मधेसियों का भारत से रोटी-बेटी के संबंधों का हवाला देते हुए आम लोगों से भी मधेस आंदोलन को समर्थन देने की अपील की. रघुवंश प्रसाद ने कहा था कि नेपाल मसले पर भारत के केंद्र सरकार की नीति पूर्णत: विफल रही है. अब मधेसियों ने भी भारत सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद छोड़ खुद लड़ने का मन बना लिया है. लेकिन यह तो तय है कि पड़ोसी नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का खामियाजा देर-सबेर भारत को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बेवक़ूफ ही भारत-पाकिस्तान जंग की सोच सकते हैं

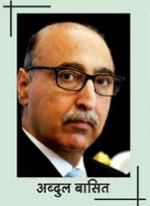
अब्दुल बासित

यह हकीकत है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया था, तो उस वक़्त पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं थे. मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि हमारे दफ्तरों में साधारण पिन तक नहीं थी और काग़ज़ात को तिनकों के जरिए जोड़ा जाता था. जब आज़ादी हासिल हुई, तो पाकिस्तान में कोई महत्वपूर्ण इंडस्ट्री नहीं थी. संक्षेप में कहा जाए तो पाकिस्तान एक नया और गरीब मुल्क था, और जो समस्याएं एक नए मुल्क के साथ होती हैं वो सभी समस्याएं पाकिस्तान के हिस्से में भी आईं थीं. लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो इसमें कोई शक-ओ-शुबहा की गुंजाइश नहीं रहती कि पाकिस्तान ने पिछले 68 साल में एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है. चाहे वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैदान हो या आर्थिक क्षेत्र, पाकिस्तान ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है. आज पाकिस्तान जहां एक न्यूक्लियर पॉवर है, वहीं पाकिस्तानी सेना यूएन शांति मिशन में दूसरी सबसे बड़ी भागीदार है. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग की पहचान पूरी दुनिया में है. भारतीय महिलाओं में पाकिस्तानी लॉन (एक किस्म का लिबास) बहुत लोकप्रिय है. भारत की महिलाएं चाहती हैं कि अधिक से अधिक लॉन यहां पर आए. पाकिस्तान ने पिछले सालों में बहुत तरक्की की, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि उसकी तमाम समस्याएं खत्म हो गई हैं. एक नए मुल्क की हैसियत से हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ उस वक्त तक विकास नहीं कर सकता जब तक अपने पड़ोसियों के साथ उसके संबंध बेहतर न हों.

भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत और बाकी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर हों. भारत के साथ पाकिस्तान के कुछ बुनियादी मसले हैं. मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि आपसी संबंध बेहतर हों. एक दूसरे का भरोसा हासिल कर सकें, लेकिन यह सब बातों से नहीं होगा. वास्तविकता के आधार पर इस संबंध को देखना होगा और फिर सोचना होगा कि दोनों देश किस तरह अपनी समस्याओं को हल करें, अपने झगड़ों को समाप्त करें ताकि आपसी भरोसे का माहौल तैयार हो.

मेरे ख्याल में सिर्फ बेवकूफ लोग ही अब यह सोच सकते हैं कि जंग भारत और पाकिस्तान के बीच मसलों का हल है. तो अब सवाल यह उठता है कि अगर जंग मसले का हल नहीं हो सकती और अगर अमन और शांति दोनों देशों के हित में है तो दोनों देशों के बीच की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? इस का जवाब यह है कि हमें अपनी समस्याओं को सिर्फ बातचीत के जरिए ही हल करना है. पिछले साल 9-10 दिसम्बर को भारत

पाकिस्तान और भारत जब अपने संबंधों को सामान्य कर लें तो फिर कोई वजह नहीं है कि कुछ ही सालों में उनकी गिनती दुनिया के विकसित देशों में न हो. यह दक्षिण एशिया की बदकिस्मती है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां किसी तरह की आर्थिक एकीकरण और सहयोग नहीं है. यूरोपियन यूनियन के देशों में आपस का व्यापार तकरीबन 60 फीसद है, आसियान में आपसी व्यापार 30-35 फीसद है और नाफ्टा (नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) में 25 फीसद से ज्यादा है, लेकिन सार्क देशों का आपसी व्यापार केवल 5 फीसद है.

की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान के दौरे पर गईं. उस दौरान पाकिस्तान और भारत के बीच एक सहमति बनी कि हमें अब बातचीत का सिलसिला शुरू करना है. इसके बाद 25 दिसम्बर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक छोटे से दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए और जिसमें यह तय किया गया कि बातचीत की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए. बदकिस्मती से 2 जनवरी को पठानकोट की घटना हो गई, और बातचीत की जो प्रक्रिया 15 जनवरी को विदेश सचिव एस जयशंकर के दौरे से शुरू होनी थी वह शुरू नहीं हो पाई. आज पठानकोट (हमले) के बाद तकरीबन पांच माह का समय बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरम्यान बाकायदा डायलॉग शुरू नहीं हो पाया है. उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत की यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

दुर्भाग्यवश सार्क, जिसकी बुनियाद 1985 में रखी गई थी, अपना मकसद हासिल नहीं कर पाया है. अगर इस इलाके को अपनी आर्थिक क्षमता और सामर्थ्य पूरा करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत अपने आपसी मसले हल करें और एक नए दौर की शुरुआत करें. इसके अतिरिक्त और भी कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना करना है. चाहे वह दहशतगर्दी का मसला हो, पर्यावरण से संबंधित जलवायु परिवर्तन का मसला हो, पानी की समस्या हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, इन सभी के ग्लोबल डायमेंशन (वैश्विक आयाम) हैं. अगर इन मसलों को हल करना है तो भारत और पाकिस्तान, जो इस क्षेत्र के दो बड़े देश हैं, को मिल-बैठकर इनका हल तलाश करना होगा. चाहे जिस नज़रिए से देखा जाए भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों से जहां इन दोनों देशों को फायदा पहुंचेगा, वहीं इस पूरे क्षेत्र को भी फायदा होगा और सिर्फ इस क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलेगा.

पाकिस्तान और भारत जब अपने संबंधों को सामान्य कर लें तो फिर कोई वजह नहीं है कि कुछ ही सालों में उनकी गिनती दुनिया के विकसित देशों में न हो. यह दक्षिण एशिया की बदकिस्मती है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां किसी तरह की आर्थिक एकीकरण और सहयोग नहीं है. यूरोपियन यूनियन के देशों में आपस का व्यापार तकरीबन 60 फीसद है, आसियान में आपसी समस्याओं को अपने मसलों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं? उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि दोनों तरफ की ख्वाहिश है कि संबंध बेहतर हों. और अगर अच्छे संबंधों की ख्वाहिश दोनों तरफ है, तो इस ख्वाहिश को जल्द ही अमली जामा पहनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इसमें देर होती जाएगी, नुकसान हमारा ही होगा. तो अब वक़्त आ गया है कि हम एक फोकस तरीके से आगे बढ़ें और अपने मसलों, अपने झगड़ों को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करें.

कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए
पानी अब तो सर से गुज़र जाना चाहिए.

(लेखक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

मजबूत विपक्ष की जरूरत

जब तोप मुकाबिल हो अंक 30 से 5 मई 2016 में विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात बताई गई है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सेहरा राहुल गांधी के सिर जाता है, हारती है तो वह पार्टी की सामूहिक हार होती है. यही बात इस चुनाव में भी कही जा रही है. हालांकि कांग्रेस का यह अपना मामला है कि वह किसे अपना अध्यक्ष बनाए या किसे न बनाए. लेकिन कांग्रेस अगर राजनीतिक परिदृश्य से हटेगी या कमजोर होगी तो यह देश के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बात होगी. लोकतंत्र में सत्तापक्ष के मुकाबले विपक्ष भले ही कमजोर हो लेकिन विपक्ष होना चाहिए. पर ऐसा विपक्ष भी अपनी साख खो देता है जो जनता से जुड़े सवाल नहीं उठाए और उन सवालों को देश का सवाल बनाने की कोशिश करे जिन सवालों को सत्ताधारी दल सवाल बनाने में रुचि दिखाता है.

–शिव कुमार, *फैजाबाद, उत्तर प्रदेश*

मोदी की चुनौती

चौथी दुनिया में प्रकाशित लेख 2019 में मोदी को पहले से अधिक मेहनत करनी होगी में कमल मोरारका ने सही कहा कि तीन साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में इन राज्यों के चुनाव परिणाम का कोई लेना-देना है. इन परिणामों से अगर कोई संकेत निकलता है तो यह कि पश्चिम बंगाल में ममता और केरल में वाममोर्चा के जीतने के तीन साल बाद लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पहले से कहीं अधिक मेहनत करनी होगी. साथ ही 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद ही कोई व्यक्ति 2019 के लोकसभा चुनाव की पूर्व समीक्षा कर सकता है.

–फिरोज आलम, *कानपुर, उत्तर प्रदेश*

पानी के लिए मारामारी

मैं चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. झारखंड में पानी के लिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है. प्रत्येक जिले, प्रखंड, पंचायत, गांव और नगर निगम के क्षेत्रों में पानी के लिए मारपीट की घटनाएं आएदिन हो रही हैं. पानी को लेकर मामला थाने में दर्ज भी हो रहा है. इसके बाद भी मंत्री और अधिकारी सिर्फ आम लोगों को बरगलाने में लगे हैं. किसी जिले में पानी के मद में जितनी भी योजनाएं पास हुई हैं, उसमें से एक भी धरातल पर कहीं नहीं दिखती हैं.

–अभिनव कुमार, *धनबाद, झारखंड*

शादी समारोह में फायरिंग पर लगे रोक

मुंडन, तिलक और शादी-विवाह जैसे मांगलिक समारोहों में फायरिंग किए जाने की मनाही है. सरकार ने स्पष्ट रूप से ऐसे समारोह के अवसर पर फायरिंग पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन लोगों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है. वे मानने को तैयार नहीं हैं. तीसरे-चौथे दिन

अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है कि अमुक गांव या शहर में हर्ष फायरिंग में कई लोग हताहत हो गए. इस फायरिंग में कई बार तो निर्दोष लोगों की जान भी चली जाती है. सरकार इसके लिए कन्या पक्ष और वर पक्ष को जिम्मेदार मानकर दोषी लोगों को जेल भेजे एवं दोषी व्यक्तियों के हथियारों का लाइसेंस रद्द हो. सख्ती बरतने पर ही इस खतरनाक परंपरा पर रोक लगाई जा सकती है.

–राजकिशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

पॉलीथिन बैन का असर नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसके बावजूद बाजार में पॉलीथिन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है. ऐसे प्रतिबंध का क्या मतलब है? पॉलीथिन के प्रयोग पर सरकार ने भारी-भरकम जुर्माना भी लगा रखा है. इसके बावजूद हालात किसी से छिपे नहीं हैं. आस-पास चारों तरफ बिखरा कूड़ा और पॉलीथिन सरकार की लापरवाही की पोल खोल रहे हैं. अखिलेश सरकार के इस प्रतिबंध को असफल बनाने में व्यापारियों और दुकानदारों से पुलिस वालों की मिलीभगत है. प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है. इसलिए इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है. जरूरत है आम लोगों को भी जागरूक होकर पॉलीथिन का प्रयोग बंद करने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की.

–विशाल सिंह, *नोएडा, उत्तर प्रदेश.*

कुलपति का अजीबोगरीब फैसला

शिक्षा के लिए सुर्खियों में रहने वाला बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय इन दिनों कुलपति साहब के अजीबोगरीब फैसले के लिए चर्चा में है. एक तरफ तो सजायाफ्ता व्यक्ति की बहाली की जा रही है, वहीं कोर्ट से बरी होने के बाद भी वहां के विजिटिंग प्रोफेसर संदीप पांडेय को ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है. कुलपति महोदय नियम-कानूनों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं. पांडे पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था. घपलेबाजी का अड्डा शीर्षक लेख में बीएचयू में जारी इन धांधलियों को प्रमुखता से उठाया गया है. आज बीएचयू से निकले छात्र वहां के शैक्षणिक हालात देखकर दुखी हैं. हालांकि पूरी उम्मीद है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बहाली के लिए सरकार अक्षम अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई करेगी.

–मंजूनाथ, *इलाहाबाद, यूपी*

सपा में कलह

चौथी दुनिया में प्रकाशित लेख सपा की बेचैनी, बेनी को फायदा राज्यसभा की लिस्ट फाइनल करने में सपा नेतृत्व ने राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव और अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खान की नाराजगी का कतई ध्यान नहीं रखा. इससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि आने वाले समय में खास तौर पर विधानसभा चुनाव के समय रामगोपाल और आजम खान की क्या वकत रहने वाली है. रामगोपाल और आजम दोनों ने ही अपने-अपने अंदाज में पार्टी नेतृत्व का विरोध किया, लेकिन मुलायम पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा.

–किशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राज्यसभा को उसका पुराना गौरव लौटाना आवश्यक है

राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन राज्यसभा चुनावों का कोई औचित्य समझ में नहीं आता. अब तो राज्यसभा का ही औचित्य समझ में नहीं आता. क्योंकि, राज्यसभा ज्यादातर उन लोगों के लिए बसेरा बन गई है, जो सरकार से काम निकलवाने में माहिर हैं. उन लोगों के लिए भी अड्डा बन गई है, जिनके पास अपार कालाधन है और जो अपने लिए सम्मान खरीदना, राज्यसभा के सदस्य का सम्मान, बहुत बड़ी बात मानते हैं. राज्यसभा सीटें, सुनते हैं कि काफी धन लेकर लोगों को दी जाती है. पहले यह धन पार्टी के खाते में जाता था, अब यह धन पार्टी नेताओं के व्यक्तिगत खाते में जाता है.

राज्यसभा का उद्देश्य यह था कि लोकसभा अगर कोई चूक करती है, कोई गलती करती है, कोई चीज छोड़ती है या किसी चीज को अनावश्यक बढ़ाती है, वैसे बिल को राज्यसभा चेक करे, उस पर विचार करे और लोकसभा को सुझाव के साथ लौटा दे. राज्यसभा पहले इस काम को करती थी. लेकिन, उन दिनों राज्यसभा में भूपेश गुप्ता हुआ करते थे, उन दिनों राज्यसभा में राजनारायण हुआ करते थे, उन दिनों राज्यसभा में चंद्रशेखर हुआ करते थे. यह ऐसे लोग थे, जो देश की समस्याओं के ऊपर गंभीरता से विचार करते थे और सवाल उठाते थे. राज्यसभा के पुराने सदस्यों के फैसले देखने से ऐसा लगता है कि वो कितने बड़े राजनेता थे और देश की समस्याओं को कितनी गहराई से समझते थे.

चंद्रशेखर जी जब युवा तुर्क कहलाते थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. लेकिन उन्होंने राज्यसभा में जिस तरह से विड़ला के खिलाफ सवाल उठाए उसने इस देश के नौजवानों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया. चंद्रशेखर कभी डरे नहीं कि विड़ला के खिलाफ सवाल उठाने पर कहीं इंदिरा गांधी नाराज न हो जाएं.

राज्यसभा इसलिए भी कि राज्यसभा की एक दूसरी कल्पना भी है कि इस सदन में ऐसे लोग जाएं जो देश के बुद्धिजीवी हों, नाटककार हों, रंगकर्मी हों, संवेदनशील लोग हों, ताकि वो मानवीय नजरिए से लोकसभा के लिए हुए फैसलों की जांच-परख कर सकें. राज्यसभा में ऐसे लोगों को भी भेजे जाने की कल्पना थी, जो राजनीतिक दलों का काम तो करते हैं, पूरी तरह से पार्टी को खड़ा करने का काम करते हैं, लेकिन जिन्हें पार्टी खड़ी करने के लिए लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना होता है. ऐसे लोग राज्यसभा में जाएं और वहां से प्राप्त साधनों का इस्तेमाल पार्टी को बढ़ाने में करें, लोगों के बीच पार्टी की साख बढ़ाएं. लेकिन यह सिर्फ बीते जमाने की कल्पना थी. आज ऐसा कुछ नहीं होता.

आज राज्यसभा में बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ, संवेदनशील लोगों की जगह, ऐसे लोग जाने की कोशिश करते हैं, जो जिंदगी में कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते. जिन्हें जनता को समझाना नहीं आता है, वो राज्यसभा में दांवपेंच लगा, तिकड़में लगा, अपने लिए पार्टी का टिकट या किसी भी पार्टी का वोट जुगाड़ लेते हैं. शायद, इसीलिए आज राज्यसभा के बारे में आम धारणा यह है कि यह सत्ता के दलालों का सबसे सुरक्षित स्थान बन गई है.

कर्नाटक से खबर आई है कि वहां पर एक वोट सात करोड़ रुपये देकर खरीदा गया है. और, मैं जब यह लिख रहा हूं तो यह कोई रूपक नहीं है. कर्नाटक में हर व्यक्ति को मालूम है कि कौन पूंजीपति सात करोड़ रुपये में वोटों की बोली लगा रहा है. दो से तीन करोड़ रुपये प्रति वोट का दांव बहुत सारी जगह

आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल ऐसे चुनाव सुधार हों, जिसमें धन का, तिकड़म का, दलाली का या फिर बंदूक का कोई रोल न हो. देश के लोग लोकतंत्र के प्रति, इस देश के राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं से ज्यादा गंभीर हैं. वो लोकतंत्र को अपनी समस्याओं की हल की चाभी मानते हैं. लेकिन, लोगों की राय एक तरफ, राजनीतिक नेताओं की राय दूसरी तरफ. वह जो दूसरी तरफ राय रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ही हर चुनाव का माहौल बना दिया है. आज राज्यसभा का वह उद्देश्य समाप्त हो गया है, जिसकी कल्पना हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने की थी.

लगता दिखा रहा है. उत्तर प्रदेश में एक महिला मुंबई से आती है और खड़े होकर विधायकों को सीधे पैसे का प्रलोभन देती है. यह सारी बातें हम किसके लिए लिख रहे हैं.

मैं फिर दोहराता हूं कि सारी बातें आखिर हम लिख किसके लिए रहे हैं. क्या इलेक्शन कमीशन को इस बारे में नहीं पता? क्या राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ नेताओं को इस बारे में नहीं पता? क्या राष्ट्रपति को इसके बारे में नहीं पता है? अगर नहीं पता है, तो इस देश के उन भोले भाले लोगों को, जो हर चुनाव को बड़ी आशा से देखते हैं और यह मानते हैं कि शायद इस चुनाव के बाद उनकी समस्याओं का कोई हल निकले, पर ऐसा होता नहीं है.

आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल ऐसे चुनाव सुधार हों, जिसमें धन का, तिकड़म का, दलाली का या फिर बंदूक का कोई रोल न हो. देश के लोग लोकतंत्र के प्रति, इस देश के राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं से ज्यादा गंभीर हैं. वो लोकतंत्र को अपनी समस्याओं की हल की चाभी मानते हैं. लेकिन, लोगों की राय एक तरफ, राजनीतिक नेताओं की राय दूसरी तरफ. यह जो दूसरी तरफ राय रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ही हर चुनाव का माखौल बना दिया है. आज राज्यसभा का वह उद्देश्य समाप्त हो गया है, जिसकी कल्पना हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने की थी. अब, सदन में हीरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, ज्योतिर्मय बसु, राजनारायण और चंद्रशेखर जैसे लोग शायद कभी न दिखें. उस स्तर की बहस शायद कभी न हो, क्योंकि अब राज्यसभा थके हारे, विचारविहीन और गैरसमझदार लोगों का घर बन गया है. लेकिन, अभी भी राज्यसभा में ऐसे लोग हैं जो कभी-कभी राज्यसभा में चमत्कार दिखा देते हैं. पर, यह अपवाद होता है. राज्यसभा को उसके पुराने रूप में लौटाना अतिआवश्यक है और इस रूप में लाने की जिम्मेदारी आज तो राजनीतिक दलों की भी है. पता नहीं कब वो अपनी चूक को समझेंगे और अपनी इस गलती को सुधारेंगे. ■

editor@chauthiduniya.com

असम की जीत भाजपा के लिए उत्साहजनक

मेघनाद देसाई

किसी सरकार के लिए पिछला समय प्रस्तावना की तरह होता है. यह समय बताता है कि कौन-कौन से कार्य हो चुके हैं और कितने काम किए जाने हैं. यह समय प्रधानमंत्री को उनके कमज़ोर और मज़बूत पक्ष से भी अवगत कराता है. विदेशों में भारत की एक बेहतर छवि के निर्माण में कामयाबी मिली है. लुक ईस्ट पॉलिसी, पाकिस्तान के साथ संबंध, चाबहार की चुनौती, इन सभी मोर्चों पर मोदी की छाप नज़र आती है. लगातार दो वर्ष के सूखे के बावजूद अर्थव्यवस्था मज़बूत है. यहां तक कि महंगाई दर, खास तौर पर प्याज और दालों की कीमतों ने हेडलाइंस नहीं बटोरा है.

दिल्ली में अति आत्मविश्वास और बिहार में गलत रणनीति के कारण मिली हार के बाद असम की जीत पार्टी के उत्साह को बहाल करेगी. मोदी एक विजेता हैं. असम में अमित शाह ने पार्टी के अंदर के सांस्कृतिक योद्धाओं को व्यवस्थित रखा जिसने उनकी जीत सुनिश्चित कर दी. इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखने को था. बहरहाल नवनिर्वाचित सरकार को एक विश्वास है कि लोकसभा में बहुमत कानून निर्माण की गारंटी है. लेकिन कानून निर्माण राज्यसभा के सदस्यों की मर्ज़ी पर निर्भर हो जाता है. सरकार को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि बहुत अच्छी स्थिति में भी 2019 से पहले राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने वाला है. दिल्ली की राजनीति में प्रधानमंत्री की अनुभवहीनता साफ दिखती है. एक आउटसाइडर की हैसियत से उन्होंने संसदीय प्रक्रिया को अक्षरश: अपना लिया. भारत में संसद संख्या बल पर नहीं बल्कि सौदेबाजी करने की क्षमता पर चलती है. वर्ष 1989 के बाद की चार सरकारें जिन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल पूरे किए और जिनके पास बहुमत नहीं था, उन सरकारों ने समझौता करके ही अपना अस्तित्व बचाया. लेकिन मोदी को समझौता करने में भ्रष्टाचार की बू आती है. लिहाज़ा अनुभवी खिलाड़ियों के दांव-पेंच सीखने में बहुत सारा कीमती वक़्त खर्च हो गया.

दिल्ली में अति आत्मविश्वास और बिहार में गलत रणनीति के कारण मिली हार के बाद असम की जीत पार्टी के उत्साह को बहाल करेगी. मोदी एक विजेता हैं. असम में अमित शाह ने पार्टी के अंदर के सांस्कृतिक योद्धाओं को व्यवस्थित रखा जिसने उनकी जीत सुनिश्चित कर दी. इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखने को था. बहरहाल नवनिर्वाचित सरकार को एक विश्वास है कि लोकसभा में बहुमत कानून निर्माण की गारंटी है. लेकिन कानून निर्माण राज्यसभा के सदस्यों की मर्ज़ी पर निर्भर हो जाता है. सरकार को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि बहुत अच्छी स्थिति में भी 2019 से पहले राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने वाला है.

यही बात कार्यपालिका के लिए भी कही जा सकती है. किसी सूबे का मुख्यमंत्री तानाशाह हो सकता है, जबकि एक प्रधानमंत्री को उसकी कैबिनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है. मोदी ने अपनी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए नौकरशाहों पर बहुत अधिक भरोसा कर लिया. भारत में नौकरशाही कार्यकुशल तो ज़रूर है, लेकिन सुस्त है. सरकार को यह समझने में दो साल लग गए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मज़बूत करने की ज़रूरत है और इसके लिए निजीकरण बेहतर विकल्प है. लेकिन मोदी एक मॉडरेट कंज़र्वेटिव (मध्यम श्रेणी के अपरिवर्तनवादी) हैं. कीमतों में मंद गति से वृद्धि हो रही है और उत्पादन क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है, जिसका कारण यह है कि सरकार ने लेबर लॉ में बदलाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई है.

जहां तक लोकप्रियता का सवाल है मोदी अब भी पहले पायदान पर हैं, इसके बावजूद बदलाव की सुस्त रफ़्तार के कारण चारों ओर निराशा है. प्रधानमंत्री ने कई पहल की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विरासत में मिली व्यवस्था में अभी भी क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता है.

मोदी सरकार के पास अब केवल 1092 दिन शेष हैं. अगर सूखे की स्थिति से छुटकारा हासिल कर लिया जाता है, तो उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. सुरेश प्रभु और नितिन गडकरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित कर रहे हैं. वहीं पीयूष गोयल को बिजली की समस्या और रविशंकर प्रसाद को संचार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान एक साल के भीतर ही कर लेना चाहिए था. मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्वच्छ भारत और सरकार द्वारा शुरू किए गए दूसरे सामाजिक पहल जल्द परिणाम देना शुरू कर देंगे. अनुमान है कि विकास का दर अगले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत से ऊपर होगा.

सरकार को अब यह ज़रूर अहसास हो जाना चाहिए कि कानून पारित कराने के लिए केवल बहुमत ही नहीं बल्कि सदिच्छा (गुडविल) की भी ज़रूरत होती है. उसे कांग्रेस को लेकर बेवजह चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है अन्य दलों से समर्थन हासिल करने की. रघुराम राजन को हटाने के लिए जो ख़तरनाक आवाजें उठ रही हैं उनसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. स्थानीय व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सामर्थ्य और वैश्विक बाजार का अर्थव्यवस्था में विश्वास. आप उन्हें एक्सटेंशन का प्रस्ताव दें और वह उसे स्वीकार कर लें. उसके बाद एक बड़े बहुमत के साथ आपका पुनर्निर्वाचित होना तय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस की कार्रवाई से नाख़ुश जनता

मगध में बढ़ता जनाक्रोश

गया जिले के डुमरिया प्रखंड के काचर पंचायत की निवर्तमान मुखिया के पति और प्रखंड लोजपा के अध्यक्ष सुदेश पासवान और उनके चचरे भाई सुनील पासवान की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई. दोनों चचेरे भाई पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हथियारबंद माओवादियों ने दोनों भाईयों को गोली मार कर फरार हो गए. इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर आ गया और लोगों ने जमकर बवाल मचाया.

सुनील सौरभ

पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला और भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली कहा जाने वाला मगध क्षेत्र आज अशांत है. मगध में प्रशासन और सत्ता की कार्यशैली से लोगों की नाराजगी जनाक्रोश का रूप ले चुकी है. इस बढ़ते जनाक्रोश की वजह से इस पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी गई हो गई है. स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के काफिले पर हमला बोल दिया और वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित लोगों की भीड़ देखकर पुलिसवाले थाना में ताला लगाकर भाग खड़े होते हैं. इस जनाक्रोश के पीछे बिहार पुलिस की कार्यशैली और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों की नाराजगी मुख्य वजह है. मगध प्रमंडल के मुख्यालय गया में एक सप्ताह के अंदर घटित तीन घटनाओं और लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से कार्रवाई की वजह से लोगों का गुस्सा सड़क पर आया.

गया जिले के डुमरिया प्रखंड के काचर पंचायत की निवर्तमान मुखिया के पति और प्रखंड लोजपा के अध्यक्ष सुदेश पासवान और उनके चचरे भाई सुनील पासवान की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई. दोनों चचेरे भाई पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हथियारबंद माओवादियों ने दोनों भाईयों को गोली मार कर फरार हो गए. इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर आ गया और लोगों ने जमकर बवाल मचाया. उसके दूसरे दिन सुबह क्षेत्र के विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का काफिला डुमरिया पहुंचा, तो देर से पहुंचने की वजह से आक्रोशित लोगों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया और उनकी एस्कॉर्ट जीप में आग लगा दी. इस दौरान लोगों ने सीआरपीएफ जवानों की दो बाइक को भी फूंक दिया. पत्थरबाजी में गया के एएसपी अभियान मनोज यादव सहित पांच पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के वाहन को ड्राईवर ने किसी प्रकार पास के सीआरपीएफ कैम्प में ले जाकर लगाया, जिससे उनकी जान बची. लोगों का कहना था कि सूचना देने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री देर से मृतक के परिजनों को सांत्वना देने आए थे. जबकि सुदेश पासवान विधानसभा चुनाव में जीतनराम मांझी के चुनाव एजेंट रह चुके थे. पुलिस सुदेश पासवान और सुनील पासवान की हत्या को नक्सली घटना मान रही है. जबकि किसी नक्सली संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. हालांकि मृतक लोजपा नेता की पत्नी ने राजद नेता रामसरेख यादव तथा उसकी पत्नी समेत कई अन्य लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है. रामसरेख यादव की पत्नी उर्मिला देवी, इसी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी थी. पिछले डेढ़ दशक में सुदेश पासवान एक बड़े नेता के रूप में डुमरिया में उभरे थे. 2001 में डुमरिया प्रखंड के उपप्रमुख बन चुके थे. पत्नी को बाद में अपने पंचायत से मुखिया भी बनवा दिया था. प्रखंड में सुदेश के बढ़ते राजनीतिक कद को देखते हुए माओवादियों तथा उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनको अपने निशाने पर ले रखा था. इस घटना के पीछे चुनावी रंजिश के साथ ही बड़े राजनीतिक नेताओं का हाथ होने से इंकार नहीं किया जा सकता. क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर अपने ही क्षेत्र में लोगों द्वारा हमला किए जाने की बात लोग असानी से नहीं पचा पा रहे हैं. इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, प्रशासन के वरीय पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी जानते हैं, लेकिन इस मामले पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. इसकी प्रकार मई के महीने में ही शेरघाटी थाना के अन्तर्गत आने वाली मोरहर नदी में अवैध खनन से हुए गड्ढे के पानी में डूबने की वजह से कठार गांव के दो बच्चों की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई और नदी में बालू उठा रहे वेस्ट लिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चार ट्रक, तीन हाइवा, दो पोकलेव मशीन और एक ट्रैक्टर को फूंक डाला. सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर भी आक्रोशित भीड़ ने हमला कर दिया और पुलिस की जीप को फूंक दिया. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. इन दोनों ही घटनाओं से करोड़ों की क्षति हुई, लेकिन सवाल यह है आखिर लोगों के आक्रोशित होने की वजह क्या है? पुलिस इस बात को आज भी नहीं समझ पा रही है. मोरहर नदी में बालू का खनन दस फीट तक करना है. प्रशासन का कहना है कि साढ़ नौ फीट बालू के गड्ढे में वर्षा का पानी जमा हो गया था और इसी गड्ढे में कठार गांव के बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई. लेकिन परिजनों का आरोप है कि इन बच्चों की मौत डूबने से नहीं, बल्कि बालू उठाते समय जेसीबी से दब जाने की वजह से हुई है. इसी प्रकार बथानी अनुमंडल थाने को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और थाना अध्यक्ष समेत सभी पुलिस कर्मी थाने में ताला लगाकर भाग खड़े हुए. वजह यह थी कि थाना क्षेत्र के बंडी बाजार में दुकानदार के द्वारा पान का पैसा मागने पर दो लोगों ने जमकर फायरिंग की. फायरिंग करने वाले शकील खां और वकील खां का क्षेत्र में आतंक है. जनवरी के महीने में पूर्व मुखिया खलील मियां की हुई हत्या का आरोप भी इन दोनों पर ही है. लोगों ने जब थाने में जाकर इन दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाही, तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. लोगों का आरोप है कि डीएसपी आरोपियों की मदद कर रहे हैं. पुलिस के असहयोग और दबंगों के बढ़ते अत्याचार की वजह से जब लोग परेशान हो गए, तो हजारों की संख्या में बथानी थाना पहुंच कर थाने का घेराव कर दिया. कई घंटे तक लोग थाना परिसर में ही बैठे रहे, लेकिन लोगों की समस्या को सुनने के लिए कोई भी पुलिस पदाधिकारी नहीं पहुंचा. यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली से लोगों में बढ़ती नाराजगी जनाक्रोश का रूप लेती जा रही है. आरोपियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की शिथिलता और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई मगध के लोगों को उग्र होने के लिए मजबूर कर रही है. इस जनाक्रोश का आम लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. ■

पुलिस सुदेश पासवान और सुनील पासवान की हत्या को नक्सली घटना मान रही है. जबकि किसी नक्सली संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. हालांकि मृतक लोजपा नेता की पत्नी ने राजद नेता रामसरेख यादव तथा उसकी पत्नी समेत कई अन्य लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है. रामसरेख यादव की पत्नी उर्मिला देवी, इसी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी थी. पिछले डेढ़ दशक में सुदेश पासवान डुमरिया के एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे.

feedback@chauthiduniya.com

www.iiher.org,
Mob. : 9386745004, 9204791696
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.

DEGREE COURSES

BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.

YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT

DIPLOMA COURSES :

DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate In Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/- only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

खगड़िया

महादलितों के साथ धोखा

आखिर पानी पर कैसे बने घर

> वर्ष 2009-10 में भी छह दर्जन महादलितों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया. इनमें भी कई ऐसे हैं, जिनके जमीन का विवरण या तो फर्जी है या उस जमीन पर उनका कब्जा नहीं है. ऐसी स्थिति में कई महादलित परिवार के लोग अपने लिए इंदिरा आवास नहीं बना पाए, अब उनकी गर्दन पर तलवार लटकने लगी है. इंदिरा आवास की राशि ऐसे परिजनों ने किसी दूसरे मद में खर्च कर दी. अब इंदिरा आवास का निर्माण आखिर हो तो कैसे?

राजेश सिन्हा

नीतीश सरकार ने भूमिहीन महादलितों व बीपीएल के उत्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराकर आशियाना सजाने का कार्यक्रम तो बनाया, लेकिन नौकरशाह व बिचौलियों के कारण महादलितों का सपना चकनाचूर हो गया. हालात ये हैं कि कहीं-कहीं नदियों के गर्भ की जमीन भी महादलितों को आवंटित कर इंदिरा आवास बनाने का फरमान जारी कर दिया गया. पीड़ित परिवार के लोगों ने कई बार पदाधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाई, जनता दरबार में भी हाजिरी लगाई, लेकिन उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह गई. नदियों के गर्भ की जमीन उपलब्ध कराने के पीछे नौकरशाहों की मंशा तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगी, लेकिन इस कदम ने सुशासन की हवा निकाल दी है. महादलित दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं. पटना में बैठे आला अधिकारियों ने मामले को गंभीर रूप लेता देख जांच के आदेश दे दिए. लेकिन वरीय पदाधिकारियों के आदेश का असर भी जिला स्तरीय पदाधिकारियों पर नहीं दिख रहा है. जब चौथी दुनिया ने इस मामले की जांच की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए. खगड़िया जिले के ओलापुर गंगौर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2008-09 में 300 लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत लाभान्वित किया गया था. लेकिन प्रशासनिक अक्षमता या बिचौलियों की करतूत के कारण लाभुकों को दिए गए एकरारनामे में जमीन का ब्योरा ही नहीं दिया गया. इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष 2009-10 में भी छह दर्जन महादलितों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया. इनमें भी कई ऐसे हैं, जिनके जमीन का विवरण या तो फर्जी है या उस जमीन पर उनका कब्जा नहीं है. ऐसी स्थिति में कई महादलित परिवार के लोग अपने लिए इंदिरा आवास नहीं बना पाए, अब उनकी गर्दन पर तलवार लटकने लगी है. इंदिरा आवास की राशि ऐसे परिजनों ने किसी दूसरे मद में खर्च कर दी. अब इंदिरा आवास का निर्माण आखिर हो तो कैसे?

> प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की गलती से ऐसी स्थिति पैदा हुई है. भूदान की जमीन को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है. भूदान की जमीन का पर्चा भूमिहीनों को देकर बसाने का प्रावधान है. इसके बावजूद तत्कालीन अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने करोड़ों रुपए के भूदान की जमीन का बागमती नदी के अस्तित्व की जमीन से बदलेन (अदल-बदल) कर दिया.

अनियमितता सामने आने के बाद ग्रामीण विकास विभाग पटना के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) ने (6 जुलाई 2011) को इस मामले की जांच का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंप दिया था. लेकिन जिलाधिकारियों ने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया. सवाल ये है कि एकरारनामे में अगर जमीन का विवरण नहीं था या अगर विवरण फर्जी था तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई. महादलित परिवार के अशिक्षित लोगों से यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि वे इन सरकारी प्रावधानों को समझें और नियम कानून के तहत विवरणी भरकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष जमा कर सकें. जाहिर है कि बिचौलियों ने महादलित परिवार के लोगों को ठगा और संबंधित अधिकारियों ने भी लाभुकों द्वारा जमा किए गए जमीन के विवरण पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा. बात सामने आने के बाद वर्तमान प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के सिर ठीकरा फोड़ रहे हैं. प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की गलती से ऐसी स्थिति पैदा हुई है. भूदान की जमीन को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है. भूदान की जमीन का पर्चा भूमिहीनों को देकर बसाने का प्रावधान है. इसके बावजूद तत्कालीन अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने करोड़ों रुपए के भूदान की जमीन का बागमती नदी के अस्तित्व की जमीन से बदलेन(अदल-बदल) कर दिया. वर्षों पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से सटे परमानंदपुर मौजे के करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को उजियार साह ने भूदान के तहत दान किया था. कई भूमिहीनों को पर्चा देकर इस जमीन पर आशियाना सजाने का आदेश भी दे दिया गया.

लेकिन जब इस जमीन की कीमत में काफी उछाल आ गया तब उजियार साह के पोते ने अंचलाधिकारी को मिलाकर इस जमीन का बदलेन बागमती नदी के अस्तित्व की जमीन से करा लिया. हद तो तब हो गई जब अंचलाधिकारी ने उजियार साह के पोते के नाम से भूदान के उक्त जमीन का नया जमाबंदी कायम करने का आदेश दे दिया . जबकि इसके पूर्व परमानंदपुर मौजे के राजस्वकर्मी ने स्पष्ट कर दिया था कि उजियार साह ने चार एकड़ आठ कट्ठा 19 धूर जमीन भूदान में दिया था. लेकिन भूदान की जमीन का बदलेन फरकिया स्थित बागमती की जमीन थाना नम्बर 189, खेसरा नंबर 02,08 एवं 98 से कर लिया गया है. जिला निबंधन कार्यालय के अभिलेख भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह बागमती के अस्तित्व की जमीन है. जिलाधिकारी साकेत कुमार का कहना है कि भूदान की उक्त जमीन एवं बदलेन की गई जमीन के बीच कोई तालमेल नहीं है. यह मामला गंभीर जांच का विषय है. वहीं तत्कालीन अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि पूर्व डीसीएलआर द्वारा पारित वाद संख्या 01.05. 2006 के आलोक में इस तरह का आदेश दिया गया.

खगड़िया जिले के साथ-साथ कोसी के विभिन्न प्रखंडों में भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे महादलितों के साथ कुछ ऐसा ही खेल खेला गया. सात नदियों से घिरे खगड़िया या कोसी में भूमि विवाद के कारण अब तक दर्जनों लोगों की जान गई है. सात वर्ष पूर्व खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड अंतर्गत अमौसी में नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया था और 11 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी. तब मुंगेर के डीआईजी ने स्वीकार किया था कि अगर पुलिस अधिकारी समय रहते भूमि विवाद का निपटारा कर लिए होते तो यह नरसंहार नहीं होता. नीतीश सरकार ने समय रहते अगर इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तो यह विपक्ष के हाथ में सरकार को घेरने के लिए मुद्दा बन सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छतीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

दांतों के टेढ़ेपन को नहीं करें इग्नोर करायें ईलाज

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. प्रभाकर सिंह राणा BDS
दन्त रोग विशेषज्ञ, सहरसा

सहरसा के मणिपाल डेन्टल क्लिनिक से डॉ. प्रभाकर सिंह राणा ने दांतों के टेढ़ेमेढ़ेपन के बारे में बताया कि बच्चों के दूध के दांत गिरने के बाद तक करीब 13साल तक दांतों के टेढ़ेमेढ़ेपन में स्वतः बदलाव आता है और सीधा होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस बीच डॉक्टर से सम्पर्क न करें। यदि दूध के दांत अपने आप नहीं टूट रहे हैं तो डॉक्टर से सम्पर्क करें शायद उसे निकलवाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि बच्चे में अंगूठा चूसने की आदत है तो यह इसे डिफोरमीटि को छुड़ाना आवश्यक है क्योंकि यह भी एक कारण है दांत के टेढ़ेमेढ़ेपन का। 13 साल के बाद तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप दांतों के डॉक्टर से सम्पर्क करें और इसका इलाज करवायें। डॉ. राणा का कहना है बच्चे हों या बड़े अच्छे लूक और स्वस्थ्य जीवन के लिए जरूरी है दांतो की सफाई । दांतों की सफाई पर ध्यान दें और दो टाईम ब्रश करें। आजकल अल्ट्रासोनिक ब्रश का प्रयोग कर बच्चों के दांतों की सफाई असानी से किया जा सकता है। डॉ. राणा का कहना है कि यदि बच्चे ब्रशींग में सहयोग नहीं करते हैं तो मां-बाप को चाहिए कि साफ सूती कपड़े से रात में सोने से पहले दांतों को साफ कर दें। ब्रशींग दो बार करवाने के अलावा बच्चों में हाथ धोने के वक्त अपनी अंगूलियों से मुंह के चारो ओर घुमाकर कुल्ला करना सिखायें। फल खाने से बच्चों के दांतों को शक्ति मिलती है इसलिए फल फ्रुट लाकर अवश्य दें टॉफी बिस्कूट या मेदे वाली चिजें खाने के बाद दांतों को साफ कर दें। ध्यान रहें कि छः महीने में एक बार अवश्य अपने दांतों के डॉक्टर के पास जायें।■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 13 और शहर होंगे स्मार्ट

स्मार्ट सिटी बनाम स्मार्ट पॉलिटी

स्मार्ट सिटी लखनऊ के स्मार्ट हजरतगंज में स्मार्ट जाम

कितने स्मार्ट हैं हम!

लखनऊ के स्मार्ट सिटी बनने के लिए चयनित होने के साथ ही आम लोगों में भी यह सवाल पैठ करने लगा है कि हम स्मार्ट सिटी के लायक हैं कि नहीं. हम स्मार्ट सिटी में रहने की काबिलियत रखने वाले स्मार्ट नागरिकों में शरीक हैं कि नहीं. इस सवाल के समेकित उत्तर में न की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है. शासन और प्रसासन की अपनी मुश्किलें हैं और उनके अपने दायित्व हैं. इसमें ट्रैफिक जाम का मसला हो सीवर जाम का. बिजली ठप्प होने का मसला हो या पानी सप्लाई ठप्प होने का. वगैरह-वगैरह. इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट तो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक मैनेजमेंट कैसे हो इसके लिए तो नागरिकों को ही समझदार होना होगा और स्मार्टनेस से काम लेना होगा. सड़कों के किनारे फुटपाथ घेरे दुकानदारों, सड़कों पर यत्र-तत्र-सर्वत्र थूकते-मूतते गंदगी फैलाते लोगों, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर तफरीह करते नागरिकों, कहीं भी कटिया लगा कर मुफ्त की बिजली जलाते लोगों और कहीं भी अतिक्रमण करके खुश हो रहे लोगों को आखिर कैसे मैनेज किया जाए और क्या इसके बगैर लखनऊ या कोई भी शहर स्मार्ट रह पाएगा? इन सवालों का एक पंक्ति में जवाब देते हैं लखनऊ शहर के महापौर व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. दिनेश शर्मा. शर्मा कहते हैं कि हर काम शासन और नगर निगम नहीं कर सकता, जब तक जनता का सहयोग न हो. ■

वैष्णवी वंदना

2017 के विधानसभा चुनाव में प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का स्मार्ट सिटी के रूप में बदलने के लिए चयनित होना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आप गौर करें तो स्मार्ट सिटी के शोर में राजनीतिक-मंशा का शातिराना मौन भी उतना ही गुंजायमान हो रहा है. विकास के बूते चुनाव लड़ने का खम ठोक रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दावे पर केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की बौछार समानान्तर असर ढा रही है. उत्तर प्रदेश के एक दर्जन से अधिक शहर अभी स्मार्ट सिटी होने की लाइन में हैं, संभव है कि चुनाव आते-आते यूपी के कई अन्य शहर भी स्मार्ट सिटी के शिगूफे में कस जाएं और सत्ताधारी दल उसमें कसमसा कर रह जाए. बिहार के दो शहर, झारखंड का एक शहर और उत्तर प्रदेश के 13 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुने जाते हैं, इसके पीछे यूपी की अधिक आबादी नहीं बल्कि यूपी का अधिक वोटर है और यहां चुनाव होना अभी बाकी है. स्मार्ट सिटी के मापदंडों से लखनऊ कितनी दूर है, यहां के नागरिक इसे भलीभांति जानते हैं और भोगते हैं. फिर वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद और रायबरेली जैसे शहर स्मार्ट सिटी कैसे बनेंगे, भगवान ही मालिक है. जो इन शहरों को जानते हैं या इन शहरों में रहते हैं, वे इन जगहों पर खुदा के सहारे ही रहते हैं. लिहाजा, अगर ये शहर (लखनऊ समेत) वाकई स्मार्ट सिटी बन जाएं तो यह साबित हो जाएगा कि अल्लाह मेहरबान है.

स्मार्ट सिटी की दूसरी खेप की फेहरिस्त जारी करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस पर जोर देकर कहा कि स्मार्ट सिटी एक मिशन है, राजनीति नहीं है. लेकिन ऐसा कह कर नायडू ने राजनीतिक बहस-मुबाहिसे को शक्ल तो दे ही दी. लखनऊ के स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित करने की भाजपा की तरफ से मुनादी पीटे जाने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव फौरन ही बोल पड़े कि सपा तो लखनऊ को पहले ही स्मार्ट सिटी बना चुकी है, फिर इसमें राजनीति छोड़ कर नया क्या है. लखनऊ में मेट्रो से लेकर गोमती के सौंदर्यीकरण व कई अन्य स्मार्ट योजनाओं का हवाला देते हुए शिवपाल ने कहा कि ये योजनाएं अब लखनऊ में ठोस शक्ल ले चुकी हैं और लोगों को विकास के ये काम सामने दिख रहे हैं, ऐसे में प्रदेश की जनता को भाजपा की राजनीति भी समझ में आ रही है. शिवपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के शहर वाराणसी की बदहाली देखें और उसे स्मार्ट सिटी बनाएं. हालांकि भाजपा पर प्रहार करते समय शिवपाल यह भूल गए कि उनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद ही यह बोल चुके हैं कि भाजपा वाले बड़े स्मार्ट हैं तो 73 सांसदों के बावजूद यूपी में एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी!

> स्मार्ट सिटी की दूसरी खेप की फेहरिस्त जारी करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस पर जोर देकर कहा कि स्मार्ट सिटी एक मिशन है, राजनीति नहीं है. लेकिन ऐसा कह कर नायडू ने राजनीतिक बहस-मुबाहिसे को शक्ल तो दे ही दी. लखनऊ के स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित करने की भाजपा की तरफ से मुनादी पीटे जाने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव फौरन ही बोल पड़े कि सपा तो लखनऊ को पहले ही स्मार्ट सिटी बना चुकी है, फिर इसमें राजनीति छोड़ कर नया क्या है.

बहरहाल, लखनऊ के स्मार्ट सिटी बनने की कतार में शामिल होने पर इसका श्रेय लेने और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की मंशा साफ-साफ समझ में आ रही है. लेकिन प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि इसी बहाने कबाड़ होते इन शहरों का कुछ भला हो जाए. हालांकि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना पर राज्य सरकारों को ही आधा खर्च करना है. यह भी स्पष्ट है कि चुनाव का माहौल गरमाने पर विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की बात कह कर भाजपा स्मार्ट सिटी का मुद्दा जरूर उठाएगी. राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं कि स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया के पहले चरण में लखनऊ का बाहर हो जाना और फिर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए दोबारा चयनित हो जाना सियासी इरादे का ही नतीजा है. इसी के जरिए भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश की सत्ता का उपभोग करने वाली पार्टियों ने डेढ़ दशक में गांव तो दूर लखनऊ जैसे महानगर तक के विकास के लिए कुछ नहीं किया. इसके साथ ही भाजपानीत केंद्र सरकार ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वह उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर इतनी चिंतित है कि राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी में चयनित कराने के लिए उसने पुरानी प्रक्रिया बदल कर फास्ट ट्रैक की नई प्रक्रिया इंट्रोड्यूस की. चुनाव सामने है तो लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के पीछे भाजपा के अपने राजनीतिक निहितार्थ तो रहे ही होंगे. लखनऊ देश के गृहमंत्री और मोदी कैबिनेट में नंबर दो का रुतबा रखने वाले राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है. लखनऊ नगर निगम पर भाजपा का पिछले लगभग 20 सालों से कब्जा है. लखनऊ भाजपा के शीर्ष नेता व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी संसदीय क्षेत्र रहा है.

मेरठ और रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के मामले में भी भाजपा की राजनीति साफ-साफ दिखती है. केंद्र ने मेरठ और रायबरेली दोनों को ही स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल कर यह संदेश दिया है विकास की कसौटी और लोगों की सुविधा के नाम पर केंद्र सरकार कोई सियासत नहीं करना चाहती. रायबरेली भले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र क्यों न हो. केंद्र ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 13 शहर मांगे थे लेकिन सपा सरकार ने 14 शहरों के नाम भेज कर राजनीति चाल चली थी. लेकिन केंद्र ने 14वें शहर को भी शामिल कर सपाई चाल को धराशाई कर दिया. केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए शहरों के मूल्यांकन के लिए 15 मापदंड तय किए थे. इसके आधार पर क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र(आरसीयूईएस) ने एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले यूपी के 60 शहरों का आकलन कराया था. इसमें कुल 13 शहर ही स्मार्ट सिटी बनने लायक पाए गए थे. रायबरेली व मेरठ को समान अंक मिला था. इस वजह से इन दोनों शहरों के बीच टाई हो गया था. हालांकि केंद्र ने राज्य सरकार से दोनों में से किसी एक शहर का नाम भेजने को कहा था लेकिन राज्य सरकार ने दोनों के नाम भेज दिए थे. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रायबरेली और मेरठ को भी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए लायक शहर मानते हुए प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति दे दी. लिहाजा अब यूपी के 14 शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हो गए हैं. हालांकि, अंतिम चयन दूसरे चरण के मूल्यांकन के बाद ही होगा. राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र के निर्णय के बाद रायबरेली और मेरठ के लिए भी स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सम्बन्धित निकायों से कह दिया गया है. अन्य 11 शहरों के साथ ही इन दोनों शहरों का प्रस्ताव भी 30 जून तक तैयार कर केंद्र को भेज दिया जाएगा. ■

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल

feedback@chauthiduniya.com

जनसूचना क़ानून को ठेंगा

संतोष देव गिरि

जनसूचना अधिकार कानून को भले ही सशक्त और प्रभावशाली बनाने की बात होती हो, लेकिन हकीकत यह है कि खुद अधिकारी ही इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला पूर्वांचल के जौनपुर जिले की केराकत तहसील क्षेत्र का है. केराकत तहसील क्षेत्र के तरियारी गांव निवासी अमित कुमार ने जनसूचना अधिकार कानून के तहत17 दिसंबर 2015 को ही ग्राम पंचायत तरियारी में सम्पन्न ग्राम प्रधान के चुनाव में श्रीमती शीला की जीत से सम्बन्धित ब्यौरा मांगा था, जिसे आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया. इस मामले को लेकर वह केराकत के उपजिलाधिकारी सहित खंड विकास अधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय में भी फरियाद लगा चुके हैं.

अमित कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के जनसूचना अधिकारी से भी यह जानकारी मांगी थी. उसके जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि जौनपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना देने के लिए अंतरित किया गया है. लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जौनपुर कार्यालय ने आयोग के साथ-साथ जिलाधिकारी के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया. केराकत के उपजिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी को जानकारी देने के लिए कहते हैं तो वह इस आदेश को नहीं मानते. वो कहते हैं कि हमारे यहां कोई ऐसा अभिलेख ही नहीं है. समझा जा सकता है कि शासन-प्रशासन के अधिकारी सूचना अधिकार कानून के प्रति कितने गंभीर और सजग हैं. केराकत के उप जिलाधिकारी सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव से मुलाकात कर अमित कुमार ने जानकारी मांगी तो वे बिफर पड़े और बोले, दूसरे से मांगो, मैं तो नहीं देता सूचना! थके हारे अमित कुमार ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव समेत कई मंत्रियों को इस बारे में लिखा है. जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बरती जा रही हीला-हवाली तथा अधिकारियों के रवैये से नाराज़ होकर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है. ■

> अमित कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के जनसूचना अधिकारी से भी यह जानकारी मांगी थी. उसके जवाब में राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि जौनपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना देने के लिए अंतरित किया गया है. लेकिन कोई जवाब नहीं आया. जौनपुर कार्यालय ने आयोग के साथ-साथ जिलाधिकारी के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया. केराकत के उपजिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी को जानकारी देने के लिए कहते हैं तो वह इस आदेश को नहीं मानते.

अवैध खदान में खनन करते पांच मज़दूरों की मौत पर शासन-प्रशासन ख़ामोश

सीएम के भाई का साला तो सबके मुंह पर ताला

अखिलेश यादव के सांसद भाई धर्मेंद्र यादव के साले पुष्पेंद्र यादव का बुंदेलखंड में अवैध खनन पर वर्चस्व है

इसरार पठान

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सांसद भाई धर्मेंद्र यादव के साले पुष्पेंद्र यादव के हाथ में बुंदेलखंड के अवैध खनन की बागडोर है. खनन क्षेत्र में मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं बल्कि पुष्पेंद्र है. प्रशासन पुष्पेंद्र और उसके गिरोह के आगे नतमस्तक है. महोबा के गौरहारी में जिस अवैध खनन में खदान दरकने से पिछले दिनों पांच मजदूरों की मौत हुई, वह खदान भी पुष्पेंद्र यादव के ही कब्जे में है. यह मजदूरों की हादसे में मौत नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन सरकार ने इसे इतने हल्के में लिया कि मौतों पर दस-दस और बीस-बीस लाख रुपये का मुआवजा रेवड़ियों की तरह बांटने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संजीदगी का प्रदर्शन करते हुए दो-दो लाख रुपये परिजनों को थमा दिए और बस, धंधा फिर जारी है.

खादी, खाकी और खनन माफियाओं का भ्रष्ट गठजोड़ बुंदेलखंड में फिर पांच मजदूरों को लील गया. महोबा के गौरहारी में खदान दरकने से हुई इन मौतों ने इस गठजोड़ का नंगा सच सामने ला दिया. एक ऐसा सच जो इस कार्य से बावस्ता हर किसी को कठघरे में खड़ा करता है. घटना के तुरंत बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने जिस तत्परता के साथ प्यादों पर कार्रवाई की और जिस चतुराई के साथ खुद को तथा इस खेल के बड़े मोहरों को सुरक्षित किया, वह बेहद काबिले गौर है. चौबीस घंटे की कड़ी मशक्कत और मुख्यमंत्री द्वारा दो-दो लाख की मामूली आर्थिक सहायता के बाद मामला भले ही शांत हो गया हो, पर इस घटना से एक बात तो साफ हो गई कि बुंदेलखंड में हो रहे अवैध खनन के धंधे की डोर माफियाओं के हाथ से सरककर नेताओं के हाथों में पहुंच चुकी है.

बुंदेलखंड में बेहद बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है. यहां सत्ता की सरपरस्ती में नदियों की रेत, मिट्टी और मोरंग निकालकर खुलेआम बेची जा रही है. पर्यावरण विभाग की आपत्ति के बाद भी पहाड़ों का खनन जोरों पर है. खनन कार्य से जुड़े लोगों पर न्यायालय के आदेश तक बेअसर हैं. यहां इस मामले में अकेले खनिज विभाग को कसूरवार ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि खनन के इस अवैध खेल में सब शामिल हैं. चौकी के संत्री से लेकर सूबे के मंत्री तक कमोबेश सब इस काम में लिप्त हैं. ललितपुर से चित्रकूट तक फैले खनन

के इस खेल में सभी की उसके पद और हैसियत के अनुसार हिस्सेदारी तथा भूमिका तय है. प्रशासनिक अफसरों, खाकी, खादी और खनन माफियों के इस गठजोड़ में यदि नुकसान पर कोई है तो वह हैं इस काम से जुड़े मजदूर! वह मजदूर जो चंद रुपये के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं. मामूली दिहाड़ी के लिए ऐसा जोखिम उठाना इन श्रमिकों की मजबूरी भी है और जरूरत भी. यही वजह है कि बुंदेलखंड में प्रतिदिन खनन कार्य की चपेट में आकर किसी न किसी कामगार की मौत हो जाती है. आए दिन होने वाली इन मौतों में से ज्यादातर पैसा, पावर और पॉलीटिक्स के दम पर भ्रष्टाचार के इतिहास का हिस्सा बना दी जाती हैं. अधिकांश मामलों में मृतक परिवार को कुछ रुपये देकर शांत करा दिया जाता है और खनन माफियाओं के इस भ्रष्ट मंसूबों को अमली जामा पहनाती है खाकी. सत्ताई आकाओं

तूती बोलती है पुष्पेंद्र यादव की

बुंदेलखंड की बदहाली से परे नेताओं की नजर यहां की खनिज सम्पदा पर है. ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर सर्वोच्च सदन के मुख्तार तक सभी इसका दोहन कर रहे हैं. बात यदि खनिज के मामले में बुंदेलखंड की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले महोबा की करें तो यहां रसूखदारों ने लूट मचा रखी है. यहां इस कारोबार में हर दल के माननीयों की मजबूत दखल है पर सत्ताधारी दल के नेताओं की तो तूती बोल रही है. प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सत्ता से जुड़े प्रत्येक माननीय की यहां खदानें, घाट और क्रशर चल रहे हैं. बताते हैं कि अकेले कबरई में करीब तीन सैकड़ा क्रशर और क्रमोबेश इतनी ही पत्थर खदानें चलाई जा रही हैं. इनमें 90 प्रतिशत पर सत्ताधारी नेताओं का कब्जा है. ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, एमएलसी, विधायक, मंत्री से लेकर इस विभाग के मुखिया तक सबका अपने कद्दानुसार इस व्यापार में रुतबा है. इस लिस्ट में एक ऐसा भी नाम है जिसके आगे खनिज मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति भी शायद बौने साबित होंगे. यह नाम है मुख्यमंत्री के भाई और सांसद धर्मेन्द्र यादव के साले पुष्पेंद्र यादव का बुंदेलखंड में आज इसे खनिज किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा. सीधे तौर पर भले इस कारोबार में इनका दखल न दिखता हो पर अंदरखाने का सच यही है कि बिना इनकी मर्जी और सहमति के किसी का भी खनन किया जाना मुमकिन नहीं. इनके अलावा दूसरा सबसे बड़ा नाम सपा के पूर्व मंत्री और मौजूदा पार्टी अधिकृत प्रत्याशी सिद्धगोपाल साहू का है जिसने कबरई मंडी में अपना अधिपत्य कायम किया हुआ है. गौरहारी कांड को लेकर गर्म चर्चाओं को सच मानें तो जिस अवैध खदान में बीते रोज घटना घटी उसे चलाने का प्रशासन पर पुष्पेंद्र यादव ने दबाव बनाया था. सत्ता भय के चलते भले प्रशासन इस बात को कहने से कन्नी काट रहा हो, लेकिन विपक्षी दलों के नेता और आम लोग यह बात चीख-चीख कर कह रहे हैं. हमीरपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष पति पुष्पेंद्र का रुतबा बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री से कम नहीं है. सपा मुखिया के रिश्तेदार होने की वजह से इनके जो ठाठ-बाट हैं, वो तो जगजाहिर हैं ही, इनके करीबियों और गुर्गों की भी खूब चांदी है. महोबा जिला पंचायत अध्यक्ष के पति एवं जिला महासचिव रमेश यादव, पूर्व मंत्री बादशाह सिंह का भतीजा राजू सिंह, अब्दुल तारिक जैसे महोबा में कई ऐसे नाम हैं जो आज इस सफेदपोश माननीय के कृपापात्रों की फेहरिस्त में शुमार बताए जाते हैं. हमीरपुर से बैठकर अपने इन्हीं सेना नायकों के सहारे पुष्पेंद्र महोबा में अपनी हुकूमत चलाता है. इसकी हैसियत के आगे जिले के नेता ही फीके नहीं दिखते बल्कि प्रशासन की भी इनके आगे कोई हैसियत नहीं है. इसी हैसियत का नतीजा है कि प्रशासन ने गौरहारी कांड को कुछ चुटकियों में और शासन ने कुछ सिक्कों में निपटा डाला.■

सत्ता के आगे मज़दूर की क्या औकात!

गौरहारी में चल रही अवैध खदान में दबकर मजदूरों के मरने की यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पूर्व 2009 में भी चार मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं. वर्ष 2009 में इसी तरह काम करते समय खदान धंसने के कारण जयसिंह, रामकिशन, टेकचन्द्र और रवि की मौत हो गई थी. तब भी इसी तरह कोहराम मचा था लेकिन कुछ दिन हो-हल्ला मचने के बाद सब शांत हो गया. इस अवैध कारोबार ने एक बार फिर बारेलाल, मकुदलाल, भागीरथ, भानुप्रताप और राजू नामक कामगारों को अपना शिकार बना डाला. मौतें होती रहेंगी, लेकिन मानक को ताक पर रख कर चलाई जा रही अवैध खदानों का धंधा कम नहीं होगा, क्योंकि जब धंधे की डोर सीधे सत्ता से बंधी हो तो मजदूर की जान की क्या कीमत है!■

खीरी को खा रहे खनन माफिया

लखीमपुर खीरी जनपद विविध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतें संजोये हुए है, लेकिन ऐतिहासिक विरासतों पर भी खनन माफियाओं की गिद्ध दृष्टि है. जनपद की अतिविख्यात तहसील गोला गोकर्णनाथ जिसे छोटी काशी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है, आज खनन माफियाओं की वजह से होने की कगार पर है. यह धार्मिक स्थान चारों तरफ से वन आच्छादित था लेकिन आज प्राकृतिक संसाधनों के अन्धाधुन्ध दोहन से इस धार्मिक नगरी का वजूद ही खतरे में है. वर्तमान समय में यह प्राचीन धार्मिक नगरी अपने आसपास की हरियाली और प्राचीन धरोहरों को खोती जा रही है. गोला नगरी के ग्राम कोटवारा व भूगर्भ में समाई सरस्वती नदी पर नजर डालने पर भूमाफियाओं के कृत्य साफ दिखाई पड़ते हैं. नदी के वजूद को बचाए रखने के लिए प्राकृतिक रूप से नदी के आसपास बालू के ऊंचे-ऊंचे टीले बने हुए थे, जिन्हें भूमाफियाओं ने प्रशासन से साठगांठ कर खोद डाला, जिससे आज नदी का वजूद ही समाप्त होने पर है. जिले में खनन का कारोबार स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में दिन-रात फलफुल रहा है. इसमें नेता और माफिया साथ शरीक हैं. खनन का धंधा सुबह से देर रात तक पुलिस व प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चलता रहता है. क्षेत्र की जनता मूक गवाह है. संस्कृति नष्ट हो रही है, समाज चिंतित है, लेकिन सत्ता को इस चिंता से कोई मतलब नहीं.पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते खनन माफिया कोटद्धार ग्राम व भूगर्भ में समाई सरस्वती नदी के किनारे बने टीलों को जेसीबी मशीनों से खोद कर लूट रहे हैं. सुबह से लेकर देर रात तक जेसीबी मशीनें गरजती रहती हैं. टीलों को काटकर निकाली जा रही मिट्टी ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर खुलेआम ले जाई जा रही हैं. कोटद्धारा के टीले गहरे खड्ड में तब्दील हो गए हैं. भूगर्भ में समाई सरस्वती नदी के टीले जो कि बांकेगंज से ग्राम इमलिया कोठी तक रेलवे लाइन के किनारे कभी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति की मिसाल बने हुए थे, अब वहां भी ऊबड़खाबड़ गड्ढे और खाई बन गई है. मिट्टी खोद-खोद कर ईंट-भट्ठे का धंधा करने वाले मौज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं. पुलिस-प्रशासन चवन्नी चाटने में व्यस्त है. हाल यह है कि गोला आरक्षित वन क्षेत्र के गोला-अलीगंज मार्ग पर ईंट भट्ठों की कतारें व गोला बांकेगंज मार्ग एवं मोहम्मदी वन रेंज और मैलानी वन रेंज के जंगलों के निकट लगभग दो किलोमीटर की परिधि में ही तमाम ईंट भट्ठे सरकार और सरकारी तंत्र के नाकारेपन का ढोल पीटते हैं. ईंट भट्ठे नेताओं और दबंगों के हैं, आम आदमी क्या करे. धार्मिक नगरी छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में नगर कैचारों तरफ ईंट भट्ठों द्वारा किए जा रहे खनन के चलते अधिकतर भूमि खड्डों का रूप ले चुकी है.■

-अजय गुप्ता

मज़दूरों की मौत पर फेंक रहे सियासत के सिक्के

बुंदेलखंड में सूखा है तो बना रहे. किसान आत्महत्याएं करते हैं तो करते रहें. लोग रोजगार के अभाव में परदेस जाते रहें और क्षेत्र में गरीबी और भुखमरी बढ़ती रहे. सियासतदानों को इससे क्या लेना देना. उन्हें तो मुद्दा चाहिए.फिर लाश पड़ी हो नेताओं के लिए इससे अच्छा मुद्दा और क्या है. सत्ताधारी नेताओं और खनन माफियाओं के गठजोड़ ने गौरहारी में पांच मजदूरों की जान ले ली, तो भाजपा नेताओं ने परिजनों को दस-दस हजार रुपये थमाकर अपनी राजनीति की रोटी सेंक ली. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर गौरहारी पहुंची पांच सदस्यीय टीम ने हादसे के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को खूब कोसा. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष करन सिंह पटेल, अकबरपुर सांसद देवेन्द्र सिंह भोले,जालौन सांसद भानू प्रताप वर्मा, महोबा सांसद पुष्पेंद्र चंदेल और महोबा के पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत भाजपा की टीम में शामिल थे. राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा बदलने का चलन कोई नई बात नहीं है. महोबा जनपद की कुछ घटनाएं नेताओं के इसी फेरबदलकी सनद देते हैं. गौरहारी खनन कांड की घटना में सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी दल सबके दावपेंच सामने खोल कर रख दिए. सत्ताधारी पार्टी ने दो लाख का मुआवजा देकर निपटा दिया तो विपक्षी दल भाजपा ने दस-दस हजार रुपये देकर अपनी संजीदगी प्रदर्शित करने की कोशिश की. कांग्रेस ने मौखिक मातमपुर्सी की तो बसपा ने मातमपुर्सी कार पर एक लाख रुपया रख कर फेंका. लेकिन बसपा की लाख टके की मातमपुर्सी कोई असर नहीं दिखा पाई, क्योंकि कीरत सागर तट पर हुई बंटी अहिरवार की हत्या में बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता मृतक दलित के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दे आए. अब पूरे क्षेत्र में लोग बसपा के एक लाख बनाम पांच लाख रुपये के सर्वजनसुखाय का भेद समझने में लगे हैं. जब गौरहारी में पांच मजदूर अवैध खनन के शिकार हुए थे, उसी दिन कबरई में भी आत्माराम नामक मजदूर की ब्लास्टिंग पत्थर लगने से मौत हो गई थी, लेकिन आत्माराम के परिवार की सुध किसी ने नहीं ली, न सत्तापक्ष ने ली और न विपक्ष ने.■

के भय और माफियाओं से मिलने वाले हिस्से के लालच ने पुलिस को अवैध खनन पर कार्रवाई करने के मामले में नपुंसक और दलाल बना दिया है. पुलिस की इसी नपुंसक कार्यशैली के चलते अधिकांश मामले मैनेज हो जाते हैं या यूं कहें कि जबरन दबवा दिए जाते हैं. नतीजतन पत्थर व्यवसाय में श्रमिकों की मौत के विरले मामले ही सार्वजनिक हो पाते हैं. महोबा जनपद के गौरहारी में घटी घटना को ऐसी ही घटनाओं में से एक कह सकते हैं. डायसफोर गौरा पत्थर खदान की बहतायत वाले इस गांव में बीते दिनों तब कोहराम मच गया जब एक अवैध ढंग से चलाई जा रही खदान में काम कर रहे आधा दर्जन मजदूरों पर चट्टान दरककर गिर पड़ी. घटना कितनी हृदय विदारक थी इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि चट्टान की चपेट में आए मजदूरों में से मात्र एक को ही जीवित बचाया जा सका, जबकि पांच ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

गौरहारी में खदान दरक जाने की सूचना मिलने के तुरन्त बाद पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह के साथ जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह मौके पर पहुंच गए. इस घटना को हल्के में ले रहे आला अफसरों ने जब वहां पहुंचकर स्थिति देखी तो उनके होश उड़ गए. ग्रामीणों द्वारा निकाले जा चुके तीन मजदूरों के शव और उनके आस-पास बैठे परिवारीजनों की चीख पुकार ने अधिकारियों की घिग्गी बांध दी. अधिनस्थों को दिशा-निर्देश देने के बाद अधिकारी जब वहां से खिसकने लगे तो ग्रामीणों ने उनके वाहनों को घेर लिया. ग्रामीणों की मांग थी कि जो मजदूर खदान में फंसे हैं पहले उन्हें निकाला जाए और मृतकों के परिवारीजनों को उचित मुआवजा तथा खदान संचालकों पर कार्रवाई की जाए. प्रशासन ने पहले तो ग्रामीणों को बहलाने की कोशिश की लेकिन जब भीड़ उग्र हो गई तो अधिकारियों को बैकफुट पर जाना पड़ा. सूचना राजधानी तक पहुंची. मुख्यमंत्री ने दो-दो लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया. इधर मौके की नजाकत को देखते हुए गैर जनपदों से सुरक्षाबल और पीएससी बुला ली गई. खबर पाकर चित्रकूट के डीआईजी और फिर इलाहाबाद जोन के आईजी भी घटना स्थल पर पहुंच गए. आला अफसरों के पहुंचते ही बचाव कार्य तेज कर दिया गया. तब जाकर कहीं चौबीस घंटे बाद मलबे में फंसे दो अन्य मजदूरों के शव बाहर निकाले जा सके. इस बीच ग्रामीणों के आक्रोश से बचने के लिए प्रशासन ने खदान के कथित सिंगमी ठेकेदार गब्बर सिंह सहित उन आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई की खानापूर्ति भी कर डाली, जिनकी हैसियत इस खेल में एक मामूली प्यादे से अधिक और कुछ भी नहीं थी. बताते हैं कि अफसरों ने राजधानी में बैठे आकाओं के इशारे पर उस कद्दावर सफेदपोश को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी, जो इस घटना के लिए असल कसूरवार है. अधिकारियों के बदलते बयान बता रहे थे कि मामला कहां से जुड़ा हुआ है. यदि ऐसा नहीं तो फिर भला 2012 में समयावधि समाप्त हो चुकी खदान को बिना रिन्युअल के कैसे चलाया जा रहा था.

घटना से जुड़े इस अहम सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया. पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने प्यादों पर कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली तो खनिज विभाग के कर्मचारी यहां वहां छिपते नजर आए. घटना के समय लखनऊ में मौजूद जिला खान अधिकारी बीपी यादव जब महोबा पहुंचे तो उन्होंने ऑफ द रिकार्ड यह स्वीकार किया कि इस खदान को चलवाने का उन पर दबाव था लेकिन खबर छापने की बात पर वह पलटी मार गए. आधिकारिक बयान के रूप में उन्होंने जो बोला वह बेहद हास्यस्पद भी था और चौंकाने वाला भी. उनके मुताबिक खनिज नियमों में ऐसा प्रावधान है कि रिन्युअल का प्रार्थना-पत्र जमा हो जाने के बाद खदान चलाई जा सकती है. हालांकि आम आदमी के मामले में इस नियम का पालन क्यों नहीं होता, जैसे सवाल पर वह बगलें झांकते नजर आए.■

नामकरण में साहित्यकारों से परहेज़ क्यों

अनंत विजय

अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री मंत्री वीके सिंह ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर करने का अनुरोध किया. यह खबर अभी चल ही रही थी कि ऋषि कपूर ने एक के बाद एक दनादन ट्वीट करके सियासत की दुनिया में सनसनी फैला दी. ऋषि कपूर ने गांधी-नेहरू परिवार पर सीधे हमला बोला और सवाल पूछा कि क्या सिर्फ एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर एयरपोर्ट और सड़कों के नाम रखे जाने चाहिए. साथ ही ऋषि कपूर ने कलाकारों के नाम लिखकर यह प्रश्न खड़ा किया कि उनके नाम पर कोई सड़क, कोई एयरपोर्ट या किसी सरकारी इमारत का नाम क्यों नहीं रखा जाता है? ऋषि कपूर ने चूंकि इसमें गांधी-नेहरू परिवार का नाम ले लिया था, इस वजह से जो सियासत शुरू हुई उसमें कई बातें दबकर रह गईं. ऋषि के ट्वीट की भाषा पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए. यह सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कपूर ने अपने एक ट्वीट में कलाकारों के नाम पर सड़क, एयरपोर्ट या सरकारी इमारत का नाम नहीं रखने की जो बात की वो कहीं इस राजनीतिक बयानबाजी के कोलाहल में दबकर रह गई. इस सवाल पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी राजधानी में हमें कोई प्रेमचंद मार्ग या निराला मार्ग क्यों नहीं मिलता है? किसी एयरपोर्ट का नाम रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत के नाम पर क्यों नहीं दिखाई देता है? किसी विश्वविद्यालय का नाम मुक्तिबोध या मोहन राकेश के नाम पर क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारे समाज में साहित्यकारों को लेकर इस उदासीनता के भाव की वजह क्या है? हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. क्या इन सड़कों, इन इमारतों या फिर एयरपोर्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हक नेताओं का ही है? इस बात पर राष्ट्रव्यापी बहस क्यों नहीं होती है कि नामकरण के वक्त साहित्यकारों के नाम पर भी विचार हो?

राजधानी दिल्ली में हर छोटे-बड़े-मंझोले नेता के नाम पर सड़क, चौक, फ्लाई ओवर आदि है लेकिन, अगर सुब्रमण्यम भारती और दिनेश नंदिनी डालमिया का नाम छोड़ दिया जाए तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी सड़क का नाम किसी भी भाषा के साहित्यकार के नाम पर है. साहित्य अकादमी के भवन का नाम छोड़ दिया जाए तो याद नहीं पड़ता कि किसी सरकारी इमारत का नाम किसी वरिष्ठ साहित्यकार के नाम पर हो. ऐसा क्यों होता है? क्या सत्ता में रहने वाले लोग ही बारी-बारी से अपने नेताओं के नाम पर सड़कों इमारतों का नामकरण करते रहेंगे? क्या साहित्यकारों के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है? क्या देश रचनात्मक लेखन करने वालों का ऋणी नहीं है?

दरअसल, अगर हम देखें तो आजादी के बाद हमारे देश में साहित्यकारों की बहुत इज्जत थी. हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वानों को राज्यसभा में जगह दी जाती थी. भारतीय भाषाओं के नुमाइंदे तब संसद में हुआ करते थे. बाद में कलाकारों के कोटे से फिल्म अभिनेताओं को जगह दी जाने लगी. यह गलत भी नहीं है. साहित्यकारों के नाम पर फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने वाले राज्यसभा पहुंचने लगे. हिंदी का आखिरी साहित्यकार, अगर हम याद करें, जो कि राज्यसभा पहुंचे थे वो थे विद्यानिवास मिश्र. विद्यानिवास मिश्र को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मनोनीत किया था. उसके बाद तो फिल्मों से, खेल जगत से तो लोग नामांकित होते रहे, लेकिन साहित्य को लेकर उदासीनता बनी रही. कालांतर में तो सक्रिय राजनीति कर रहे और चुनाव में हारे हुए नेताओं को सरकार राज्यसभा में मनोनीत करने लगी. साहित्य और साहित्यकारों की जगह कम होती चली गई.

इस सवाल पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसी राजधानी में हमें कोई प्रेमचंद मार्ग या निराला मार्ग क्यों नहीं मिलता है? किसी एयरपोर्ट का नाम रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंदन पंत के नाम पर क्यों नहीं दिखाई देता है? किसी विश्वविद्यालय का नाम मुक्तिबोध या मोहन राकेश के नाम पर क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारे समाज में साहित्यकारों को लेकर इस उदासीनता के भाव की वजह क्या है?

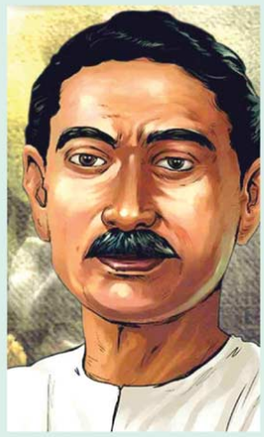

साहित्यकारों को लेकर कुछ नेताओं के मन में किस तरह के विचार हैं, यह वीके सिंह के उस बयान से पता चलता है जो उन्होंने पिछले साल भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन के ठीक पहले दिया था. यह उस सरकार के मंत्री का बयान था, जिसके मुखिया यानि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं कवि हैं और उनकी कविता की पुस्तकें प्रकाशित हैं. स्वयं वीके सिंह की भी किताब प्रकाशित हुई है और पाठकों द्वारा पसंद की जा रही है. हालांकि वीके सिंह ने बाद में सफाई देकर कहा था कि लेखकों को अपमानित करने की उनकी मंशा नहीं थी.

दरअसल, अगर हम विचार करें तो देखते हैं कि साहित्य और राजनीति के बीच खाई गहरी होती जा रही है. साहित्यकारों और नेताओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है. सत्तर के दशक के बाद हिंदी में इस प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा था कि लेखकों को नेताओं के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहिए. लेखकों ने नेताओं को हेय दृष्टि से देखना शुरू किया था. इनमें वो लेखक ज्यादा थे जो कि अपनी रचनाओं के लिए अजय भवन के संदेशों का इंतजार करते थे. इसका नतीजा यह हुआ कि राजनीति और साहित्य में दूरियां बढ़ती चली गईं. मुझे याद पड़ता है कि दो एक साल पहले बिहार के सांसद पप्पू यादव की आत्मकथा का विमोचन नामवर सिंह ने किया था, तो नामवर सिंह पर जमकर हमले हुए थे. पिछले साल एक कहानी पुरस्कार वितरण समारोह में एक वरिष्ठ साहित्यकार ने इस वजह से आने से इंकार कर दिया था, क्योंकि वहां दिल्ली के उपराज्यपाल को भी होना था. राजनेताओं के साथ मंच साझा नहीं करने की प्रवृत्ति ने साहित्य और राजनीति के विचारों की आवाजाही को रोक दिया. आयातित विचारधारा की संस्कृति ने अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के बैरियर लगाए थे. अपनी संस्कृति को छोड़कर हम बाहर से आई संस्कृति के हिसाब से काम करने लगे थे. तभी तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, जातियों का सांस्कृतिक विनाश तब होता है जब वह अपनी परंपराओं को भूलकर दूसरों की परंपराओं का अनुकरण करने लगती हैं. जब वह मन-ही-मन अपने को हीन, दूसरों को श्रेष्ठ मानकर मानसिक दासता को स्वेच्छया स्वीकार कर लेती हैं. पारस्परिक आदान-प्रदान तो संस्कृतियों का स्वाभाविक धर्म है, किन्तु जहां प्रवाह एकतरफा हो, वहां यही कहा जाएगा कि एक जाति दूसरे जाति की सांस्कृतिक दासी हो रही है. किन्तु सांस्कृतिक गुलामी का इन सबसे भयानक रूप वह होता है, जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की भाषा को अपना लेती है और उसी में तुतलाने को अपना परम गौरव मानने लगती है. यह गुलामी की पराकाष्ठा है. क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, वह अपनी परंपरा से छूट जाती है और उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है. दिनकर जी की बातों को अगर हम वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखें तो सारी बातें साफ हो जाती हैं. दिनकर के इस कथन से सूत्र पकड़ने की जरूरत है, जब वो एकतरफा प्रवाह की बात करते हैं.

दूसरी बात यह है कि दूसरों को श्रेष्ठ मानकर मानसिक दास्ता को स्वीकार कर लेते हैं तो विकास अवरुद्ध हो जाता है. आत्मविश्वास की कमी हो जाती है. अपने सांस्कृतिक विचारों से मार्क्स के विचारों को श्रेष्ठ मानने का नतीजा आज हम सबके सामने है. किसी मार्क्सवादी कवि में यह नैतिक साहस नहीं है जो दिनकर में था. आज कौन सा कवि लिख सकता है कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी! अपने समय का सूर्य हूं मैं. अब यह पंक्ति कहने का साहस कवि को है तो उसके पीछे उसका अपनी परंपराओं पर अपनी संस्कृति पर गर्व और विश्वास की ताकत है. उसका आत्मविश्वास है. अपने समय का सूर्य हूं कहना मामूली बात नहीं है. सवाल यही है कि जिस तरह से हमारे साहित्यकार एक पक्ष में खड़े होते चले गए, उसने साहित्य को राजनीति का एक पक्ष बना दिया और जब आप एक पक्ष बन जाते हैं तो दूसरा पक्ष आपका अनदेखी करता ही है. साहित्य और साहित्यकारों की अनदेखी तो दोनों पक्षों ने की. हिंदी के सबसे बड़े लेखक नामवर सिंह ने तो विचारधारा की ध्वजा भी उठाई थी और चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस विचारधारा ने कभी भी नामवर सिंह को संसद में भेजने का नहीं सोचा. बंगाल के हर तरह के छोटे-मोटे नेता, प्रोफेसर आदि को राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन नामवर सिंह के बारे में सोचा भी नहीं गया. आज जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में सड़कों, इमारतों और एयरपोर्ट के नामकरण के लिए एक नीति और समिति बनाई जानी चाहिए. उसमें साहित्य कला और संस्कृति के नुमाइंदे भी हों जो सरकार को इस बात का सुझाव दें. अगर ऐसा हो पाता है तो अच्छा होगा, नहीं तो नामकरण को लेकर राजनीतिक वर्ग खासकर सत्ताधारी दल की मनमानी चलती रहेगी और जिस परिवार या वर्ग का उस दल पर वर्चस्व रहेगा वह अपनी मनमानी करता रहेगा. वक्त आ गया है आजादी के बाद से हुई गलतियों से सबक लेने की और उसको ठीक करने की योजना पर अमल करने की. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

व्यंग्य

घर का हर शख्स न्यूज़ एंकर सा लगता है

अभिषेक मेहरोत्रा

बड़ा ही अजीब जमाना आ गया है, अभी तक तो सिर्फ अपने बापू ही अपुन से आने-जाने से लेकर खर्च-जमा का हिसाब रखते थे, पर जब से यह नेशन वॉन्ट टू नो का चलन चला है, अपुन तो बड़ी मुश्किल में आ गए हैं. अब तो घर का बच्चा भी हर सवाल पूछता है और आंख दिखाओ तो टका सा जवाब देता है कि टीवी नहीं देखते क्या? आजकल सवाल पूछने का चलन जोरों पर है.

अरे भाई, इस चलने ने तो अपुन की जान ही ले ली है. अब तो लगता है कि टीवी से फिर से वह रामारण वाला युग ही आ जाए तो बेहतर है. बच्चों को न्यूज़ देखने की सलाह देकर अपुन तो खुद ही उनके गेस्ट कम टारगेट ज्यादा बन गए हैं. अब तो घर का हर शख्स एंकर सा ही लगता है. वैसे भी पत्रकार के घर में उसके साथ रहते-रहते उसके तर्क-वितर्कों के चलते ही सब घर वाले पत्रकार बन जाते हैं और ऊपर से यह टीवी के बहस के चलते रोज की चिक-चिक से झिक-झिक देखकर, अब तो हर कोई बस अपनी बात को लंबी से लंबी खींच के ले जाने में निपुण होता जा रहा है.

कल तो हद ही हो गई है, जब अपुन ने बच्चों के पिज्जाई टेस्ट से दूर जाकर मालपुए बनाने के लिए घर की सीनियर मोस्ट एंकर की तरह व्यवहार करने वाली श्रीमती जी से कहा, तो आज के जुकरबर्गीय बच्चों ने सबसे पहले यह ही सवाल दाग दिया कि नेशन वॉन्ट्स टू नो वॉट इज़ मालपुआ. वो तो खैर रही कि गूगल बाबा की मदद से अपुन ने उन्हें मालपुआ की फोटो के दर्शन करा दिए, वरना पता नहीं कहीं यह भी ट्विटर पर ट्रेंड करकर हमारी तो इज्जत की ग्लोबली बेइज्जती कर देता.

पर जब फेसबुक पर हमने फीलिंग हैप्पी, ईटिंग मालपुआ लिखा तो न जाने मालपुए को लेकर कितने पिज्जुओं को इसका टेस्ट भी कराना पड़ा. लो जी, अपुन के आधे मालपुए तो नेशन को समझाने-चटवाने में ही निपट गए.

पर एक राहत है कि अब कुछ महीनों से बच्चों के जल्दी सोने पर सन्नाटे से चीरते हुए उनके सनसनी टाइप सवालों से जरूर बच जाते हैं. पर यह जो नए ठुमकने वाले प्रोग्राम दिनभर चलते हैं, इनके नित्य-नित्य नए नृत्य शैलियों पर दागे जा रहे सवालों से आजकल अपुन घायल हो रहे हैं.

अपुन ने तो घर में टीवी इसलिए लगवाया था कि सबका मन लगे और ज्ञान बढ़े पर अब तो इसके चलते हमारे ही ज्ञान की रोज टेस्टिंग होती रहती है. बस सहारा है गुगलु महाराज का. इधर सवाल तो उधर मोबाइल पर गुगलु वर्जन से पाया जवाब. तो भइया, अगली बार तो ऐसा डिश कनेक्शन लेंगे जिसमें सवाल दागते ही टीवी वाले कम ही दिखें. नहीं तो घर में एंकर बने हमारे लोग कहीं इतने ग्रूम ने हो जाए कि नेशन से यूनिवर्सल तक के सवाल अपुन पर ही दागते रहें. ■

feedback@chauthiduniya.com

कविता

आशाएं

हैं राह में कई मुश्किलें मगर
बढ़ हौसलों के तु साथ अगर
न रोक पाएंगी तुझे जीवन के लक्ष्य से
न भटकेगा तु कभी अपने पथ से
माना मंजिल अभी बहुत दूर है
पर तु क्यों इतना मजबूर है
हिम्मत कर तु आगे बढ़ने की
नयी सोच, नयी कहानी गढ़ने की
न देख पीछे जो छूट गया
हर सपना जो टूट गया
संजोकर उन सपनों को फिर कदम बढ़ा
ढूंढ़ लेगी मंजिल तुझे इस बार कसम खा
जिंदगी के सफर में कई बाधाएं भी हैं
निराशा है तो आशाएं भी हैं

❖❖❖

रुकते क़दम

तमन्नाओं के भंवर में गिरते-गिरते
बची हूं मैं जरा संभलते-संभलते
उठ जाए जो कदम एकबार तो
नहीं थमते फिर ठहरते-ठहरते
बड़ी मुश्किल से है रोका खुद को
जानती हूं दिया है धोखा खुद को
माना कि मैं चाहती हूं बहुत
न समझा दिल, तो टोका खुद को
राह में जो कठिन फासले हैं
मिट जाएगी गर दिल में हौसले हैं
है दिल में कहीं यकीं फिर भी
ले लिया जो दिल के फैसले हैं
नहीं आने दिया है कभी होठों पे नाम
नहीं चाहती हूं करना किसी को बदनाम
शायद है रब की यहि ख्वाहिश
कि हाथों से मेरे छूट गया जाम

-नूपुर मिश्रा (नूर)

साईं वंदना

गुरु -शिष्य

गुरुओं का आध्यात्मिक स्तर

मानव-सभ्यता के इतिहास में हर मनुष्य चाहे वह किसी भी काल में हो, उसे गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और वह उनकी खोज करता है. यह खोज शिक्षा-प्राप्त करने या धार्मिक/आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए होती है.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

क्या आध्यात्मिक जगत में गुरुओं का भी स्तर होता है?

जी हां. जैसे सांसारिक जगत में कई गुरु होते हैं- कुल गुरु, विद्या गुरु, विद्यालय के गुरु, महाविद्यालय के गुरु-उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी गुरुओं का स्तर होता है. सद्गुरुओं को छोड़कर और कोई पूर्ण ब्रह्म अवस्था को प्राप्त नहीं है, क्योंकि केवल वह ही सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं. बाकी अन्य गुरु सीमित हैं. अन्य गुरु सद्गुरु तक पहुंचने का माध्यम बन सकते हैं. सद्गुरु अंतिम हैं. अतः प्रकृति के नियम के अनुसार जो सच्चे भक्ति-भाव से सद्गुरु की शरण प्राप्त कर चुका है, वह कभी भी अन्य गुरु को नहीं ढूंढ़ेगा. उनके जीवन की हर चीज की प्राप्ति सद्गुरु के माध्यम से होगी. अगर कोई व्यक्ति अपने अज्ञान से अन्य गुरुओं को सद्गुरु समझ बैठे तो वह भी सत्यता नहीं है.

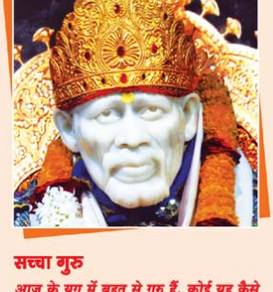

सच्चा गुरु

आज के युग में बहुत से गुरु हैं. कोई यह कैसे जान पाएगा कि उसका सच्चे गुरु से साक्षात्कार हुआ है?

मानव-सभ्यता के इतिहास में हर मनुष्य चाहे वह किसी भी काल में हो, उसे गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और वह उनकी खोज करता है. यह खोज शिक्षा-प्राप्त करने या धार्मिक/आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए होती है. गुरु-गीता में कहा गया है कि जैसे कोई मधुमक्खी शहद प्राप्त करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति भी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाता है. यदि वह सद्गुरु को पाना चाहता है, तो आध्यात्मिक मार्ग की दिशा में उसका ऐसा करना गलत नहीं है. हां, एक बार यदि सद्गुरु उसे मिल जाते हैं तो उसे एकाग्रचित होकर उनका अनुगमन करना चाहिए. यह आवश्यक नहीं है कि सभी गुरु सद्गुरु हों. सद्गुरु वे होते हैं, जिनमें कि हर परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करने की क्षमता होती है (समर्थ सद्गुरु) और जो कि भक्तों की चेतना को विकसित कर उन्हें मोक्ष-प्राप्ति की दिशा में संचालित करते हैं. पृथ्वी पर बहुत ही कम सद्गुरु हैं. एक बार यदि सद्गुरु से संबंध जुड़ जाता है, तो फिर उसके पश्चात् किसी अन्य गुरु से सम्पर्क जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है. जिसके हृदय में सद्गुरु को पाने की अदम्य इच्छा है, उसे इस दिशा में अथक प्रयास करना चाहिए. ऐसा करने से कभी न कभी वह सद्गुरु का ध्यान अपनी ओर अवश्य आकर्षित कर लेगा. फिर किसी न किसी माध्यम से वह उन तक पहुंच जाएगा. केवल सद्गुरु ही शिष्यों को अपने तरीके से स्वयं की ओर आकर्षित करते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

सन-राइजर्स बना आईपीएल का सरताज

हौसलों के आगे कोई नहीं विराट!

सैय्यद मोहम्मद अब्बास

इंडियन प्रीमियर लीग समाप्त हो चुकी है. रविवार 29 मई को विराट की सेना का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया. वार्नर के रणबांकुरों ने बंगलुरु को उसी के मैदान पर धूल चटा दी. फाइनल में गेल का बल्ला चला किन्तु अपनी टीम की नैया पार नहीं लगा सका. सन-राइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को आठ रन से पछाड़ते हुए आईपीएल का खिताब अपने नाम किया. हैदराबाद की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची और चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया जबकि विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही बंगलुरु की टीम तीसरी बार फाइनल में पहुंचकर भी खिताब हथियाने से चूक गई. टूर्नामेंट में बेहद उतार-चढ़ाव भरे सफर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सन-राइजर्स हैदराबाद खिताब जीतेगा. जहां एक ओर विराट रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर वार्नर भी अपना खेल दिखाने में मशगूल थे. दोनों ही टीमों में शक्तिशाली बल्लेबाजों की फौज थी. सन-राइजर्स हैदराबाद ने तूफानी खेल का प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया. शानदार फॉर्म में चल रहे वार्नर ने केवल 38 गेंदों में 69 रन की पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंगलुरु की टीम एक बार फिर विराट के बल्ले की दहाड़ सुनने को बेताब थी. दूसरी ओर गेल फाइनल में खतरनाक दिखे और 38 गेंद में छह गगन चुंबी छक्कों की मदद से 76 रन ठोक डाले, लेकिन अपनी टीम को जीता नहीं पाए. रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने रिकॉर्ड 973 रन बनाकर आईपीएल-9 में ऑरेंज कैप हासिल की जबकि सन-राइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप हासिल करने में सफल रहे. लीग चरण के शुरुआती दौर में निरंतरता की कमी के कारण पिछड़ी बंगलुरु ने अपने अंतिम मैचों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर फाइनल का टिकट कटाया था. दूसरी ओर सन-राइजर्स की टीम का प्रदर्शन भी अच्छा था. टूर्नामेंट के अंतिम दौर में सन-राइजर्स ने दो बड़ी जीत के बाद फाइनल में प्रवेश किया था. सन-राइजर्स ने टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार व दो बार की चैम्पियन कोलकाता नाइटराइडर्स को एलिमिनेटर में 22 रन से पराजित किया और इसके बाद दूसरे क्वालीफायर में गुजरात लायंस को चार विकेट की करारी शिकस्त दी.

आईपीएल में लगातार युवा खिलाड़ी चमक रहे हैं. बल्ले और गेंद की इस जंग में हर दिन नए रिकॉर्ड बने. आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया. दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ियों ने भी फटाफट क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनायी. गेल का खेल नहीं चला, लेकिन विराट का बल्ला रनों की बारिश कर विराट स्कोर खड़ा कर रहा था. अपनी प्रचंड फॉर्म में चल रहे विराट ने अपने बल्ले से सबको कायल बनाया. विराट लगातार रन बनाते रहे. इसका फायदा आने वाले दिनों में टीम इंडिया को मिलेगा. बतौर कप्तान भी आईपीएल में कोहली का दम-खम देखने को मिला. आईपीएल में इस बार दो नई टीमों को भी जगह दी गई थी. पिछले सत्र में फिक्सिंग खेल में शामिल दो टीमों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था. बोर्ड ने मैच फिक्सिंग से जुड़े विवाद के कारण दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद आईपीएल की दो नई टीमों को शामिल किया गया. मौजूदा सत्र में राइजिंग पुणे सुपरजॉयंट्स और गुजरात लॉयन्स की इंट्री हुई. इसमें गुजरात लॉयन्स की टीम ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया जबकि माही की नई टीम राइजिंग पुणे सुपरजॉयंट्स चारों-खाने चित्त हो गई. गौरतलब है कि माही इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे थे. आईपीएल के नौवें संस्करण के शुरुआती मैचों से कुछ नामी खिलाड़ी चोट के चलते बाहर हो गए वहीं कई गुमनाम खिलाड़ी एकाएक सुर्खियां में आ गए.

नौवें संस्करण में अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो एक बार फिर विराट सबसे आगे नजर आते हैं. मौजूदा आईपीएल में विराट का कोई सानी नहीं दिखा है. विराट हर दिन बल्ले से रिकॉर्ड बनाते रहे. उनकी मौजूदा फॉर्म इस बात की गवाह है कि आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड कोहली के बल्ले से टूटेंगे. आईपीएल के इस सत्र में विराट 973 रनों के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं, जिसमें चार शतक और सात अर्धशतक शामिल है. इतना ही नहीं आईपीएल के इतिहास में चार बार 500 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है. विराट ने 2015 के संस्करण में 505 रन बनाए थे, 2013 के संस्करण में 634 रन और 2011 के संस्करण में 557 रन बनाय थे. कोहली के बाद गंभीर, गेल और वार्नर का नाम आता है. नौवें संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने के चलते ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है. विराट का आईपीएल औसत भी बेमिसाल है. कोहली का औसत 81.08 के आसपास है. कोहली के बाद शॉन मार्श का नाम आता है. मार्श ने 2008 की सत्र में 11 मैच खेलते हुए करीब 69 के औसत से 616 रन बनाए थे. गेल तीसरे स्थान पर हैं. गेल ने 2011 के सत्र में मैच खेलते हुए करीब 68 के औसत से 608 रन बनाए थे. विराट को छोड़ अगर अन्य भारतीय बल्लेबाजों की बात की जाए तो उनमें रहाणे ने शानदार खेल दिखाया. भले ही उनकी टीम इस सत्र में कुछ खास नहीं कर पाई हो लेकिन रहाणे ने राइजिंग पुणे सुपरजॉयंट्स की तरफ से 43.63 की औसत से 480 रन बनाए. उन्होंने इस साल छह अर्धशतक भी जमाते हुए अपनी फॉर्म को साबित किया. विदेशी खिलाड़ियों की बात की जाए तो इनमें ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर का नाम सामने आता है. वार्नर ने अभी तक 17 मैचों में 09 अर्धशतकों की मदद से 848 रन जुटाए हैं. वह आईपीएल 9 में सर्वाधिक रन जुटाने वाले बल्लेबाजों में कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं. वहीं डिविलियर्स लीग में 687 रन बनाकर तीसरे सर्वाधिक रन जुटाने वाले खिलाड़ी हैं, इसमें उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतक बनाए हैं. गेंदबाजी के क्षेत्र में भुवनेश्वर की सटीक लाइन लेंथ खूब चर्चा में रही. यूपी के भुवी ने आईपीएल के नौवें संस्करण में 23 विकेट हासिल किये हैं. उनका औसत 20.21 का है. भुवनेश्वर ने इस सत्र में 17 मैच खेले हैं.

आईपीएल की खासियत है कि वह हर बार नया सितारा देता है. इस बार अगर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात की जाए तो लीग चरण में कई ऐसे खिलाड़ी सामने आए जिसे दुनिया कभी नहीं जानती थी. भारत के युवा खिलाड़ियों में करुण नायर का नाम सामने आता है. करुण नायर ने आईपीएल में बल्ले से खूब कमाल दिखाया. नायर ने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए 357 रन बनाए. इतना ही नहीं रणजी के फाइनल में तिहरा शतक लगाकर सबको चौंका दिया था. इसी प्रदर्शन के आधार पर जिम्बाब्वे का उन्हें टिकट मिला है. वहीं मुम्बई इंडियंस के ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या ने अपने खेल से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दरअसल, कुणाल हार्दिक पांड्या के भाई हैं. आईपीएल में कुणाल ने 191.12 की स्ट्राइक रेट से 12 मैचों में 237 रन बनाए. इतना ही नहीं शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट झटके. कुछ और बल्लेबाज हैं जो इस बार के आईपीएल में छाये रहे. ऋषभ पंत उनमें से एक हैं. भारतीय अंडर-19 टीम के स्टार बल्लेबाज पंत ने अपनी बल्लेबाजी से लोगों को प्रभावित किया है. इस साल 10 मैच में 198 रन बनाए. इस साल उनकी कुछ पारियों पर चयनकर्ताओं की नजर जरूर पड़ेगी. गेंदबाजी में संदीप शर्मा का नाम सबसे आगे हैं. संदीप ने शुरुआती ओवरों में अपनी स्विंग से दुनिया के कई धाकड़ बल्लेबाजों को डराया है. उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने साबित किया कि वह आने वाले दिनों में भारतीय गेंदबाजी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे.

कुल मिलाकर आईपीएल का मौजूदा सत्र विवादों की भेंट नहीं चढ़ा है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के नौवें संस्करण की शुरुआत काफी धमाकेदार रही, लेकिन बाद के मैचों में इसकी चमक धुंधली पड़ गयी. शुरुआती मैचों के बाद इसकी लोकप्रियता को लेकर कई सवाल खड़े किये गये, लेकिन लीग समाप्त होते-होते आईपीएल ने एक बार कामयाबी की नयी सीढ़ी चढ़ी है. एक आकड़ों के अनुसार आईपीएल का नौवां सीजन 31 करोड़ 70 लाख लोगों तक पहुंचा है. एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 902 जीवीएम के साथ पूरे भारत में दूसरे प्राइम टाइम चैनल से 231 फीसदी आगे है. साथ ही 655 जीवीए के साथ एचएसएम स्तर पर दूसरे प्राइम टाइम चैनल से 198 फीसदी आगे है. ■

जिम्बाब्वे में फिर चमक सकता है धोनी का सितारा

जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. आईपीएल की खुमारी के बाद भारतीय टीम को अब जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से दो-दो हाथ करना है. जिम्बाब्वे में भारत को तीन वन-डे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है. यह दौरा 11 जून से शुरू हो रहा है. महेंद्र सिंह धोनी 16 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुआई करेंगे. हाल के दिनों में टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. माही का प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में है. इतना ही नहीं उनका बल्ला आईपीएल में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया. बतौर कप्तान भी वह नाकाम रहे. ऐसे में जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ वह अपनी फॉर्म हासिल कर सकते हैं. जिम्बाब्वे में धोनी का सितारा फिर से चमक सकता है, यह एक मौका है. बात अगर जिम्बाब्वे दौरे पर चुनी गई टीम की जाए तो इसमें कई युवा खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. चयनकर्ताओं ने इस दौरे पर कई सीनियर खिलाड़ियों-विराट, रोहित और धवन को आराम दे दिया है. पहली बार बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज फैज फजल, ऑफ स्पिनर जयंत यादव, पंजाब के मध्यक्रम के बल्लेबाज मनदीप सिंह और आईपीएल स्टार यजुवेन्द्र चहल को भारतीय टीम से खेलने का मौका मिलेगा. वहीं जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाज़ी कोच रहे संजय बांगर को बीसीसीआई ने मुख्य कोच बनाया है. इसके साथ ही फील्डिंग कोच की ज़िम्मेदारी अभय शर्मा को सौंपी गई है.

चयनकर्ताओं ने धोनी को जो टीम सौंपी है, वह एकदम नयी नवेली है. जिम्बाब्वे दौरे पर चुनी गई टीम में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. रणजी के रण में कई खिलाड़ी लगातार बल्ले और गेंद से कमाल करते रहे हैं. इतना ही नहीं आईपीएल में भी इनका जलवा देखने को मिला है. बात अगर सलामी बल्लेबाज फैज फजल की जाए तो वह बेहद अंजान खिलाड़ी हैं. 30 साल के फैज फजल विदर्भ की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उनका बल्ला इस समय खूब चल रहा है. फजल ने रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हुए मुम्बई के खिलाफ 127 और 28 रन की पारी खेलकर खूब वाहवाही लूटी थी. फजल आईपीएल में भी जौहर दिखा चुके हैं. वह 2009-2011 तक आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स की टीम के अहम सदस्य थे. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 11 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं लिस्ट-ए कॅरियर में भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ है. फजल इस समय इंग्लैंड में नॉर्थ इस्टर्न प्रीमियर लीग खेल रहे हैं. वहां भी उनका बल्ला रनों की बारिश कर रहा है. वह दो शतक लगा चुके हैं.

टीम इंडिया में शामिल यजुवेन्द्र चहल इस समय चर्चा में हैं. उनकी चालाक गेंदबाजी विश्व के धाकड़ बल्लेबाजों को चकमा देने में सफल रही है. राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक दिखाने वाले यजुवेन्द्र चहल केवल 20 प्रथम श्रेणी मैचों का अनुभव रखते हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी घूमती हुई गेंदों ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है. बहुत कम लोग जानते हैं कि यजुवेन्द्र चहल कभी चेस के खिलाड़ी हुआ करते थे. 64 खानों के खेल में भी चहल अव्वल रह चुकेहैं, लेकिन अब वह 22 गज की पिच पर जौहर दिखा रहे हैं. यजुवेन्द्र चहल चेस खेलने के दौरान एशियन और वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. भारतीय टीम में इस बार जयंत यादव को भी मौका मिला है. जयंत यादव बेहद प्रतिभावान ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं. साल 2011 में हरियाणा रणजी टीम से अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी. जयंत ने 2014-15 के सत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 33 विकेट लेकर चयनकर्ताओं की नजरों में आए. पिछले रणजी सत्र में गजब का प्रदर्शन करते हुए 21 विकेट झटके थे, जबकि कर्नाटक के खिलाफ जोरदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा था. इनके आलावा पंजाब के जलन्धर के रहने वाले मनदीप सिंह को भी टीम इंडिया से खेलने का मौका मिला है. वह पंजाब के तीसरे क्रिकेटर हैं जो टीम इंडिया में शामिल किये गये हैं. उन्होंने 57 प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 3699 रन बनाया है. ऐसे में भारत के लिए खेलना उनके लिए खास चुनौती होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रियंका या दीपिका कौन किस पर भारी?

बॉलीवुड में वैसे भी दमदार हीरोइनों की कमी है. जहां दीपिका *ट्रीपल एक्स: द जेंडर केज* में व्यस्त हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा *बेवॉच* की शूटिंग कर रही हैं.

बॉलीवुड का नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां की टॉप हीरोइन दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा का सारा ध्यान हॉलीवुड फिल्मों में लगा हुआ है. बॉलीवुड में वैसे भी दमदार हीरोइनों की कमी है. जहां दीपिका *ट्रीपल एक्स: द जेंडर केज* में व्यस्त हैं वहीं प्रियंका चोपड़ा *बेवॉच* की शूटिंग कर रही हैं. वैसे प्रियंका चोपड़ा ने *क्वांटिको* सीरियल से काफी सुर्खियां बटोरी है. जिसके लिए उनको पीयोपल्स च्वाइस अवार्ड से नवाज़ा भी गया है. प्रियंका और दीपिका हॉलीवुड में जिस प्रकार अपना मुकाम तेजी से बनाती नज़र आ रही हैं, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दोनों अभिनेत्री हॉलीवुड में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती नज़र आएंगी. अब यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस रेस में आगे निकलता है?

ख़बर है कि दीपिका और प्रियंका में से किसी एक को जेम्स बॉण्ड गर्ल बनने का अवसर मिल सकता है. दोनों इस दिशा में कोशिश कर रही हैं. हालांकि जेम्स बॉण्ड की अगली फिल्म जल्दी शुरू होने की संभावना कम है, क्योंकि *स्पेक्टर* कुछ समय पहले ही प्रदर्शित हुई थी.

अनुमान यह लगाया जा रहा है कि भारत में हॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है लिहाज़ा हॉलीवुड वाले अब भारतीय कलाकारों को अपनी फिल्मों में अवसर देने लगे हैं. संभव है कि इस बार बॉण्ड गर्ल के रूप में भारतीय लड़की देखने को मिले.■

जॉन अब्राहम के लिए परीक्षा की घड़ी

जुलाई में रोहित धवन के निर्देशन में जॉन अब्राहम की दिशूम प्रदर्शित होने जा रही है. इसमें वह एक महत्वपूर्ण किरदार में वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस के साथ नज़र आएंगे. जॉन की एक और फिल्म *फिर हेराफेरी–3*, अगस्त में रिलीज़ हो रही है. 2000 में प्रदर्शित फिरोज नाडियाडवाला की हेराफेरी का सीक्वल *फिर हेराफेरी* 2006 में आई थी.

फिर हेराफेरी–3 उसका तीसरा पार्ट है. जॉन के लिए यह फिल्म काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन्हें अक्षय कुमार की जगह रिप्लेस किया गया था. वेलकम बैक के बाद *फिर हेराफेरी–3* ऐसी दूसरी फिल्म है जो जॉन अब्राहम को अक्षय की जगह मिली है. 2 सितंबर को नीरज पांडे द्वारा निर्देशित *एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी* प्रदर्शित होगी. इसमें भी जॉन का महत्वपूर्ण किरदार है. इसके अलावा जॉन की फोर्स–2 भी 18 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. जॉन द्वारा निर्मित रॉकी *हैंडसम* ज्यादा नहीं चल सकी. कुल मिलाकर जॉन अब्राहम के लिए *वज़ीर* और *रॉकी हैंडसम* के पिट जाने के बाद यह परीक्षा की घड़ी है. बतौर एक्टर हो या प्रोड्यूसर, हर हाल में उन्हें खुद को साबित करना होगा, वर्ना बाज़ी बिगड़ते देर नहीं लगेगी.■

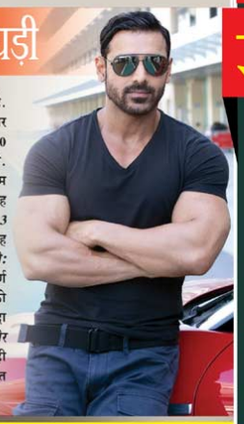

श्रद्धा की सफलता से घबराई आलिया

निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने अपनी फिल्म बागी की सफलता का जश्न मनाया. इस फिल्म में उनके चहेते सितारे टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर ने काम किया है. इसमें टाइगर और श्रद्धा के कई करीबी दोस्त पहुंचे, लेकिन श्रद्धा की दोस्त आलिया भट्ट इस पार्टी में नहीं पहुंची. आलिया के इस पार्टी में न पहुंचने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

इनमें से एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आलिया, श्रद्धा की सक्सेस से असुरक्षित महसूस करने लगी हैं. बॉलीवुड में श्रद्धा बड़ी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं. श्रद्धा की हालिया रिलीज़ बागी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. फिल्म में श्रद्धा की एक्टिंग और एक्शन सीन की भी काफी तारीफ हो रही है. पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धा की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है जिसमें आशिकी–2, एबीसीडी–2 और हैदर शामिल हैं. श्रद्धा की यह सफलता आलिया को डरा रही है.

वैसे भी आलिया की पिछली प्रदर्शित फिल्मों (शानदार और कपूर एंड संस) ने बॉक्स ऑफिस पर कोई तीर नहीं मारा है. फिल्म शानदार जहां पलाप साबित हुई, तो वहीं कपूर एंड सन्स ने लगभग 73 करोड़ कमाई कर औसत साबित हुई. लेकिन इस फिल्म की सफलता का श्रेय आलिया को नहीं बल्कि इसके निर्देशक शकुन बत्रा और फवाद खान को मिला. आलिया इस बात को भूल गई हैं कि उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उनमें से सिर्फ एक हाइवे ही ऐसी फिल्म है जिसका निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया, बाकी सभी फिल्में करण जौहर की हैं, जिनको अगर सफलता भी मिलती है तो वह करण जौहर की फिल्म कहलायी जाती है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रंग-रूप को लेकर मेरा मज़ाक उड़ाया जाता था परिणीति चोपड़ा

हालांकि वजन घटाने को लेकर परिणीति चोपड़ा को सोशल मीडिया पर कई लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परिणीति का कहना है कि उन्हें अन्य महिलाओं के लिए प्रेरक बनने पर खुशी है. परिणीति ने जब *लेडीज वर्सेज रिकी बहल* से बॉलीवुड में प्रवेश किया था, तब उनका वजन थोड़ा ज्यादा था.

परिणीति ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करने के साथ लिखा कि महिलाओं ने मुझसे कहा है कि मैंने उनकी जिंदगी बदल दी है. वह प्रसव के बाद बढ़ा वजन, किशोरावस्था के मोटापे जैसी समस्याओं से लड़ रही हैं और मैं उनकी प्रेरणा हूं. एक कलाकार के तौर पर मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है. परिणीति ने आगे लिखा कि अगर मैं यह कर सकती हूं, तो आप भी कर सकते हैं. मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं. ढेर सारा प्यार.

परिणीति ने कहा कि पहले उन्होंने अपने रंग–रूप और लुक को लेकर काफी मेहनत किया है. मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मैं इन बातों को हंसी में उड़ा देती थी. आज लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बॉलीवुड के दबाव में आकर मैंने अपना वजन घटाया है. इस पर मैं कहती हूं कि भगवान का शुक्र है कि मैं अभिनेत्री बनी और मुझ पर यह दबाव बना और मैं वह हासिल कर पाई, जो मैं नहीं कर पाती.■

> मैंने अपने रंग-रूप और लुक को लेकर काफी मेहनत किया है. मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मैं इन बातों को हंसी में उड़ा देती थी.

श्रद्धांजलि

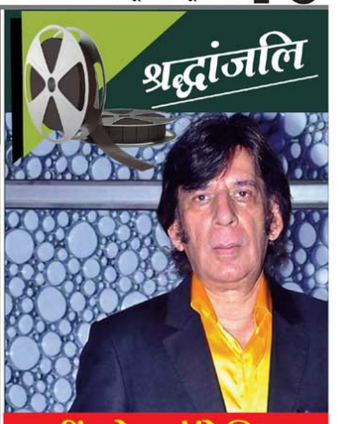

नहीं रहे कॉमेडियन रज़्ज़ाक़ खान

बॉलीवुड में गोल्डन भाई के नाम से थे मशहूर

फिल्म *अंखियों से गोली मारे* के एक दृश्य में क़ादर खान व असरानी के साथ रज़्ज़ाक़ खान

कॉमेडियन रज्जाक खान नहीं रहे. गोल्डन भाई के नाम से चर्चित रज्जाक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. रज्जाक को 31 मई मंगलवार को हार्टअटैक आया था. उनके दोस्त एक्टर शहज़ाद खान ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, कार्डियक अरेस्ट के चलते मैंने अपने बड़े रज्जाक भाई को खो दिया है. उनके लिए प्रार्थना करें.

रज्जाक खान ने सलमान, गोविंदा और शाहरुख खान के साथ कई कॉमेडी फिल्में की थीं. आखिरी बार उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में देखा गया था.

फिल्म *इश्क़* में नवाब की भूमिका में रज्जाक खान

फिल्म *बड़े मियां छोटे मियां* में अमिताभ बच्चन व गोविंदा के साथ रज्जाक खान

बांद्रा के हॉस्पिटल में ली आख़िरी सांस

रज्जाक के परिवार वालों ने बताया कि बांद्रा, मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली. 31 मई मंगलवार को उन्हें हार्ट अटैक आया था. इसके बाद से वे हॉस्पिटल में थे. जहां उनका निधन हो गया.

बॉलीवुड में ख़ास थी रज़्ज़ाक़ की जगह

रज्जाक का नाम बॉलीवुड के फेमस कॉमेडियंस में गिना जाता है. उन्होंने शाहरुख खान स्टारर बादशाह (किरदार : माणिकचंद) सलमान खान स्टारर हैलो ब्रदर (किरदार : निंजा चाचा) और गोविंदा स्टारर अंखियों से गोली मारे (किरदार : टक्कर पहलवान), राजा हिंदुस्तानी, मोहरा, प्यार किया तो डरना क्या, हसीना मान जाएगी, हर दिल जो प्यार करेगा, होगया दिमाग़ का दही, हंगामा और हेरा–फेरी सहित कई सुपरहिट फिल्मों में नज़र आ चुके हैं.

रज्जाक 1999 में आई फिल्म बादशाह में अपने रोल मानिकचंद से सुर्खियों में आए थे. रज्जाक खान ने 1993 में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म दर्शकों ने काफी पसंद की थी जिसमें श्रीदेवी और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे.■

फिल्म *होगया दिमाग़ का दही* में तिली भाई की जानदार भूमिका में रज्जाक खान

कॉमेडी नाइट विथ कपिल के दौरान रज्जाक खान